THE LARGEST CIRCULATED AND READ HINDI DAILY IN TELANGANA & ANDHRA PRADESH

स्वतंत्र वार्ता

epaper.vaartha.com
Vaartha Hindi
@Vaartha_Hindi
Vaartha official
www.hindi.vaartha.com

वर्ष-31 अंक : 113 (हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टणम, तिरुपति से प्रकाशित) आषाढ शु.10 2083 शुक्रवार, 24 जुलाई-2026

प्रधान संपादक - डॉ. गिरीश कुमार संघी हैदराबाद ☼ पृष्ठ : 16 मूल्य : 8 रुपये

अभिषेक बनर्जी को फिलहाल समग्र अंतरिम राहत नहीं

कोलकाता, 23 जुलाई (एजेंसियां)। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ दर्ज आठ एफआईआर के मामले में फिलहाल समग्र अंतरिम संरक्षण नहीं मिलेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि अलग-अलग आरोपों के आधार पर दर्ज सभी मामलों को एक साथ जोड़कर व्यापक अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। >14

फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे : पीएम मोदी

युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का यह ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया है। सीजेपी पिछले 34 दिन से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं उनका इलाज चल रहा है।

पीएम-युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी, इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे। अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है, ताकि फैसला तेजी से हो सके। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरूआत साल 2000 में हुई थी। इनका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग ने देशभर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार, रेप और पॉक्सो मामलों के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 तक 3.06 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। इन अदालतों में मामलों के निपटारे का रेट 96.28 प्रतिशत है, यानी जितने नए मामले आए, लगभग उतने ही मामलों का निपटारा भी हुआ। हालांकि, नए मामले लगातार दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक 2.45 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग थे, जबकि 2024 के अंत में यह संख्या 2.04 लाख थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि नीट पेपर लीक की खबर मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए दोबारा परीक्षा कराई गई और समय पर परिणाम भी घोषित किए गए।

प्रदर्शनकारी छात्रों के पक्ष में अन्ना हजारे ने रखा दो घंटे मौन

मुंबई, 23 जुलाई (एजेंसियां)। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरुवार को दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों के पक्ष में दो घंटे का मौन रखा। अन्ना हजारे के सहयोगी दत्ता अवारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक मौन रखा। इसके बाद अन्ना हजारे अपने गांव रालेगण सिद्धि के लिए रवाना हो गए। इससे पहले बुधवार को अन्ना हजारे ने पीएम को पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली में विद्यार्थियों के मौजूदा प्रदर्शन के दौरान हिंसा एवं पुलिस कार्रवाई 'बहुत दुखद' है तथा लोकतंत्र में संवाद हमेशा टकराव से बेहतर होता है। अन्ना हजारे ने पत्र में यह भी कहा कि किसी मंत्री का इस्तीफा लेने से सरकार कमजोर नहीं होगी, बल्कि इससे दूसरे मंत्रियों को जवाबदेही के बारे में एक मज़बूत संदेश जाएगा और शासन में सुधार आयेगा।

राहुल बोले-पीएम एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी के जिम्मेदार

छात्रों की मांगें-प्रधान को हटाएं, स्टूडेंट्स से हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लें

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। देश भर में नीट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया किस पेपर लीक मामलों के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे 'शिक्षा तंत्र की तबाही' छिपाने की कोशिश करार दिया।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में आरोप लगाया कि देश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद करने और युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज पर करीब 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाए। राहुल कहा कि नीट पेपर लीक से देश के 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स और उनके परिवार प्रभावित हुए। नीट मामले में किसी भी को सजा नहीं हुई। महिलाओं के साथ बर्बरता : महिलाओं के साथ पुलिस बदसलूकी करते दिख रही है। डीसीपी संदीप लांबा पर लड़की को थप्पड़ मारने के आरोप लग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। >14

दिल्ली में फिर लागू हुआ एनएसए : पुलिस कमिश्नर को मिला हिरासत का अधिकार, पुलिस बोली-सीजेपी विरोध प्रदर्शन नहीं वजह

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लेने का अधिकार फिर से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह अधिकार 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि यह फैसला जंतर-मंतर पर चल रहे सीजेपी छात्र आंदोलन को देखते हुए लिया गया है।

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस दावे को गलत बताया है। पुलिस का कहना है कि यह हर तीन महीने में होने वाली सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। मौजूदा आदेश भी 7 जुलाई 2026 को ही जारी कर दिया गया था, यानी सीजेपी आंदोलन के तेज होने से पहले ही। इसलिए इसका मौजूदा प्रदर्शन से कोई सीधा संबंध नहीं है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पुलिस कमिश्नर को एनएसए के तहत अधिकार देने का आदेश नया नहीं है। यह हर तीन महीने में नियमित रूप से बढ़ाया जाता है। मौजूदा आदेश भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक के लिए लागू किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि यह फैसला सीजेपी के प्रदर्शन को रोकने के लिए लिया गया है। इस पर दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि ऐसी खबरें सही नहीं हैं और इस बार भी केवल नियमित रूप से रिन्यू किया गया है। सीजेपी का जंतर-मंतर प्रदर्शन 20 जून से परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ था। बाद में इस आंदोलन में कई छात्र संगठन जुड़े और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठने लगी।

समय और तारीख तय करे विपक्ष : पेपर लीक पर चर्चा के लिए सरकार तैयार : रिजिजू

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। मानसून सत्र के चौथे दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नीट पेपर लीक मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गए। गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल शुरू होने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने फिर से अपील की कि विपक्ष समय और तारीख तय करे, सरकार पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है।

हालांकि, लगातार नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमने कल अपील की थी। मैं आज आपके (पीठासीन) जरिए सदन से फिर अपील करना चाहता हूं। हमने कांग्रेस पार्टी के नेताओं और दूसरे विपक्षी सदस्यों से भी व्यक्तिगत स्तर पर बात की है। हमने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने और अपने सुझाव शेयर करने के लिए बुलाया है। हमने लोकसभा स्पीकर से भी बात की है कि सरकार इस सदन और राज्यसभा में नीट पेपर लीक पर विपक्ष जिस भी तरह चाहे, जिस भी तारीख को चाहे और जितने समय के लिए चाहे, चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने यह भरोसा दिया है। रिजिजू ने कहा कि गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने संदेश दिया कि नीट पेपर लीक मामलों को दोषियों को सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष शर्तें सामने रखकर बहाना बना रहा है। उन्होंने कहा, अगर आप (विपक्ष) बहाने बनाएंगे, तो स्पष्ट है कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। >14

नड्डा ने कॉजपा को वार्ता के लिए बुलाया प्रदर्शनकारियों ने ठुकराया प्रस्ताव

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसके नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह सरकार से केवल किसी तटस्थ स्थान पर ही बातचीत करेगी।

एक सूत्र ने कहा, जेपी नड्डा की ओर से आज बातचीत के लिए कॉजपा को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन प्रदर्शन स्थल के मंच पर मौजूद नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र 'लीक' मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले महीने से जंतर-मंतर पर धरना दे रही कॉजपा के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पुलिस ने उन्हें बृहस्पतिवार सुबह बताया कि नड्डा ने उन्हें अपने आवास पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।

मेट्रो स्टेशन बंद होने पर सीजेआई बोले-दोपहर तक समाधान नहीं हुआ तो करेंगे हस्तक्षेप

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। छात्रों के प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने का मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने आग्रह किया की कि कम से कम उन वकीलों, पक्षकारों और अदालत के कर्मचारियों को स्टेशन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, जिनके पास सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश का वैध पास है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने मुद्दा उठाते हुए विकास सिंह ने कहा कि जिन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के वैध पास हैं और रजिस्ट्री के कर्मचारी हैं, उन्हें उचित सुरक्षा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति दी जानी चाहिए। विकास सिंह ने कहा, मेट्रो में एक फायदा है कि जब वे ट्रेन से बाहर आते हैं तो वहां एक निकास बिंदु होता है। वहां उनकी जांच की जा सकती है। जिन लोगों के पास प्रॉक्सिमिटी कार्ड हैं और रजिस्ट्री के कर्मचारी हैं, उन्हें बाहर आने की अनुमति दी जा सकती है और बाकी लोगों से कहा जा सकता है कि वे दूसरी ट्रेन लें और चले जाएं।

इससे लोग ट्रेन का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को पहले ही इस मामले को मेट्रो अधिकारियों के सामने उठाने के लिए कहा गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भरोसा दिलाया कि अगर यह मुद्दा नहीं सुलझता है तो वह खुद हस्तक्षेप करेंगे।

सीजेआई सूर्य कांत ने कहा, मैंने उन्हें सुबह ही इसकी जानकारी दे दी है। अब यह उनके ऊपर है कि वे अधिकारियों से बात करें। वह इसे समाधान के एक विकल्प के रूप में भी देख रहे हैं। दोपहर के भोजन तक अगर कोई समाधान निकलता है तो ठीक है। >14

'हमेशा देर कर देता हूं मैं'

पीएम की 'फास्ट-ट्रैक कोर्ट' की घोषणा पर शशि थरूर का तंज

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। नीट परीक्षा पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठन की घोषणा की है, उसपर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शायरी के माध्यम से तंज कसा है। जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के बार-बार हिंसक होने के बाद पीएम मोदी ने यह कदम उठाया है।

केरल के तिरूवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर कई बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डटकर मोदी सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में खड़े दिखे हैं। लेकिन, नीट पेपर लीक को लेकर उन्होंने मोदी सरकार और खासकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। अब उन्होंने पीएम मोदी के एक्स पोस्ट पर पाकिस्तानी शायर मुनीर नियाजी का शेर लिखकर उनपर कटाक्ष किया है।

> भारत का पाकिस्तान को साफ संदेश

जब तक सीमा पार से आतंक खत्म नहीं होता

सिंधु संधि पर रोक जारी रहेगी

संयुक्त राष्ट्र, 23 जुलाई (एजेंसियां)। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक इस्लामाबाद सीमा पार आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के रूप में अपनाए रखेगा, तब तक सिंधु जल संधि निलंबित रहेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कहा, सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और लगातार एक जैसा रहा है।

उन्होंने कहा, जब सीमा पार आतंकवाद को नियमित रूप से राज्य की नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तब आपसी विश्वास और सद्भावना के आधार पर सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 'प्राकृतिक संसाधनों का शासन: शांति, सुरक्षा और समृद्धि की नींव' विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय खुली बहस के दौरान पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने सिंधु जल संधि और जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस पर भारतीय प्रतिनिधि पी. हरीश ने करारा जवाब दिया।

पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि उसका पूर्वी पड़ोसी भारत सिंधु जल संधि को एकतरफा और अवैध रूप से स्थगित कर रहा है और यह कदम जम्मू-कश्मीर विवाद की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। दरअसल, अप्रैल में 2025 पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में धर्म से प्रेरित हमले किए। इस हमले में 24 लोगों की निर्मम तरीके से धर्म पूछ-पूछकर हत्या की गई। इसके बाद भारत ने नदी के पानी के बंटवारे के लिए 1960 की सिंधु जल संधि को रोक दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद संधि को रोकने और पाकिस्तान के साथ व्यापार रोकने का कारण बताते हुए कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा रहा है, वर्तमान में है और रहेगा।

उन्होंने कहा, यह संवैधानिक और कानूनी सच्चाई है जिसे पाकिस्तान जानबूझकर नजरअंदाज करना चाहता है। जम्मू और कश्मीर के संबंध में एकमात्र लंबित मुद्दा पाकिस्तान द्वारा भारत के संप्रभु क्षेत्र पर खुला हमला और अवैध कब्जा है। सुरक्षा परिषद ने 21 अप्रैल, 1948 को पास किए गए अपने प्रस्ताव में मांग की थी कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर से अपने सैनिकों और नागरिकों को वापस बुलाए, वहां घुसपैठ रोके और राज्य में लड़ रहे लोगों की मदद न करे।

बता दें, पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाके में कश्मीरियों के विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से दबा रहा है और जून से अब तक उसके सुरक्षा बलों ने 30 से ज्यादा लोगों को मार डाला है। हाल ही में, 14 जुलाई को तरारखाल में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने छह कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया। भारतीय प्रतिनिधि हरीश ने कहा, भारत पर उंगली उठाने के बजाय, पाकिस्तान को अपना घर ठीक करके अपनी और अपने लोगों की बेहतर सेवा करनी चाहिए।

ईरान युद्ध की भारी कीमत चुका रहा अमेरिका

> अब तक 3.2 लाख करोड़ खर्च, रक्षा मंत्री ने अब मांगे 70 अरब डॉलर

पेंटागन, 23 जुलाई (एजेंसियां)। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल के सैन्य अभियान पर अब तक 37.5 अरब डॉलर (करीब 3.2 लाख करोड़ रुपये) का खर्च हो चुका है। मंगलवार को अमेरिकी सीनेट की विनियोग समिति की बैठक में पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट की मांग रखी। इस बजट में ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए करीब 70 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि भी शामिल है।

सीनेट में क्या बोले हेगसेथ :

हेगसेथ ने कहा कि युद्ध के लिए अतिरिक्त धन की तुरंत जरूरत है और यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट का अहम हिस्सा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह राशि मंजूर नहीं हुई तो रक्षा विभाग को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सुनवाई के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों ने हेगसेथ के शुरूआती संबोधन में बाधा भी डाली। यह सुनवाई ऐसे समय हुई जब कुछ दिन पहले ही पेंटागन ने बताया था कि ईरान से जुड़े संघर्ष में तीन और अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। इसके साथ ही

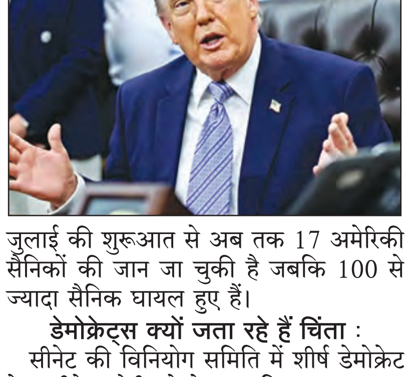

जुलाई की शुरूआत से अब तक 17 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है जबकि 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं।

डेमोक्रेट्स क्यों जता रहे हैं चिंता :

सीनेट की विनियोग समिति में शीर्ष डेमोक्रेट नेता सीनेटर पैटी मरे ने कहा कि यह युद्ध एक बार फिर नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि समझौता जल्द होने वाला है और युद्ध समाप्त होने वाला है। इसके बावजूद अब सरकार ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए 70 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि मांग रही है।

वहीं सीनेटर जीन शाहीन ने सवाल उठाया कि जब पिछले साल कांग्रेस द्वारा रक्षा विभाग को दिए गए 150 अरब डॉलर में से करीब आधी राशि अभी तक खर्च ही नहीं हुई है तो फिर अतिरिक्त धन की जरूरत क्यों पड़ रही है। इस पर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जवाब दिया कि बची हुई राशि का इस्तेमाल सितंबर तक कर लिया जाएगा। इसलिए युद्ध और रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है।

सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ :

सीनेट की सुनवाई कई बार तीखी बहस में बदल गई। अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल डैन केन ने कहा कि फिलहाल यह बताना संभव नहीं है कि ईरान के साथ युद्ध की कुल लागत कितनी होगी। युद्ध का नतीजा केवल अमेरिका नहीं बल्कि विरोधी पक्ष की रणनीति पर भी निर्भर करता है।सुनवाई के दौरान सांसदों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ईरान होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना शुरू कर सकता है। यह समुद्री मार्ग लंबे समय से दुनिया में तेल आपूर्ति का प्रमुख रास्ता रहा है। हालांकि अधिकारियों ने इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बाद में डेमोक्रेट सांसद गैरी पीटर्स ने कहा कि सरकार की युद्ध रणनीति विफल रही है। इस पर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीटर्स 'चुनावी प्रचार' कर रहे हैं।

श्रीनिवासन हत्याकांड : एनआईए ने आरोपी मुहम्मद अली को एयरपोर्ट पर दबोचा

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल के श्रीनिवासन हत्याकांड में एक और फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह मामला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआई) से जुड़ा है।

एनआईए ने पीएफआई के पलक्कड़ जिला अध्यक्ष मुहम्मद अली केपी को गुरुवार सुबह नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया।

वह सऊदी अरब के रियाद से लौट रहा था। वह पिछले चार साल से रियाद में छिपा हुआ था। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए कुल आरोपियों की संख्या अब 67 हो गई है। एनआईए के मुताबिक, केस आरसी-02/2022/ एनआईए /केओसी में अब तक जिन 65 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें मुहम्मद अली केपी भी शामिल है।

गड़बड़ गोला-बारूद से 62 करोड़ का नुकसान

> धनुष प्रोजेक्ट पर भी पीएसी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। संसद की पीएसी ने एक बार फिर रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई है। पीएसी की 49वीं रिपोर्ट (18वीं लोकसभा, 2026-27) में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल द्वारा सेना को दिए गए गड़बड़ गोला-बारूद की जगह नए माल सप्लाई करने पर 62.10 करोड़ रुपये का नुकसान उजागर किया गया है। समिति ने आर्टिलरी गन्स की खरीद में दशकों की देरी को भी सेना की ऑपरेशनल तैयारी के लिए बड़ा खतरा बताया है।

धनुष तोप जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट की उत्पादन समस्याओं पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। पीएसी ने पांच प्रमुख सिफारिशें की हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, स्किल डेवलपमेंट, बेहतर निर्णय प्रक्रिया और समयबद्ध उत्पादन शामिल हैं। यह रिपोर्ट आत्मनिर्भर भारत के रक्षा लक्ष्यों को हासिल करने में आने वाली असल चुनौतियों को सामने लाती है। पीएसी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल द्वारा सप्लाई किए गए गड़बड़ को बदलने पर हुए 62.10 करोड़ रुपये के नुकसान को गंभीर बताया। ऐसी खामियां न सिर्फ पैसे की बर्बादी हैं बल्कि सेना के गोला-बारूद स्टॉक की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती हैं।

समिति ने रक्षा मंत्रालय से मांग की है कि सप्लाई चेन को सख्त एसओपी और समयसीमा के साथ मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं।

20 साल की आर्टिलरी खरीद देरी, सेना पुरानी तोपों के सहारे :

1986 में बोफोर्स से 155एमएम/39 कैलिबर तोपें खरीदी गई थीं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ था। 1989 के बैन के बाद नई ऊंची कैलिबर वाली तोपें खरीदने की कोशिश 1990 के दशक में हुई लेकिन जरूरतों का फैसला न हो पाने और विक्रेताओं के कम रिस्पॉन्स से प्रक्रिया रुक गई। पीएसी के अनुसार मंत्रालय को नई तोप प्रणाली खरीदने और शामिल करने में दो दशक लग गए। >14

पीएम मोदी के नीट लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया

जयराम रमेश बोले- 'दबाव का असर'

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें संसद में खड़े होकर गंभीर बहस करने का साहस नहीं है। उन्होंने दावा किया कि देशभर के छात्रों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की ओर से किया गया सोशल मीडिया पोस्ट इस बात का संकेत है कि सरकार दबाव में है। जयराम रमेश ने कहा कि यह पोस्ट सरकार की चिंता नहीं, बल्कि उसकी बेचैनी को दिखाती है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में संसद में खड़े होकर बोलने और गंभीर बहस में हिस्सा लेने का साहस नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब भी देश में ऐसे महत्वपूर्ण मौके आए, तब उनसे पहले के सभी प्रधानमंत्रियों ने संसद में आकर चर्चा की और सवालों का जवाब दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें देशभर के छात्रों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों की चिंता है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि यह पोस्ट बताती है कि प्रधानमंत्री दबाव में हैं और सरकार छात्रों के आंदोलन से घबराई हुई है।

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी और परीक्षा पत्र लीक जैसे मामलों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। जयराम रमेश का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के युवाओं का कल्याण और उनका हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

मातम में बदली शादी की खुशियां तालाब में गिरी बारातियों की कार 5 लोगों की मौत, 2 बचाए गए

ढेंकानाल, 23 जुलाई (एजेंसियां)। ओडिशा के ढेंकानाल जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया। बारातियों से भरी एक महिंद्रा एक्सयूवी कार अनियंत्रित होकर एक तालाब में जा गिरी। हादसे में पांच बारातियों की डूबने से मौत हो गई, जबकि दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक, बांगुरसिंह गांव निवासी अभिषेक साहू की शादी ढेंकानाल सदर थाना क्षेत्र के इंदुपुर गांव निवासी रोहित कुमार पृष्टि की बेटी के साथ तय हुई थी। शादी में शामिल होने के लिए बांगुरसिंह गांव से कई वाहनों में बाराती इंदुपुर जा रहे थे। इसी दौरान बारातियों से भरी एक कार रात के अंधेरे में रास्ते में अनियंत्रित हो गई और सीधे एक बांध के पानी में जा गिरी।

अनंतनाग में सुरक्षाबलों का एक्शन

लश्कर के दो आतंकियों के मकान ध्वस्त

जम्मू, 23 जुलाई (एजेंसियां)। कश्मीर जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी की आतंकी हमले में वीरगति के एक दिन बाद प्रशासन और सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों के मकानों को ध्वस्त कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने जीएनएस को बताया कि अनंतनाग के गुरी निवासी और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी आदिल अहमद थोकर के नए मकान को गुरुवार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। वहीं, गुरुवार की दरमियानी एक अन्य कार्रवाई में बिजबेहाड़ा के हसनपोरा तवेला निवासी अब्दुल रशीद गनई के बेटे हारून रशीद गनई के एक मंजिला रिहायशी मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया।

हारून वर्ष 2018 से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा सक्रिय आतंकी बताया गया है। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस, एक राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और सीआरपीएफ की 90वीं बटालियन ने संयुक्त रूप से की। गौरतलब है कि बुधवार को हुए आतंकी हमले में जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान आशिक हुसैन कुरैशी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद सुरक्षाबलों ने यह कार्रवाई की।

आंध्र प्रदेश सरकार जी .ओ नम्वर. 3 को फिर से लागू करने के लिए प्रतिबद्धः मंत्री गुमिमिडी संध्या रानी

अमरावती, 23 जुलाई (एजेंसियां)। गठबंधन सरकार ने आदिवासी समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों को मजबूत करते हुए, कानूनी रूप से टिकाऊ ढांचे के माध्यम से जी .ओ नम्वर. 3 को फिर से लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री एन। चंद्रबाबू नायडू के निर्देशों पर अमल करते हुए, आदिवासी कल्याण मंत्री गुमिमिडी संध्या रानी ने विजयवाड़ा में आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय में आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। यह बैठक आदिवासी कल्याण से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें जी .ओ नम्वर. 3 को फिर से लागू करना, 1/70 भूमि हस्तांतरण विनियमन को लागू करना, आदिवासी भूमि अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल था।

संध्या रानी ने कहा कि गठबंधन सरकार जी .ओ नम्वर. 3 को फिर से लागू करने और आदिवासी लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न तो गठबंधन सरकार और न ही मुख्यमंत्री ने कभी जी .ओ नम्वर. 3 का विरोध किया था और सरकार का उद्देश्य एक कानूनी रूप से मजबूत तंत्र पेश करना था जो आदिवासी रोजगार अधिकारों को स्थायी सुरक्षा प्रदान करेगा।

मंत्री ने वाईएसआरसीपी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जी .ओ नम्वर. 3 का बचाव करने में उसकी विफलता के कारण इसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि आदिवासी मतदाताओं द्वारा सात विधायक और एक सांसद चुनने के बावजूद, वाईएसआरसीपी सरकार ने कोई याचिका तक दायर नहीं की, जिससे वह आदिवासियों के हितों की रक्षा करने में विफल रही। संध्या रानी ने कहा कि रद्द किए गए सरकारी आदेश को उसके मूल रूप में फिर से जारी करना न्यायिक जांच में टिक नहीं पाएगा। इसके बजाय, सरकार आदिवासी समुदायों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संशोधनों के साथ एक कानूनी रूप से मजबूत ढांचा तैयार कर रही थी। इसके हिस्से के रूप में, सभी नौ एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी (आईटीडीए) क्षेत्रों में आदिवासी संगठनों, संयुक्त कार्य समितियों (जेएसी), जन प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया गया था।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का आदेशः फ़र्ज़ी पट्टों पर चार हफ़्ते में कार्रवाई करें

अमरावती, 23 जुलाई (एजेंसियां)। हाई कोर्ट ने रेवेन्यू और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विभागों के सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे चार हफ़्ते के अंदर उन कथित फ़र्ज़ी हाउस पट्टों को रद्द करने के लिए कदम उठाएं, जिन्हें वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान पूर्व मंत्री और वाईएसआरसीपी नेता पेर्नी नानी और उनके बेटे किट्टू ने मछलीपट्टनम म्युनिसिपल इलाके में बांटा था। कोर्ट ने अधिकारियों को एक हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश दिया, जिसमें उन अधिकारियों के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई का ब्योरा हो जिन्होंने कथित तौर पर इन पट्टों को जारी करने में मदद की थी। चीफ़ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस चल्ला गुना रंजन की डिवीज़न बेंच ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।

यह पीआईएल पिछले साल टीडीपी नेता आई। दिलीप कुमार ने दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि चुनावों से पहले मछलीपट्टनम म्युनिसिपैलिटी के सर्वे नंबरों में सड़क के किनारे की ज़मीन, कब्रिस्तान और ड्रेनेज (नाली) की ज़मीन के लिए फ़र्ज़ी हाउस पट्टे बांटे गए थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि गड़बड़ियों की पुष्टि होने के बावजूद, अधिकारी ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में नाकाम रहे।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पट्टे ज़मीन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करके जारी किए गए थे और उन्होंने इन्हें तुरंत रद्द करने की मांग की। पेर्नी नानी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील वाई। नागी रेड्डी ने तर्क दिया कि यह पीआईएल राजनीतिक मकसद से प्रेरित है और याचिकाकर्ता ने अपनी राजनीतिक संबद्धता और लंबित आपराधिक मामलों जैसी अहम जानकारियों को छिपाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर जानकारी छिपाने की बात साबित होती है तो वह जुर्माना लगा सकता है और मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

नीट प्रोटेस्ट पर देवेंद्र फडणवीस की बेटी की अपील

प्रदर्शनकारी शिक्षा सुधार का करें समर्थन, राजनीति का नहीं

मुंबई, 23 जुलाई (एजेंसियां)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बेटी दिविजा फडणवीस ने नीट और शिक्षा सुधारों को लेकर देशभर में चल रहे प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करने, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल या उसकी विचारधारा का बिना सोचे-समझे समर्थन न करने की अपील की। दिविजा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि उनसे कई बार इन प्रदर्शनों पर अपनी राय देने के लिए कहा गया। ऐसे में उन्होंने कहा, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर हिंसा और पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हिंसा, दोनों की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने लिखा कि लोग शिक्षा सुधारों की मांग का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन जिस राजनीतिक दल या विचारधारा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, उसका आंख मूंदकर समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन का समर्थन करने से पहले उसके वास्तविक उद्देश्य को समझना जरूरी है। दिविजा फडणवीस ने लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक मजबूत विपक्ष का उद्देश्य देश के हित में काम करना होना चाहिए। विपक्ष को सरकार को बेहतर फैसले लेने में मदद करनी चाहिए, न कि केवल सत्ता पक्ष को बदनाम कर उसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड्स को लेकर भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने लिखा कि सिर्फ इसलिए किसी आंदोलन का हिस्सा न बनें, क्योंकि वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।

किसी भी विचारधारा के प्रभाव में आए बिना सोच-समझकर फैसला लें। दिविजा ने कहा कि जब तक आंदोलन छात्रों के हित, शिक्षा सुधार, नीट, पेपर लीक और एनटीए से जुड़े मुद्दों तक सीमित रहता है, तब तक यह उचित है। लेकिन जैसे ही आंदोलन धर्म या इन मुद्दों से बाहर के विषयों की ओर मुड़ता है, उसके इरादे बदल जाते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहना चाहिए।

सोनम-मुस्कान से बेरहम है अर्चना!

पहले पति को छोड़कर की दूसरी शादी, 45 दिन बाद नए हसबैंड की हत्या, सोते समय लकड़ी के मुगदर से मारा

पन्ना, 23 जुलाई (एजेंसियां)। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। यहां शादी के महज 45 दिन बाद पत्नी ने अपने पूर्व पति के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी अर्चना और उसके पूर्व पति रामप्रताप को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया है। पन्ना पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी महिला अर्चना का अपने पहले पति रामप्रताप से विवाद चल रहा था। इसके बाद उसने मई 2025 में नन्नू सोनी से कोर्ट मैरिज की थी।

शादी के कुछ समय बाद ही अर्चना का व्यवहार बदलने लगा और वह नन्नू पर अपनी पूरी जमीन-जायदाद अपने बच्चों के नाम करने का दबाव बनाने लगी। जब नन्नू ने इसका विरोध किया तो अर्चना ने अपने पूर्व पति रामप्रताप के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली। दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस के मुताबिक, 10 जुलाई 2025 की रात रामप्रताप चोरी-छिपे नन्नू सोनी के घर पहुंचा। वहां दोनों आरोपियों ने मिलकर सो रहे नन्नू पर लकड़ी के भारी मुगदर से हमला कर दिया।

हमले में नन्नू की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी महिला और उसका पूर्व पति अपने बच्चों को साथ लेकर फरार हो गए। पुलिस के लिए इस अंधे कत्ल को सुलझाना आसान नहीं था, क्योंकि आरोपी रामप्रताप बेहद शातिर तरीके से फरारी काट रहा था।

आज के समय में जहां ज्यादातर अपराधी मोबाइल लोकेशन, ऑनलाइन पेमेंट और सोशल मीडिया गतिविधियों के जरिए पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं, वहीं रामप्रताप ने इन सभी माध्यमों से दूरी बना ली थी। उसने अपना मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। पुलिस से बचने के लिए वह सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने से भी बचता रहा और पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा। इस दौरान उसने कई बार अपना नाम और हुलिया बदला।

फरारी के दौरान दोनों आरोपी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अपना ठिकाना बदलते रहे। आरोपियों की तलाश के लिए पन्ना पुलिस ने तीन विशेष टीमें गठित कीं, जिन्होंने लगातार छह राज्यों में दबिश दी। आखिरकार रैपुरा थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम को आरोपियों के गुजरात के सूरत में होने की सूचना मिली। पुलिस ने योजना बनाकर कपोदरा इलाके में दबिश दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

माता-पिता के सामने 5 वर्ष की मासूम को उठा ले गया तेंदुआ गन्ने के खेत में मिली लाश

पुणे, 23 जुलाई (एजेंसियां)। महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिरूर तालुका के पिंपलसुटी गांव में हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। गन्ना काटने वाले मजदूर दंपति की 5 वर्षीय बेटी भाग्यश्री को तेंदुआ उस समय उठा ले गया, जब वह अपने माता-पिता के साथ घर के पास बने गोठे (पशुशाला) में सो रही थी। भाग्यश्री अपने माता-पिता के साथ गोठे में सो रही थी। इसी दौरान तेंदुआ वहां पहुंचा और बच्ची को मुंह में दबाकर ले गया। बच्ची के माता-पिता की नींद खुली तो उन्होंने अपनी बेटी को तेंदुए के जबड़े में देखा।

दोनों ने शोर मचाया और तेंदुए का पीछा भी किया, लेकिन वह बच्ची को लेकर पास के गन्ने के खेत में भाग गया। कुछ समय बाद बच्ची का शव बरामद हुआ। आईएएनएस से बातचीत में सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) स्मिता कुलकर्णी ने बताया कि घटना की जानकारी वन विभाग को लगभग 15 मिनट के भीतर मिल गई थी। सूचना मिलते ही रात 3:15 बजे वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। टीम ने तत्काल इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

जगन मोहन रेड्डी ने तंबाकू किसानों को समर्थन देने का वादा किया

कडपा, 23 जुलाई (एजेंसियां)। वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस। जगन मोहन रेड्डी ने तंबाकू किसानों को भरोसा दिलाया है कि पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और उनके मुद्दों के लिए अपनी लड़ाई तेज करेगी। किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनने के बाद, उन्होंने घोषणा की कि वे जल्द ही पश्चिमी गोदावरी (जिसमें गोपालपुरम और जंगारेड्डीगुडेम शामिल हैं) का दौरा करेंगे ताकि सरकार पर उनकी उपज खरीदने का दबाव बनाया जा सके। जगन ने गठबंधन सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह कुल तंबाकू उत्पादन का 10 प्रतिशत भी नहीं खरीद पाई है, जिससे किसान बिचौलियों और सिंडिकेट के भरोसे रहने को मजबूर हैं। 232 मिलियन किलोग्राम के कुल उत्पादन में से, नीलामी शुरू होने के 94 दिनों में केवल 38 मिलियन किलोग्राम की ही खरीद हुई है।

कीमतें गिरकर 130 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गई हैं, जबकि पहले यह भरोसा दिलाया गया था कि कीमतें 200 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे नहीं गिरेंगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही किसी का लाइसेंस रद्द किया गया, जिससे किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ी। उन्होंने मांग की कि सरकार 'मार्कफेड' को सक्रिय करे ताकि प्रतिस्पर्धा पैदा हो, किसानों का भरोसा बहाल हो और उन्हें हुए नुकसान की भरपाई में मदद मिल सके। वाईएसआरसीपी के कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये का 'मार्केट इंटरवेंशन फंड' बनाया था और फसल खरीद पर 7,800 करोड़ रुपये खर्च किए थे, साथ ही आरबीके और सीएमएपीपी के जरिए कीमतों की निगरानी और समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित किया गया था।

वैवाहिक वेबसाइट पर अविवाहित बन मिली ठग की पत्नी, वकील की शिकायत पर पति गिरफ्तार

कोलकाता, 23 जुलाई (एजेंसियां)। महानगर के अलीपुर थाने की पुलिस ने एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर वैवाहिक वेबसाइट पर अपनी पत्नी को अविवाहित बताकर एक वकील के साथ धोखाधड़ी और दस्तावेज जालसाजी करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार इस मामले के शिकायतकर्ता पेशे से एक वकील हैं। वकील ने पुलिस को बताया कि एक वैवाहिक वेबसाइट पर उन्होंने शादी का विज्ञापन दिया था, जिसे देखकर बाचेंद्री भट्टाचार्य नाम की एक युवती ने उनसे संपर्क किया और शादी में रुचि दिखाई। बाचेंद्री ने पहचान की पुष्टि करने के बहाने वकील के महत्वपूर्ण दस्तावेज और पहचान पत्र ले लिये। वकील ने बताया कि कुछ समय बाद उस को पता चला कि युवती पहले से शादीशुदा है और उसके पति का नाम निर्माल्य भट्टाचार्य है।

हैरान करने वाली बात यह थी कि पति की सहमति से ही उसने खुद को अविवाहित बताया था। आरोपियों ने वकील के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर एक फर्जी राशन कार्ड भी बनवा लिया। सरकार की ओर से जारी राशन कार्ड में वकील को बाचेंद्री भट्टाचार्य का पति दर्शाया गया है। सच्चाई सामने आने के बाद वकील ने दक्षिण कोलकाता के अलीपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी।

504 करोड़ रुपए के सरकारी धन गबन मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, चंडीगढ़-लुधियाना में छापेमारी

लुधियाना, 23 जुलाई (एजेंसियां)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) के बैंक खातों से सरकारी धन गबन मामले में कार्रवाई करते हुए गुरुवार को चंडीगढ़ और लुधियाना में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य अपने कब्जे में लिए हैं। सीबीआई के अनुसार, कुल पांच स्थानों पर तलाशी ली गई। इनमें गबन की गई राशि के लाभार्थियों के घर और कारोबारी प्रतिष्ठान, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) के अधिकारी अनुभव मिश्रा का ठिकाना तथा जांच से जुड़े निजी संस्थानों के परिसर शामिल हैं। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को कई अहम सबूत मिले हैं। इनमें डिजिटल स्टोरेज ड्राइव, डिजिटल सिग्नेचर, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं।

अब इन दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बारीकी से जांच और विश्लेषण किया जा रहा है। सीबीआई ने बताया कि यह मामला पहले हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास था। राज्य सरकार के अनुरोध पर बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। जांच एजेंसी के मुताबिक, यह मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32, चंडीगढ़ शाखा से जुड़े एक बड़े बैंकिंग घोटाले का हिस्सा है। आरोप है कि हरियाणा सरकार के आठ विभागों के करीब 504 करोड़ रुपए सरकारी धन को फर्जी या अस्तित्वहीन फिक्स्ड डिपॉजिट और धोखाधड़ी वाले डेबिट लेनदेन के जरिए निकालकर शेल कंपनियों के माध्यम से इधर-उधर भेज दिया गया।

इस मामले में अब तक सीबीआई 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के तीन सरकारी कर्मचारी, दो कंपनियां और छह व्यक्ति शामिल हैं। सीबीआई ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े दो अन्य मामलों की जांच की। जिनमें पहला मामला चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) और नगर निगम चंडीगढ़ से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (सीआरईएसटी) से संबंधित है। इन दोनों मामलों में भी सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

सीएससीएल मामले में पांच बैंक अधिकारियों, एक सीएससीएल अधिकारी और एक निजी व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। वहीं सीआरईएसटी मामले में पांच बैंक अधिकारी, दो सीआरईएसटी अधिकारी, चार निजी व्यक्ति और दो कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। सीबीआई ने कहा कि वह इस पूरे मामले में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही गबन किए गए सार्वजनिक धन की पूरी श्रृंखला का पता लगाकर अपराध से अर्जित राशि को ट्रेस करने की दिशा में जांच लगातार जारी रहेगी।

हनीफ खान केसः गुजरात में सात पुलिसकर्मियों पर चलेगा हत्या का केस

अदालत ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट खारिज की

अहमदाबाद, 23 जुलाई (एजेंसियां)। गुजरात के सुरेंद्रनगर की एक अदालत ने वांछित अपराधी हनीफ खान मलिक और उसके नाबालिग बेटे की पुलिस कार्रवाई में हुई मौत के मामले में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी। अदालत ने सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या व आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) केपी शर्मा की अदालत ने 18 जुलाई को यह आदेश दिया। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को समन जारी कर 8 अगस्त को अदालत में उपस्थित होने को कहा गया है। पुलिस टीम ने 6 नवंबर 2021 को दसादा तालुका के गेडिया गांव में हनीफ खान और उसके नाबालिग बेटे को गोली मार दी थी।

पुलिस ने किया दावा था कि गिरफ्तारी के दौरान भीड़ ने हमला किया था और आत्मरक्षा में उसे गोली चलानी पड़ी। हनीफ खान की पत्नी सोहनाबेन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें उनके पति और नाबालिग बेटे की मौत हो गई। मई 2025 में अदालत के आदेश पर सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने दो महीने बाद अदालत में सी-समरी रिपोर्ट दाखिल की। ऐसी रिपोर्ट तब दी जाती है, जब जांच एजेंसी यह निष्कर्ष निकाले कि मामला न पूरी तरह सही है और न ही पूरी तरह गलत।

सोहनाबेन ने इस रिपोर्ट को चुनौती देते हुए कहा कि यह आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश है। याचिकाकर्ता के वकील पुनीत दवे ने बताया कि अदालत के सामने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और फोरेंसिक (एफएसएल) रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन पुलिस सब-इंस्पेक्टर वीएन जडेजा समेत सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और धारा 114 (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

सुविचार: परमात्मा में दृढ विश्वास का अर्थ है निर्भयता

भावी पीढ़ियों के लिए सिंगरेणी की दीर्घकालिक स्थिरता आवश्यक : भट्टी

> उत्पादन प्रक्रियाओं और कोयले की गुणवत्ता की समीक्षा

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि राज्य सरकार का सर्वोपरि उद्देश्य सिंगरेणी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) को एक मजबूत, कुशलतापूर्वक प्रबंधित और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बनाए रखना है, जिसके लिए इसके व्यवसाय का विस्तार करना और भावी पीढ़ियों के लिए इसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

उपमुख्यमंत्री ने सिंगरेणी को तेलंगाना की आत्मा बताते हुए कहा कि राज्य की जनता और यहां के कर्मचारी इस 130 साल पुरानी संस्था से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि इसे मजबूत बनाना और भावी पीढ़ियों को एक लाभदायक संगठन के रूप में सौंपना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उपमुख्यमंत्री ने गुरुवार को साथुपल्ली खुली कोयला खदान का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कोयला भंडार, उत्पादन प्रक्रियाओं और कोयले की गुणवत्ता की समीक्षा की। उनके साथ आए वरिष्ठ अधिकारियों में ऊर्जा विशेष मुख्य सचिव नवीन मित्तल, एससीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. बुद्ध प्रकाश ज्योति, टीजीजीईएनसीओ के सीएमडी डॉ. हरीश, एससीसीएल के निदेशक गौतम पोत्रू, खम्मम जिले के कलेक्टर दिवाकर टीएस, विधायक मट्टा रागमयी और मालोथ रामदास नाइक आदि शामिल थे। मीडिया से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह फील्ड विजिट खनन कार्यों का प्रत्यक्ष आकलन करने, कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने और उसकी भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए की गई थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विस्फोट और लोडिंग कार्यों के दौरान कोयले में ऊपरी परत, मिट्टी और चट्टानें न मिलें। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि कोयले की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक खुदाई और लोडिंग बिंदु पर निरंतर निगरानी आवश्यक है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि घटिया गुणवत्ता वाले कोयले के परिवहन से न केवल परिवहन लागत अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है, बल्कि तापीय ऊर्जा संयंत्रों की कार्यक्षमता भी कम हो जाती है और संयंत्र बंद होने की नौबत भी आ सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे टीजीजीनको और अन्य ग्राहकों को केवल उच्च गुणवत्ता वाला, शुद्ध कोयला ही आपूर्ति करें। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि कोयला क्षेत्र में कभी एकाधिकार था, लेकिन निजी कंपनियों के प्रवेश और विदेशों से कोयले के बढ़ते आयात के कारण अब बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए सिंगारेनी को उच्च गुणवत्ता वाला कोयला उत्पादन करने के साथ-साथ उत्पादन लागत को भी कम करना होगा। उन्होंने बताया कि सिंगारेनी ने पिछले दशक में नए कोयला ब्लॉकों की नीलामी में भाग न लेकर कई अवसरों को गंवा दिया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगारेणी लोगों को कम से कम 10 साल की रणनीतिक दृष्टि से योजनाएं तैयार करनी और उन्हें क्रियान्वित करना होगा। उन्होंने सिंगारेणी और टीजीजीईएनसीओ के प्रबंधन को राज्य में भविष्य की बिजली मांग का आकलन करके और अगले दशक में कोयले की संबंधित आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर संयुक्त रूप से एक दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक रुझान पर प्रकाश डालते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगारेनी को केवल कोयला उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से विस्तार करना चाहिए।

पूर्व डिपो प्रबंधक 1.23 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में दोषी

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। नामपल्ली के आठवें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चदरघाट पुलिस द्वारा जांच किए गए 1.23 करोड़ रुपये के आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के मामले में मेसर्स 3एफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक पूर्व डिपो मैनेजर को दोषी ठहराया है। अदालत ने एम वीरा वेंकट कृष्ण राव को आईपीसी की धारा 423, 408, 420, 468 और 506 के तहत दोषी पाए जाने के बाद एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने 2016 में कंपनी के सॉफ्टवेयर सिस्टम को ईआरपी से एसएपी में माइग्रेट करने के दौरान अनधिकृत मैनुअल बिल बनाए और कंपनी के स्टॉक को डायवर्ट किया। बाद में एक ऑडिट में 1.23 करोड़ रुपये मूल्य की 12,910 इकाइयों की कमी का पता चला। हालांकि आरोपी ने दायित्व स्वीकार करते हुए क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित किए, लेकिन आरोप है कि उसने राशि का भुगतान नहीं किया, ड्यूटी से फरार हो गया और कंपनी के अधिकारियों को धमकी दी। विस्तृत जांच और दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रस्तुति के बाद, अभियोजन पक्ष ने उसे दोषी ठहराया।

अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं लगभग 25 लाख छात्र : राव

भाजपा का शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। भाजपा तेलंगाना के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने गुरुवार को लंबित शुल्क प्रतिपूर्ति राशि की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता के कारण लगभग 25 लाख छात्र अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। बशीरबाग स्थित निज़ाम कॉलेज में 'फीस बकाया- भाजपा लड़ाई' (फीस बकाया- भाजपा संघर्ष) अभियान पोस्टर का अनावरण करते हुए राव ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) और महिला मोर्चा के नेतृत्व में भाजपा, पार्टी के विधायकों, सांसदों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस आंदोलन को राज्यव्यापी जनसभा में ले जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा सभी बकाया राशि का भुगतान होने तक आंदोलन जारी रखेगी और रेवंत रेड्डी सरकार पर उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बावजूद छात्रों की अनदेखी करने का आरोप लगाया तथा रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और भर्ती संबंधी चुनावी वादों को पूरा करने की मांग की।

कार्यक्रम में भाजपा विधायक दल की नेता अलेटी महेश्वर रेड्डी, राज्य महासचिव एन. गौतम राव, भाजपा राज्य उपाध्यक्ष जयश्री, भाजपा युवा मोर्चा राज्य अध्यक्ष गणेश कुंडे और अन्य लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा, भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, वामपंथी दल और कुछ विदेशी समर्थित समूह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में अशांति फैलाने और उसे अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कुछ अति-वामपंथी और नरम-वामपंथी ताकतें, साथ ही एसएफआई, एआईएसएफ और एएसए जैसे पुराने संगठनों के नेता, तिलचट्टा जनता पार्टी जैसे नए नामों के तहत एकजुट होकर भारत में हिंसा और अस्थिरता भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में देखा गया है। राज्य पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए राव ने दावा किया कि राष्ट्रविरोधी तत्व विदेशी समर्थन से युवाओं को भड़काने और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में केंद्र सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को मजबूत किया। उन्होंने केंद्र सरकार के रोजगार रिकॉर्ड पर भी प्रकाश डाला और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कथित तौर पर काम करने वाले संगठनों का समर्थन न करने की चेतावनी दी।

पिरामिड धोखाधड़ी मामले में क्यूनेट के पांच प्रतिनिधि गिरफ्तार

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। हैदराबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कथित मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) और पिरामिड धोखाधड़ी मामले में क्यूनेट के पांच स्वतंत्र प्रतिनिधियों को गोवा के एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया है, जिसमें कई लाख रुपये के निवेश शामिल हैं। सभी आरोपी केरल के मूल निवासी हैं। हैदराबाद निवासी सरदार शरणपाल सिंह की शिकायत के बाद कैंडोलिम में क्यूनेट कार्यक्रम के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। शरणपाल सिंह ने आरोप लगाया कि आकर्षक व्यापारिक लाभ का वादा करके उनसे 7.5 लाख रुपये का निवेश करवाया गया। उन्होंने शुरू में 30,000 रुपये ट्रांसफर किए थे। क्यूनेट को कथित धन परिसंचरण योजनाओं से जोड़ने वाली रिपोर्टों का पता चलने से पहले बुकिंग राशि के रूप में। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया, मनगढ़ंत सफलता की कहानियों, जूम मीटिंग और साथियों के दबाव की रणनीति का इस्तेमाल किया, जबकि लिखित संचार को हतोत्साहित किया। इस अभियान के दौरान, पुलिस ने तीन लग्जरी वाहन- एक टोयोटा फॉर्च्यूनर, किआ और एमजी हेक्टर- और पांच मोबाइल फोन जब्त किए जिनमें व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम संदेश और वित्तीय रिकॉर्ड सहित डिजिटल साक्ष्य मौजूद थे। आरोपियों को गोवा की अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें हैदराबाद स्थानांतरित करने के लिए ट्रांजिट रिमांड जारी कर दी। पुलिस ने बताया कि फरार अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार करने और अतिरिक्त पीड़ितों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

डीजीपी कार्यालय के कांस्टेबल ने आत्महत्या की, सट्टेबाजी ऐप के कर्ज का संदेह

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने गुरुवार तड़के कार्यालय परिसर के अंदर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान स्वामी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वह रात्रि ड्यूटी के दौरान सुबह करीब 5:30 बजे शौचालय गया और वहां उसने खुद को गोली मार ली। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वह सट्टेबाजी ऐप के जरिए लिए गए कर्ज के कारण गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पुलिस को एक हस्तलिखित नोट मिला है जिसमें स्वामी ने अनुरोध किया है कि उनकी पत्नी और बच्चों को दोषी न ठहराया जाए या परेशान न किया जाए, क्योंकि वे अच्छे लोग हैं। यादाद्री भुवनगिरी जिले के चौटुप्पल के मूल निवासी स्वामी को इसी महीने की शुरूआत में डीजीपी कार्यालय में तैनात किया गया था। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है।

ई-पेटी केस में संदिग्ध व्यक्ति को 15 दिन की जेल

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। हैदराबाद की एक अदालत ने चदरघाट पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक ई-पेटी मामले में दोषी पाए जाने के बाद 27 वर्षीय व्यक्ति को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी फिरोज खान को चदरघाट पुलिस स्टेशन क्षेत्र के भीतर अपराध करने के इरादे से संदिग्ध तरीके से घूमते हुए पकड़ा गया। हैदराबाद के छठे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एम भास्कर ने गुरुवार को उन्हें नगर पुलिस अधिनियम की धारा 61(बी) के तहत दोषी ठहराया। इस मामले की जांच एसआई बी येल्ला कृष्णा ने कोर्ट ड्यूटी ऑफिसर कांस्टेबल जी साईनाथ की सहायता से की। पुलिस ने कहा कि यह दोषसिद्धि सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए संदिग्ध तत्वों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

एआईएसएफ ने विरोध प्रदर्शन किया, लंबित छात्रवृत्तियों को जारी करने की मांग की

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। अखिल भारतीय छात्र संघ (एआईएसएफ) ने गुरुवार को हैदराबाद कलेक्ट्रेट में लंबित छात्रवृत्तियों को तत्काल जारी करने, शिक्षा मंत्री की नियुक्ति और राज्य में बेहतर शैक्षिक सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लकडीकापुल स्थित कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालने के बाद, एआईएसएफ नेताओं ने अतिरिक्त कलेक्टर जितेंद्र को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रवृत्ति की 11,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण शिक्षण संस्थानों को छात्रों के प्रमाण पत्र रोकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। छात्र संगठन ने सरकारी स्कूलों के प्रस्तावित विलय का भी विरोध किया, छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की आलोचना की और सरकार पर छात्रों के कल्याण की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

इंदिरम्मा आवास योजना पर दुष्प्रचार बंद करे बीआरएस : पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना के राजस्व, आवास, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आरोप लगाया कि हैदराबाद के मध्य क्षेत्र में गरीबों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की पहल से बीआरएस नेतृत्व असहज है और राजनीतिक लाभ के लिए दुष्प्रचार कर रहा है। गुरुवार को सचिवालय में इंदिरम्मा आवास योजना और प्राप्त आवेदनों की समीक्षा बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार गरीब परिवारों को उनके निवास क्षेत्र के निकट ही इंदिरम्मा आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को इकाई मानकर निर्माण कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा आवास के लिए पात्र व्यक्ति निकटतम मी सेवा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मी सेवा व्हाट्सऐप नंबर 8096958096 तथा मी सेवा वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। मंत्री ने कहा कि दस वर्ष तक सत्ता में रहने के बावजूद बीआरएस सरकार हैदराबाद के गरीबों के अपने घर के सपने को पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने गरीबों को शहर से 30 से 40 किलोमीटर दूर बसाने का प्रयास किया, जबकि वर्तमान सरकार उन्हें शहर के भीतर ही सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरम्मा टावर्स परियोजना शुरू कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले से बने डबल बेडरूम आवासों को इंदिरम्मा टावर्स बनाकर बेचने की खबरें पूरी तरह निराधार हैं। सरकार घोषित दिशा-निर्देशों के अनुसार नई परियोजना का निर्माण कर रही है।

केटीआर के 50वें जन्मदिन पर छात्राओं को 50 साइकिलें उपहार में दी गईं

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 'गिफ्ट ए स्माइल' पहल के तहत, तेलंगाना खाद्य निगम के पूर्व अध्यक्ष मेदे राजीव सागर ने गुरुवार को किंग कोटी स्थित एलेन हाई स्कूल की छात्राओं को 50 साइकिलें वितरित कीं। पूर्व मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और महमूद अली, एमएलसी दासोजू श्रवण के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। केटीआर के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए रामकोटी सीएसआई चर्च में विशेष प्रार्थना भी की गई। इस अवसर पर बोलते हुए राजीव सागर ने कहा कि यह पहल सार्थक कल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से समाज की सेवा करने के केटीआर के दृष्टिकोण को दर्शाती है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि साइकिलें छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने में सुगमता प्रदान करेंगी।

केंद्र संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है : सांसद लक्ष्मण

नई दिल्ली, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। भाजपा के राज्यसभा सांसद के. लक्ष्मण ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जिसमें नीट पेपर लीक मामला भी शामिल है, जबकि उन्होंने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया।

नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि नीट पेपर लीक के सिलसिले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने और संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए आलोचना की।

पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

कुलसुमपुरा पुलिस को मिली बड़ी कानूनी सफलता

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। हैदराबाद नगर पुलिस के गोलकोंडा क्षेत्र अंतर्गत कुलसुमपुरा थाना पुलिस ने वर्ष 2022 के चर्चित हत्या मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। यह मामला कुलसुमपुरा थाना के अपराध संख्या 188/2022 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में दर्ज किया गया था।

पुलिस के अनुसार, 15 जुलाई 2022 को संजय नगर, जियागुड़ा निवासी मेंडा संतोष (32) का अपनी पत्नी सरिता से विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपी ने पत्नी पर बेरहमी से हमला किया, कैंची से गंभीर चोटें पहुंचाईं और दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। मृतका की बड़ी बहन की शिकायत पर कुलसुमपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तत्कालीन विवेचक एवं कुलसुमपुरा थाना के निरीक्षक अशोक कुमार (वर्तमान में केंद्रीय अपराध शाखा, हैदराबाद में निरीक्षक) ने वैज्ञानिक एवं ठोस साक्ष्य एकत्र किए, महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए तथा न्यायालय में विस्तृत आरोपपत्र प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई सत्र वाद संख्या 705/2022 में नामपल्ली स्थित द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय में हुई। 23 जुलाई 2026 को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.बी. शीतल ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कठोर कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।

कुलसुमपुरा थाना प्रभारी ए. रामुलु ने मामले की सफल विवेचना और प्रभावी पैरवी के लिए तत्कालीन विवेचक अशोक कुमार, अतिरिक्त लोक अभियोजक रामकृष्ण, न्यायालय समन्वय में सहयोग देने वाले पुलिस कर्मियों तथा संबंधित स्टाफ की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके समन्वित प्रयासों से आरोपी को अधिकतम दंड दिलाना संभव हो सका। हैदराबाद नगर पुलिस ने कहा कि हिंसक अपराधों के प्रति उसकी शून्य सहनशीलता की नीति जारी रहेगी तथा पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते रहेंगे।

एससीएससी ने युवा पेशेवरों को साइबर सुरक्षा के प्रति प्रेरित किया

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। साइबरबाद सुरक्षा परिषद सोसायटी (एससीएससी) ने साइबरबाद पुलिस और तेलंगाना राइजिंग के सहयोग से गोपनपल्ली स्थित विप्रो परिसर में अपने प्रमुख कार्यक्रम 'कॉफी विद अ कॉप' का छठा संस्करण आयोजित किया, जिसका विषय था 'जुड़े रहें, उपभोग न करें: डिजिटल युग में आगे बढ़ना'। इस कार्यक्रम की मेजबानी विप्रो के सेंटर हेड वेंकट सेशु ने की, जिन्होंने इस पहल का स्वागत किया और कर्मचारियों को व्यावहारिक सुरक्षा जागरूकता प्रदान करने और सामुदायिक साझेदारी को मजबूत करने वाले सार्थक मंच बनाने में विप्रो, एससीएससी और साइबरबाद पुलिस के बीच सहयोग की सराहना की। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो की पुलिस अधीक्षक साई श्री ने फ़िशिंग, क्यूआर कोड घोटाले, फर्जी निवेश योजनाएं, ओटीपी धोखाधड़ी, एआई-जनरेटेड डीप फेक और सोशल इंजीनियरिंग सहित बढ़ते साइबर खतरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों से भरोसा करने से पहले सत्यापन करने और अच्छी साइबर स्वच्छता का पालन करने का आग्रह किया, और इस बात पर जोर दिया कि हर विकल्प, हर क्लिक, हर परिणाम मायने रखता है। युवा पेशेवरों ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, डिजिटल गोपनीयता और सोशल मीडिया सुरक्षा पर पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की।

'पैसे के अभाव में नहीं रुकेगा इलाज', गोरखपुर जनता दर्शन में बोले सीएम योगी

गोरखपुर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में आए लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार सबकी समस्या का समाधान कराने को प्रतिबद्ध है। गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता का अनुरोध लेकर आए लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि गंभीर बीमारियों के इलाज में सरकार भरपूर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए शीघ्रता से समस्या समाधान के लिए निर्देशित किया। साथ ही चेताया भी कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया

'अगर यह मामला'सदन के अंदर उठता, चर्चा होती, तो पूरे मामले पर नजरिया साफ होता

पटना, 23 जुलाई (एजेंसियां)।

नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी घोषणा की गई जिस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का रिएक्शन आया है।

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने पीएम मोदी के ऐलान पर कहा, नीट पेपर लीक का मामला सिर्फ छात्र-छात्राओं से

ही नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि अभिभावकों का भी भावनात्मक जुड़ाव है।

देश इस पर चिंता व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस संबंध में आश्वासन, कार्रवाई एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश हुआ जिससे उम्मीद है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।

न्यायपालिका उनको मुकम्मल सजा देगी। सभी लोगों को भरोसा, संयम और धैर्य रखना चाहिए। नीरज कुमार ने इस मामले में तूल दे रहे विपक्ष पर भी निशाना साधा।

नसीहत देते हुए कहा कि अगर यह मामला सदन के अंदर उठता, चर्चा होती, तो पूरे मामले पर नजरिया साफ होता।

उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक के मामले में कांग्रेस ने पहले क्या कहा था, गहलोत सरकार में भी 15 बार पेपर लीक हुआ था, सदन में चर्चा होती तो यह सारी बातें भी आतीं।

उन्होंने आगे कहा, मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है तो पार्लियामेंट में सब लोग को अपनी गलती कबूल करनी चाहिए। तकनीक का जो इस्तेमाल हुआ है उस पर कैसे नियंत्रण हो, एक साझा रणनीति बननी चाहिए और उस पर विपक्ष को सलाह देनी चाहिए।

विदेशी नागरिक की उत्पात से मचा हड़कंप, भेजा गया मानसिक चिकित्सालय

वाराणसी, 23 जुलाई (एजेंसियां)। मैदागिन क्षेत्र में एक विदेशी नागरिक का लोगों के घरों और बाजार में घुसकर हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। बाद में उसे छोड़ दिया गया था। अब वही विदेशी नागरिक एक बार फिर शहर में हंगामा मचाता नजर आया। पुलिस के अनुसार वही विदेशी नागरिक एक बार फिर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लोगों से उलझता और उत्पात मचाता मिला। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने दोबारा कार्रवाई की। उसे पकड़कर थाने लाया गया। शुरुआती जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने विदेशी नागरिक को उपचार के लिए मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया है। पहले उसके नशे की हालत में होने की चर्चा थी, लेकिन अब चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है।

'अगर बच्चे घायल हुए तो पुलिसवाले भी जख्मी हुए हैं'

दिल्ली प्रोटेस्ट पर अपर्णा यादव का बड़ा बयान

लखनऊ, 23 जुलाई (एजेंसियां)। दिल्ली में नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के आंदोलन पर हुए लाठीचार्ज पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्षी दलों पर इस आंदोलन को और आक्रोशित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उस दिन बच्चे घायल हुए तो कई पुलिसवाले भी घायल हुए हैं। उन्हें भी चोटें आई हैं। उन्होंने इस प्रदर्शन के पीछे अंडर करंट को लेकर भी सवाल उठाए। अपर्णा यादव ने छात्रों के आंदोलन और विरोधी दलों के खुलकर समर्थन पर कहा कि ये सब विपक्ष के सम्मानित नेता है, इस प्रकार जहां बच्चे और युवा थे जो इतने आक्रोशित थे, ऐसे समय पर उन्हें और आक्रोशित करना, उन्हें फ्यूल करना इसकी आवश्यकता नहीं थी।

मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रशासन ने वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की वो बहुत

अनिवार्य भी था। उन्होंने कहा कि इस दौरान पुलिस के लोगों को भी बहुत चोटें लगी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही उसमें घायल हुए हैं, पत्थरबाजी में बच्चों के साथ पुलिस को भी चोट आई हैं। मुझे लगता है कि वो भी इंसान हैं, जहां तक नीट की बात है तो अभी तो नतीजे आएं हैं उनमें कई ऐसे बच्चों ने भी क्वालिफ़ाई किया है जो सब्जी वालों के बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जिनकी मां ईंट के भट्टों पर काम करती थी उनकी बेटियों ने नीट क्वालिफाई किया है। अपर्णा ने कहा कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने पूरी मेहनत और शिद्दत से नीट परीक्षा पास की है। लेकिन ये बच्चे जो प्रदर्शन में हैं, वो कहां से हैं, इसके पीछे क्या अंडर करंट है ये आप लोगों के माध्यम से हमें पता चलेगा।

भारत में जो अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे उनको यथाउचित उसी प्रकार व्यवहार किया जाएगा। बता दें दिल्ली में नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन आज भी जंतर-मंतर पर जारी है। वहीं दूसरी तरफ़ मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने भी अपनी भूख हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। उन्होंने सरकार से माँग की है प्रदर्शन में आए बच्चों पर कार्रवाई न की जाए।

10 साल पहले पति, अब पत्नी की भी उसी तरह गई जान

हरदोई, 23 जुलाई (एजेंसियां)। यूपी के हरदोई से एक बड़ा ही दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां 10 साल पहले एक शख्स की जैसे जान गई थी। वैसे ही आज उसकी पत्नी की मौत हो गई। खौफनाक मंजर देखकर हर किसी के रौंगटे खड़े हो गए। दरअसल, कोतवाली देहात क्षेत्र के खेतुई गांव के रोडवेज बस अड्डे पर दर्दनाक हादसा हुआ। ड्राइवरों की घोर लापरवाही ने बेकसूर महिला की जान ले ली। कन्नौज व हरदोई डिपो की बसों के बीच फंसकर 32 साल की नेहा सिंह की मौत हो गई। खेतुई गांव की रहने वाली 32 साल की नेहा सिंह की दो रोडवेज बसों के बीच फंसने से मौत हो गई। वह एक निजी दवा कंपनी में काम करती थीं और उन्नाव के बांगरमऊ में आयोजित आधिकारिक बैठक में शामिल होने के लिए बस का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान कन्नौज डिपो और हरदोई डिपो की बसें आगे बढ़ीं और वह दोनों बसों के अगले हिस्से के बीच फंस गईं। गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

'चाहे रात से सुबह हो जाए वांगचुक से मिलकर ही जाएंगे', मेदांता अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर बैठी रहीं प्रिया सरोज

लखनऊ, 23 जुलाई (एजेंसियां)। नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। रात उनसे मिलने के लिए विपक्षी दल के नेताओं का एक समूह पहुंचा पर उनको मिलने नहीं दिया गया। इन नेताओं में सपा सांसद प्रिया सरोज , आप सांसद संजय सिंह और राजद के सांसद संजय यादव शामिल थे। ये लोग अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर काफी देर तक बैठे रहे। पुलिस ने विपक्षी नेताओं को अस्पताल के अंदर जाने और वांगचुक से मिलने की अनुमति नहीं दी।

इस पर प्रिया सरोज ने कहा- 'हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमको मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। चाहे रात से सुबह हो जाए मिलकर ही जाएंगे। ये मेडिकल प्रोटोकॉल जरा हमको भी दिखाइए। हमसे पहले कई नेता आए उनको आपने जाने दिया। हमारे लिए मेडिकल प्रोटोकॉल आ गया। हम लोगों के प्रति पुलिस का जो रवैया था वह बहुत गलत था।' संजय सिंह ने इस पूरे मामले पर विरोध जताया। उनका कहना है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पुलिस किसी अस्पताल में भर्ती मरीज से लोगों को मिलने से रोक रही है। हम सोनम वांगचुक से मिलना चाहते हैं। 55 सांसदों ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और हम यह पत्र उनको देने आए हैं। इस पत्र में वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने का अनुरोध किया गया है।

क्या ये लोग सोनम वांगचुक को मारना चाहते हैं? बता दें कि सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और समाजवादी पार्टी के 15 विपक्षी सांसद बुधवार देर शाम तक हॉस्पिटल के बाहर डटे रहे। इस दौरान उनकी पुलिस से भी तीखी नोकझोक हुई। सांसदों ने आरोप लगाया कि उनको बिना कोई स्पष्ट कारण बताए रोक दिया गया। सरकार आखिर किस बात से डर रही है? हालांकि सोनम वांगचुक की पत्नी से मुलाकात करने के बाद सभी सांसद अस्पताल से चले गए। सांसदों ने पुलिस पर गलत रवैये का आरोप लगाया।

'मैंने टीचर के 10 रुपये नहीं चुराए', 10 साल की आयुषी को स्कूल में इतना पीटा, घर आकर मासूम ने दे दी जान

मुजफ्फरनगर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित नई मंडी कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पंचेड़ा कलां गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 10 वर्षीय छात्रा आयुषी ने घर पहुंचकर फंदे से लटककर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। आरोप है कि स्कूल में 10 रुपये चोरी का आरोप लगाकर शिक्षिका और शिक्षक ने मासूम की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिससे क्षुब्ध होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक, कक्षा चार की छात्रा आयुषी पर स्कूल की टीचर सविता ने बैग से 10 रुपये चुराने का आरोप लगाया था। सविता की शिकायत के बाद स्कूल के शिक्षक राजीव ने मासूम छात्रा की स्कूल परिसर में ही बुरी तरह से पिटाई कर दी। मोहल्ले के लोगों और अन्य बच्चों के अनुसार, पिटाई के बाद बच्ची स्कूल से रोते हुए अपने घर पहुंची थी। वह इस अपमान और प्रताड़ना से मानसिक रूप से बेहद आहत थी।

मारपीट मामले में लखनऊ कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा

स्वतः संज्ञान लेकर पीआईएल दर्ज करने का निर्देश

लखनऊ, 23 जुलाई (एजेंसियां)। राजधानी स्थित जिला अदालत परिसर में वादकारी और दिल्ली से आए अधिवक्ताओं के साथ मारपीट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। साथ ही अदालत ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका (पीआइएल) के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान जिला जज और पुलिस आयुक्त की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। अदालत ने जिला अदालत की आठवीं मंजिल पर हुई घटना की सीसीटीवी फुटेज भी देखी। सुनवाई में सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल और महासचिव अवनीश दीक्षित वरिष्ठ अधिवक्ता डा। एलपी मिश्रा के साथ मौजूद रहे।

वहीं आरोपित अधिवक्ता सौरभ कुमार वर्मा की ओर से अधिवक्ता अनुपम मेहरोत्रा ने वकालतनामा दाखिल किया। भारत सरकार के डिप्टी सालिसिटर जनरल और सीबीआई के अधिवक्ता भी अदालत में उपस्थित रहे। हाई कोर्ट अब सभी पक्षों के जवाब, उपलब्ध साक्ष्यों और रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम आदेश जारी करेगा।

उल्लेखनीय है कि 21 जुलाई को लखनऊ जिला अदालत में दिल्ली से आईं महिला अधिवक्ता अभिप्सा मोहंती, उनके सहयोगी वकीलों और उनके मुवक्किल के साथ मारपीट और धमकी का मामला सामने आया था। महिला अधिवक्ता ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजन राय से मामले पर तत्काल ध्यान देने का आश्वासन दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने विशेष सुनवाई कर मामले का संज्ञान लिया।

आईएएस रिंकू सिंह अब मुश्किल में, जालौन में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख से हाथापाई मामले की जांच पुलिस के हवाले

जालौन, 23 जुलाई (एजेंसियां)। यूपी के चर्चित आईएएस अफसर रिंकू सिंह इस बार मुश्किल में हैं। जालौन में न्यायिक उप जिलाधिकारी पद पर तैनात आईएएस रिंकू सिंह राठी और ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन के बीच हुए विवाद की जांच अब पुलिस के हवाले कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) का कहना है कि यह केस राजस्व विभाग से जुड़ा नहीं है इसलिए जांच पुलिस ही करेगी। जून महीने में रिंकू सिंह अनियमितता की शिकायत मिलने पर एक कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां बीजेपी ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन भी पहुंच गए।

यहां किसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। ब्लॉक प्रमुख ने आरोप लगाया कि रिंकू सिंह ने उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था जिसमें दोनों के बीच धक्का-मुक्की देखी जा सकती है। विवाद सामने आने के बाद मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया।

'जब मंत्री के लायक नहीं तो झूठे का क्यों बनें'

अनंत सिंह का दो टूक- विपक्ष का काम है तो खिलाफ में बोलेगा ही?

पटना, 23 जुलाई (एजेंसियां)। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने दो टूक कह डाला कि हम मंत्री बनने लायक नहीं, झूठों के मंत्री हमको नय बनना है। हालांकि पत्रकारों से बातचीत के दौरान कल पटना में हुए प्रदर्शन को लेकर बतौर बानगी खुद का उदाहरण रख कर सच्ची बातें रख दी। और ऐसी बात जिस पर न तो पार्टी का रंग था और न ही बाहुबल का। चलिए जानते हैं कम पढ़े लिखे अनंत सिंह जाने अनजाने ही सही कैसे पढ़े-लिखों की पोल खोलते है। विधायक अनंत सिंह पर चाहे भले पढ़े-लिखे न होने का ठप्पा लगाते रहे पर किसी भी प्रश्न का जवाब देने में हाजिर पना का कोई जवाब नहीं। पत्रकारों ने पूछा कि विपक्ष हंगामा कर रहे हैं, सड़कों पर तोड़ फोड़ कर रहे थे।

प्रश्न खत्म होते ही अनंत सिंह बोल पड़े विपक्ष का काम क्या है? विरोध करना न! वही कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष तो इसलिए न होता है। विधायक अनंत सिंह कहते हैं कि काहे ल हुआ है ये हम नए जानते हैं। हम कहते है जो पढ़ता है वो पढ़े, चोरी चमारी के चक्कर में नए रहे। नौकरी लग जाए और पढ़ावे अयवे नए करें तो ऊ नौकरी कोई काम

के है। नीतीश कुमार जी हमरो मंत्री बनाते थे। जब हम मंत्री के लायक नहीं हैं तो झूठे के मुख्यमंत्री हमको नय बनना है। जदयू के विधायक अनंत सिंह के बयान पर पार्टी का रंगत नहीं होता। अब तेजस्वी यादव के संदर्भ में क्या कहा? प्रश्न था तेजस्वी विधानसभा के चलते सत्र में नहीं है? अनंत सिंह ने कहा ई हम नए जानते हैं। क्या पता शादी में होगा ,दोस्त यार के यहां होगा। ई हम कैसे बतावे कि कहां होगा। क्या पता बीमार होवे तब सदन कैसै जायेगा?

कोविड ड्यूटी में जान गंवाने वाले दारोगा की पत्नी को एचसी से राहत

अनुग्रह राशि दावे पर पुनर्विचार का आदेश

प्रयागराज, 23 जुलाई (एजेंसियां)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले उपनिरीक्षक की पत्नी को बड़ी राहत देते हुए जिलाधिकारी मुरादाबाद के उस आदेश को रद कर दिया है, जिसमें अनुग्रह धनराशि के लिए अर्जी खारिज कर दी गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने दिया है।याची ऊषा द्विवेदी के पति योगेंद्र प्रताप द्विवेदी थाना सिविल लाइंस में कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात थे।

ड्यूटी के दौरान वे संक्रमित हो गए और जांच में पाजिटिव पाए जाने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 23 अप्रैल 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी ने राज्य सरकार के शासनादेश के तहत 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि के लिए आवेदन किया, लेकिन जिलाधिकारी ने 11 नवंबर 2021 के आदेश से इसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया।

कारण यह बताया कि कोविड प्रबंधन ड्यूटी पर तैनाती संबंधी सक्षम अधिकारी का कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। राज्य के स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि मृतक की कोविड ड्यूटी पर तैनाती का कोई दस्तावेज समय दिए जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए मात्र संक्रमण और मृत्यु के आधार पर अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने पाया कि याचिका के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी वह प्रमाणपत्र संलग्न है, जिसमें मृतक की कोविड ड्यूटी पर तैनाती की पुष्टि की गई है। यद्यपि यह पत्र जिलाधिकारी के आदेश के बाद का है फिर भी 11 नवंबर 2021 की तिथि का एक अन्य ड्यूटी प्रमाणपत्र भी शासनादेश के प्रारूप के अनुसार मौजूद है, जिसमें मृतक की कोविड ड्यूटी की अवधि दर्शाई गई है। अदालत ने कहा कि अनुग्रह राशि से संबंधित शासनादेश का उद्देश्य कल्याणकारी प्रकृति का है और चूंकि विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का प्रमाणपत्र उपलब्ध है, इसलिए याची के दावे पर पुनर्विचार आवश्यक है।

खंडपीठ ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ताजा टिप्पणी/दस्तावेज मंगवाकर आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर याची के दावे पर पुनः विचार करें। याचिका बिना किसी हर्जाने के आदेश के साथ स्वीकार कर ली गई।

90 साल की उम्र में सपा विधायक आलम बदी का निधन, 5 बार बने एमएलए, सादगी थी उनकी पहचान

आजमगढ़, 23 जुलाई (एजेंसियां)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और आजमगढ़ के निजामाबाद से विधायक आलमबदी आजमी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 90 साल के थे। कुछ समय पहले उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। चार दिन पहले उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर आजमगढ़ स्थित उनके घर लाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में नेता, समर्थक और शुभचिंतक उनके आवास पहुंचे। राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी मदनी, सपा विधायक नफीस अहमद, उनके बेटे मुस्तजाब आलम बाबू और अन्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आलम बदी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक जाना-पहचाना चेहरा थे। वह पांच बार विधायक चुने गए और अपनी सादगी, साफ-सुथरी छवि और जनता से जुड़े रहने के लिए पहचाने जाते थे। उनके निधन से समाजवादी पार्टी और प्रदेश की राजनीति को बड़ा नुकसान हुआ है। विधायक आलमबदी का जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ में हुआ था। वह आजमगढ़ के विंदावल इलाके में रहते हैं।

अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करे तो आलम बदी ने 12वीं तक पढ़ाई की हुई है। इतना ही नहीं उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा भी हासिल किया हुआ है। राजनीति में आने से पहले वह एक इंजीनियर हुआ करते थे। सपा नेता की पत्नी का नाम कुदैशा खान है और उनके 6 बच्चे हैं। साल 1996 में उन्होंने पहली बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था और उन्हें आजमगढ़ में जीत भी मिली थी। इंजीनियर की नौकरी छोड़ राजनीति में आए आजमबदी के लिए इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़, राजनीति की तरफ रुख करना थोड़ा मुश्किल था। मगर उनके लिए कहीं न कहीं जनता और उनकी सेवा करना सबसे बड़ा मकसद था। दिलचस्प बात यह है कि सपा विधायक आलमबदी अपने पूरे राजनीतिक करियर में सिर्फ एक ही बार चुनाव हारे थे। इसके बाद से लगातार चुनाव जीते। पांच बार विधायक रहे है।

देहरादून में बन रही थीं कई कंपनियों की नकली दवाएं

एफएसडीए और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने किया खुलासा

लखनऊ, 23 जुलाई (एजेंसियां)। देहरादून के एक इंस्टिट्यूट में कई प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के नाम से नकली दवाएं बनाई जा रही थीं। एफएसडीए और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर दवा के नकली कारोबार के सिंडिकेट का खुलासा किया। मौके से कई कंपनियों के नाम से बनाई गईं नकली दवाएं बरामद हुई हैं। एफएसडीए और पुलिस की टीमें कई अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन कर रही हैं। देहरादून के देवीपुर न्यू हाइवे रोड परवाल क्षेत्र के न्यू होपटाउन में उत्तरांचल मेडिकल इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च फाउंडेशन संस्थान स्थित है। इसी इंस्टिट्यूट में नकली दवा बनाने का कारखाना चल रहा था।

एफएसडीए और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री में छापा मारा तो वहां से सिप्ला, ल्यूपिन, डॉ. रेड्डीज, एल्डर, माइक्रो, मैनकाइंड, इंटास, एबॉट, सन फार्मा, एरिस्टो,

मैक्लियोड्स और जाइडस सरीखी नामी दवा कंपनियों के नाम से बनाई गईं दवाएं बरामद हुईं।

फैक्ट्री में तैयार की गई नकली दवाओं के अलावा दवा बनाने का मैटीरियल, प्रिंटेड, पैकेजिंग सामग्री और उपकरण रैपर भी मिला है। एफएसडीए के अफसरों का दावा है कि ब्रांड का दुरुपयोग कर फैक्ट्री में नकली दवाइयां तैयार की जा रही थीं। इन दवाओं की पैकेजिंग भी इस प्रकार की जा रही थी कि खरीदार और दवा विक्रेता आसानी से भ्रमित हो सकते थे। एफएसडीए की टीम ने फैक्ट्री से मिली दवाओं और सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

फैक्ट्री संचालक रिसर्च इंस्टिट्यूट की आड़ में नकली दवाओं का गोरखधंधा कर रहे थे। फैक्ट्री के बाहर न्यू होपटाउन में उत्तरांचल मेडिकल इंस्टिट्यूट ऐंड रिसर्च फाउंडेशन संस्थान का बोर्ड लगा था। जिस पर एमईएचएम कंट्रोल बोर्ड दिल्ली-53 से एफिलेटेड दर्शाया गया है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर छानबीन कर रही है। इसके साथ ही फर्म के दस्तावेज भी जांचे जा रहे हैं। एफएसडीए की टीम ने तीन दिन पहले लखनऊ के अमीनाबाद, टीपीनगर में नकली दवाओं को सीज किया तो जांच में सामने आया था कि नकली दवाएं राजस्थान से बनकर आ रही हैं।

इस मामले में अमीनाबाद कोतवाली में राजस्थान के एक फर्म संचालक समेत आठ लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इस मामले के आरोपियों से पूछताछ और दस्तावेज की जांच में एफएसडीए को अहम सुराग मिले थे। जिसके बाद एफएसडीए की टीम पुलिस के साथ देहरादून पहुंची और नकली दवा का जखीरा पकड़ा है।

आधार कार्ड को कलकत्ता हाइकोर्ट ने बताया मौजूदगी का सबूत नागरिकता को लेकर कही ये बात

कलकत्ता, 23 जुलाई (एजेंसियां)। हाइकोर्ट ने हाल ही में आधार कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाइकोर्ट ने कहा कि भले ही आधार निवास का पक्का सबूत न हो, लेकिन यह किसी संपत्ति पर व्यक्ति की मौजूदगी या कब्जा का प्रथम दृष्टया में सबूत जरूर है। ये टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता को गार्डनरीच इलाके में कथित तौर पर जर्जर हो चुकी इमारतों को गिराने से रोक दिया। इससे पहले एक सिंगल-जज बेंच ने पोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था, जिसके तहत ट्रस्ट अपनी जमीन पर बनी 33 इमारतों को गिराना चाहता था। कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड किसी संपत्ति पर रहने का पहला सबूत माना जा सकता है। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के बाद, देश में आधार कार्ड की उपयोगिता पर एक बार फिर गहरा सवाल उठ खड़ा हुआ है। अब इसे सिर्फ एक पहचान पत्र ही नहीं, बल्कि कई जरूरी कामों का सशक्त माध्यम माना जा रहा है। पोर्ट अधिकारियों का तर्क था कि क्वार्टर में रहने वाले 52 लोगों में से सिर्फ 22 ने ही अपने आधार कार्ड दिखाये थे और सिंगल-जज बेंच का यह कहना सही था कि कब्जे का कोई सबूत नहीं दिया गया।

देशभर में आफत की बारिश

असम में बाढ़ से 41 की मौत, महाराष्ट्र में जल भराव, कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। देश भर में बारिश की कहर जारी है। बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों ने जान गंवाई है। असम में जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बारिश के कारण असम में एक ही दिन में 10 लोगों की मौत हो गई। मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, समीक्षा का विशेष ध्यान बाढ़ प्रभावित चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर था, और विभिन्न विभागों की स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया।

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसमें अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और 11 जिलों में 65 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। उन्होंने बताया कि सेना, वायु सेना और अन्य एजेंसियों ने राहत और बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं, साथ ही दूरदराज के इलाकों में फंसे लोगों को

आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्य की कई प्रमुख नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही थीं।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा दिन में गोलाघाट जिले के कुछ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने पड़ोसी जोरहाट और शिवसागर में बचाव कार्यों का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अनुसार, आधी रात से शुरू हुए 24 घंटों में आई बाढ़ में 10 लोगों की जान चली गई।

इसके साथ ही इस साल की बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। वहीं, महाराष्ट्र के पालघर जिले में रात भर हुई भारी बारिश ने कई कस्बों और गांवों को जलमग्न कर दिया, जिससे कई लोग फंसे रह गए और अधिकारियों को बचाव अभियान तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिला कलेक्टर इंदु रानी जाखर ने बताया कि एक व्यक्ति नाले में मृत पाया गया। उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कलेक्टर ने बताया कि एहतियात के तौर पर जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को गुरुवार को बंद रहने का आदेश दिया गया है। जाखर ने बताया कि बिगड़ती स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की एक अतिरिक्त टीम की मांग की है।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण तालुका में भारी बारिश के कारण प्रमुख पुल जलमग्न हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में यातायात और संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है, एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। ठाणे शहर में गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 99.32 मिमी बारिश दर्ज की गई। ठाणे नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन ताडवी ने बताया कि इस मौसम में अब तक कुल 1893.78 मिमी बारिश हुई है, जबकि पिछले साल यह 1270.48 मिमी थी।

सोने-चांदी का शौकीन निकला बिजली कंपनी का अफसर, संपत्ति का आंकड़ा 16 करोड़ तक पहुंचा

इंदौर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। इंदौर में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थ शिवराम सेमिल सोने-चांदी का शौकीन भी निकला। लोकायुक्त के छापे में उसके पास से 300 ग्राम सोना और 4 किलो चांदी भी मिली है। उसकी संपत्ति का आंकड़ा बढ़कर 17 करोड़ रुपये हो चुका है, जो अब तक के उसके सेवाकाल में मिले वेतन से 600 गुना ज्यादा है। सेमिल के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद बिजली कंपनी भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। लोकायुक्त अधिकारियों ने आयकर विभाग और सेबी से भी सेमिल की कंपनियों व संपत्ति से जुड़ी जानकारी मांगी है। सेमिल व उसके परिवार के बैंक खातों को भी फ्रीज करने के लिए गुरुवार को अधिकारी बैंकों को पत्र लिखेंगे। सेमिल के बेटों की शुभम इलेक्ट्रिकल और कर्निश पावर जोन नाम की कंपनियां हैं, जो बिजली उपकरणों से जुड़ी हैं। सूत्रों के अनुसार, वह बिजली कंपनी के ठेकेदारों पर दबाव बनाता था कि वे उसकी कंपनियों से ही सामान खरीदें। इससे कंपनियों को मोटा मुनाफा होता था। शुभम इलेक्ट्रिकल कंपनी के छह खातों में 62 लाख रुपये मिले हैं।

कैलाश विजयवर्गीय ने छात्रों को बताया था 'कीड़ा'? अब खुद दी सफाई, क्या कहा?

भोपाल, 23 जुलाई (एजेंसियां)। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमा गई है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर छात्रों को 'कीड़ा' बताने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छात्रों को 'कीड़ा' कहा है। हालांकि, मोहन यादव सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आरोपों का मंत्री कैलाश विजवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि, मैंने ऐसा कहा ही नहीं; उन्होंने (उमंग सिंघार) जो भी आरोप लगाए हैं, वे बेबुनियाद हैं। उन्होंने छात्रों के मन में मेरी छवि खराब करने की कोशिश की। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से छात्रों को कीड़ा बताए जाने संबंधित लगाए गए आरोपों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, शहर का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की गई। इंदौर में लगभग पांच लाख बच्चे पढ़ते हैं, छात्रों के मन में मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। मोहन के मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि, आवश्यकता पड़ी तो वे उमंग सिंघार पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराएंगे।

दरअसल, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि, मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छात्रों को 'कीड़ा' कहा, भाजपा छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर चर्चा नहीं चाहती। छात्रों के सम्मान और अधिकारों के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल सदन में आवाज उठा रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को छात्रों से माफी माँगनी होगी। जब तक मंत्री छात्रों से माफी नहीं माँगते, तब तक कांग्रेस विधायक दल विरोध से पीछे नहीं हटेगा।

'हर छात्र आंदोलन लोकतंत्र के लिए नहीं'

तसलीमा नसरीन की चेतावनी, बोलीं- बांग्लादेश सा न हो जाए भारत का हाल

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि जंतर-मंतर पर जुटे कॉकरोच आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को देखकर उन्हें बांग्लादेश के जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन की याद आ गई। उन्होंने कहा कि उस आंदोलन की शुरुआत आरक्षण और मेरिट के मुद्दे से हुई थी, लेकिन बाद में वह सरकार बदलने की मांग तक पहुंच गया। तसलीमा नसरीन ने दावा किया कि बांग्लादेश आज भी उस आंदोलन के बाद की स्थिति की कीमत चुका रहा है। उनके मुताबिक, वहां कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुईं और देश में हिंसा, सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, महिलाओं के खिलाफ अपराध, आतंकवाद और अराजकता बढ़ी। यह उनकी व्यक्तिगत राय है, जिसे उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में साझा किया। तसलीमा नसरीन ने लिखा कि जंतर-मंतर पर कॉकरोच आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को देखकर उन्हें जुलाई 2024 के बांग्लादेश आंदोलन की याद आ गई।

उन्होंने दोनों घटनाओं के बीच अपनी आशंका का जिक्र करते हुए कहा कि छात्र आंदोलनों को अब वह पहले की तरह आसानी से भरोसे की नजर से नहीं देख पाती हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की शुरुआत कोटा या मेरिट, मेरिट- मेरिट₹ के नारे से हुई थी, लेकिन बाद में आंदोलन का लक्ष्य सरकार को हटाना बन गया था। नसरीन के अनुसार, उसके बाद देश की स्थिति बिगड़ गई और कई गंभीर समस्याएं सामने आईं। तसलीमा नसरीन ने लिखा कि जुलाई 2024 की घटनाओं ने उन्हें यह सिखाया कि हर छात्र आंदोलन लोकतंत्र के लिए नहीं होता, हर सरकार विरोधी आंदोलन आजादी नहीं लाता और हर क्रांति वास्तव में क्रांति नहीं होती। उनके अनुसार, कुछ क्रांतियां पुरानी व्यवस्था को हटाकर उससे भी ज्यादा डरावनी स्थिति पैदा कर देती हैं।

10 गुना बढ़ी चांदी की तस्करी, सोने की स्मगलिंग में 186% की उछाल

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। सोने और चांदी की तस्करी में हाल में काफी तेजी देखने को मिली है। सरकार ने 12 मई को सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी। इसे 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया था। ईरान युद्ध के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए सरकार ने यह कदम उठाया था। चीन के बाद भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत ज्यादातर सोना आयात करता है। इसका आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने $72 अरब का सोना और $12 अरब की चांदी आयात की थी। लेकिन सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ने से स्मगलिंग के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है।

सरकार ने खुद इस बात को माना है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि इस साल 13 मई से 30 जून के बीच सोने की तस्करी के 287 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 160.91 टन सोना बरामद किया गया और 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार के मुताबिक 1 अप्रैल से 12 मई तक देश में सोने की तस्करी के 165 मामले पकड़े गए थे। इस दौरान 86.16 टन सोना बरामद किया गया और 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह 1 अप्रैल से 12 मई की अवधि की तुलना में 13 मई से 30 जून के बीच पकड़ी गए सोने की खेप में 186 फीसदी तेजी आई है। चांदी के मामले में 13 मई से 30 जून के बीच तस्करी के 16 मामले पकड़े गए। इस दौरान 535.92 टन चांदी बरामद की गई जो 1 अप्रैल से 12 मई की अवधि (49.53 टन) की तुलना में 10 गुना से भी ज्यादा है।

हालांकि इस दौरान केवल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2024-25 की तुलना में 2025-26 में सोने और चांदी की तस्करी में काफी कमी आई थी। सरकार ने साल 2024 में सोने की तस्करी रोकने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी थी। लेकिन मई में इंपोर्ट बढ़ने से तस्करी बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। भारत आने वाले सोने की सबसे ज्यादा तस्करी दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, खाड़ी देश, अफ्रीकी देश आदि से होती है। इन देशों में सोना सस्ता होता है।

ऑनलाइन ठगी पर हाई कोर्ट सख्त, बेव सीरीज 'प्रीतम और पेड्रो' का किया जिक्र, तीन राज्यों के डीजीपी तलब

जबलपुर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। देश में बढ़ रहे साइबर अपराध ने सबको परेशान कर के रखा है। लोगों की मेहनत की कमाई एक पल में गायब हो जा रही है। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों और पुलिस की धीमी कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा कि साइबर अपराधी कुछ ही मिनटों में लोगों की जीवन भर की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं, जबकि पुलिस की जांच और कार्रवाई बेहद धीमी गति से चल रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए पारंपरिक जांच व्यवस्था अब पर्याप्त नहीं है

और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग करना समय की जरूरत बन गया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जबलपुर निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई करीब 6.25 लाख रुपये की साइबर ठगी का उल्लेख किया। पीड़ित के खाते से रकम निकल जाने के बावजूद अपराधियों का पता लगाने और पैसे वापस दिलाने में जांच एजेंसियों को सफलता नहीं मिली। रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई को दौरान कोर्ट ने बेव सीरीज 'प्रीतम और पेड्रो' का जिक्र करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि तकनीकी एक्सपर्ट को पुलिस को एक मंच लाकर साइबर अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अदालत ने केंद्र, बैंकों और जांच एजेंसियों को साइबर ठगी से जुड़े मामलों के लिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता आयुष तिवारी ने बैंकों की लापरवाही का मुद्दा उठाया जिसके कोर्ट ने गंभीरता से लिया और व्यवस्था पर टिप्पणी की।

हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को 31 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने को कहा है। साथ जबलपुर एसपी को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिए। कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 11 दिनों में गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपने के लिए असम पुलिस की सराहना की।।

गीदड़ का शव खाते ही तड़पकर मरे 8 दुर्लभ गिद्ध, 4 लाल सिर, 2 सिनेरियस और 2 मिस्र प्रजाति के गिद्धों की मौत

पन्ना, 23 जुलाई (एजेंसियां)। टाइगर रिजर्व और आसपास के जंगलों में गिद्धों के संरक्षण की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। दक्षिण पन्ना वन मंडल से महज तीन किलोमीटर दूर पहाड़ीखेड़ा गांव के एक खेत में 8 दुर्लभ गिद्ध और एक सियार मृत पाए गए हैं। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि सियार का जहरीला शव खाने से इन गिद्धों की जान गई है। मृत पक्षियों में सबसे दुर्लभ माने जाने वाले 4 लाल सिर वाले, 2 सिनेरियस और 2 मिस्र प्रजाति के गिद्ध शामिल हैं।

यह पूरी घटना जंगल की सीमा से बाहर राजस्व विभाग के दायरे में आने वाली जमीन पर हुई है प्राथमिक जांच के मुताबिक, सियार की मौत करीब एक हफ्ते पहले हुई थी और उसका शव घनी झाड़ियों के बीच एक गड्ढे में पड़ा हुआ था, जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। भोजन की तलाश में पहुंचे गिद्धों ने जैसे ही सियार के मांस का सेवन किया, उनकी भी मौत हो गई।हालांकि वन अधिकारियों का कहना है कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि सियार की मौत किसी जहरीले पदार्थ को खाने से हुई या वजह कुछ और थी। पन्ना डीएफओ के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी शवों को कब्जे में लिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सियार और आठों गिद्धों के विसरा सैंपल एकत्र कर फॉरेंसिक जांच के लिए सागर और जबलपुर की लैब में भेज दिए गए हैं। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एल। कृष्णमूर्ति ने बताया कि घटना चूंकि राजस्व क्षेत्र की है, इसलिए पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमें हर एंगल से जांच कर रही हैं। लैब रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। यह घटना राजस्व क्षेत्र में हुई है। घटना के सभी संभावित पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

भारी बारिश से कई जिलों में नदियां ऊफनाई कावेरी नदी का जलस्तर 27 फीट तक पहुंचा

अहमदाबाद, 23 जुलाई (एजेंसियां)। नवसारी भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई जिलों में नदियां उफान पर है। कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। नवसारी जिले में लगातार बारिश के कारण पूर्णा नदी का जलस्तर 24 फीट तक पहुंच गया, जिससे कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। कावेरी नदी का जलस्तर 27 फीट तक पहुंच गया है, जो इसके 19 फीट के खतरे के निशान से ऊपर है। नवसारी में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।

करीब 218 अंदरूनी सड़कें बंद कर दी गई हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। मंत्री नरेश पटेल ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। मंत्री नरेश पटेल ने कहा, नवसारी में स्थिति कल से भी अधिक कठिन हो सकती है। डांग जिले के वाघई में 14 इंच से अधिक बारिश हुई है। कल रात 10 बजे से वंसदा में 15 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है।

डांग जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई बड़ी नदियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अंबिका नदी पर मौजूद गिरा वॉटरफॉल में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। प्रशासन ने पर्यटकों के लिए वॉटरफॉल तक जाने पर रोक लगा दी है और एहतियात के तौर पर लोगों से नदियों, झरनों और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। तापी के डोलवन के गदत के पास नेशनल हाईवे 56 पर भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया, जिससे यातायात बाधित हुआ।

डीएनए रिपोर्ट ने खोला राज सगा भाई ही निकला बच्चे का पिता... कोर्ट ने बेगुनाह युवक पर दर्ज केस किया रद्द

शिमला, 23 जुलाई (एजेंसियां)। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील और पेचीदा कानूनी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के झूठे आरोपों में फंसे एक बेगुनाह युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। जस्टिस राकेश कैंथला की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि जब वैज्ञानिक साक्ष्यों ने आरोपी को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर दिया है, तो उसे आपराधिक मुकदमे की मानसिक और कानूनी प्रताड़ना झेलने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। मामले की शुरुआत बिलासपुर जिले से हुई थी।

साल 2023 में बिलासपुर जिले के महिला पुलिस स्टेशन में नाबालिग पीड़िता के बयानों के आधार पर आयुष नाम के युवक पर केस दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 506 (धमकी देना) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि 9 मार्च 2023 को आयुष ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अदालत में मामले का रुख तब बदला जब वैज्ञानिक साक्ष्य सामने आए।

सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की मेघायल में हनीमून के दौरान हुई हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। तीन हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल में देरी होती है, तो 6 महीने बाद सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत याचिका दाखिल कर सकती है। आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

सुनवाई के दौरान सोनम रघुवंशी के वकील ने कहा कि इस मामले में कुल 94 गवाह बनाए गए हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ 4 गवाहों के ही बयान दर्ज हुए हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और कड़ी शर्तों के साथ उसे जमानत मिली है। सोनम के वकील ने कहा कि उसने सरेंडर नहीं किया है, उसे यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था, उसकी गिरफ्तारी को सरेंडर बताया जा रहा है। सोनम के वकील ने कहा कि वो जमानत की कड़ी शर्तों का पालन कर रही है। फरार होने का कोई खतरा नहीं है। मेघालय सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने

कहा कि जिस ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का हवाला दिया जा रहा है, उसका कोई आधार नहीं, क्योंकि आरोपी ने खुद सरेंडर किया था और चार्जशीट में भी ये बात दर्ज है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील को दो विकल्प दिया था और पूछा था कि क्या सोनम रघुवंशी सरेंडर करेगी या कोर्ट उसकी जमानत रद्द करने पर फैसला दे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आरोपी सोनम रघुवंशी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है

और उसके खिलाफ अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। ऐसे में केवल आरोपों के आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि दस्तावेज में केवल एक कानूनी धारा का नंबर टाइप करने में गलती हुई थी। इतनी छोटी तकनीकी गलती के आधार पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि जमानत बरकरार रहने की सूरत में सोनम के फरार होने की आशंका है।

सोनम की जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बदलते समाज में ये चीजें होना लाजमी है। आज की पीढ़ी हमसे ज्यादा जानकार हो सकती है, लेकिन प्रेशर से निपटने के मामले में वे ज्यादा कमजोर हैं। एसजी मेहता ने कहा कि उनके पास जानकारी ज्यादा है, ज्ञान नहीं। जस्टिस वराले ने कहा कि व्हाट्सएप? पर जो कुछ भी शेयर किया जा रहा है, उसे ज्ञान माना जा रहा है।

रेड सी और होर्मुज संकट से भारत के बासमती व्यापार पर असर; बंदरगाहों पर करीब 5 लाख टन चावल फंसा

चंडीगढ़, 23 जुलाई (एजेंसियां)। भारत के बासमती चावल के एक्सपोर्ट में लगातार रुकावटें आ रही हैं क्योंकि बाब अल-मंडेब और होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) जैसे अहम समुद्री रास्ते प्रभावित हैं। इससे रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ने वाले अहम समुद्री कॉरिडोर से होने वाले ग्लोबल ट्रेड को लेकर चिंता बढ़ गई है। इन एक साथ आई रुकावटों ने मिडिल ईस्ट और यूरोप के अहम बाजारों में भारत के बासमती चावल के शिपमेंट को प्रभावित किया है। इससे फ्रेट और इंश्योरेंस की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है और एक्सपोर्टर्स पर कैश की भारी कमी (लिक्विडिटी प्रेशर) का दबाव बढ़ गया है। गल्फ देशों के लिए भेजे जाने वाले करीब 5 लाख मीट्रिक टन बासमती और नॉन-बासमती चावल (जिसमें ईरान के लिए भेजा जाने वाला करीब 3 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल भी शामिल है) अभी गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों पर कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) पर फंसे हुए हैं।

ग्लोबल चावल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी करीब 45 फीसदी है और यह 140 से ज़्यादा देशों को चावल एक्सपोर्ट करता है, साथ ही पाकिस्तान और थाईलैंड जैसे बड़े एक्सपोर्टर्स से मुकाबला करता है। हालांकि, बासमती और नॉन-बासमती किस्मों सहित भारत का कुल चावल एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2026 में सालाना आधार पर 7.5 फीसदी घटकर 11.53 अरब डॉलर रह गया। वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान, भारत का चावल एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 4 फीसदी से ज़्यादा बढ़कर लगभग 3.03 अरब डॉलर हो गया। अकेले जून में, देश ने 1 अरब डॉलर से ज़्यादा मूल्य का चावल एक्सपोर्ट किया, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में लगभग 16 फीसदी ज़्यादा था। ऐसा क्षेत्रीय तनाव में अस्थायी कमी और गल्फ बाजारों में सप्लाई चेन की आंशिक बहाली के कारण संभव हुआ।

सऊदी अरब बासमती चावल एक्सपोर्ट के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है, जो सालाना करीब 12 लाख मीट्रिक टन चावल इम्पोर्ट करता है, जबकि ईरान ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान करीब 8 लाख मीट्रिक टन चावल इम्पोर्ट किया था। ये दोनों देश मिलकर भारत के सालाना बासमती एक्सपोर्ट का लगभग 20 लाख मीट्रिक टन हिस्सा लेते हैं, जिससे इस इंडस्ट्री के लिए गल्फ शिपिंग कॉरिडोर में स्थिरता बहुत ज़रूरी हो जाती है। इस अख़बार से बात करते हुए, बासमती राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वाइस-प्रेसिडेंट रंजीत सिंह जोसन ने कहा कि स्थिति बहुत चिंताजनक है क्योंकि सऊदी अरब भारतीय चावल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है,

जबकि ईरान भारतीय बासमती के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार बना हुआ है। अगर लाल सागर और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में रुकावटें लंबे समय तक जारी रहती हैं, तो भारत के बासमती निर्यात, बंदरगाह के कामकाज, कंटेनर लॉजिस्टिक्स और निर्यातकों की वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है।

सिंधु जल संधि पर भारत ने हड़काया तो बौखलाया पाकिस्तान

प्रतिनिधि की यूएनएससी में गुहार- भूखे मर जाएंगे हमारे लोग

न्यूयॉर्क, 23 जुलाई (एजेंसियां)। पाकिस्तान ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर भारत के रुख को गलत बताया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि इस संधि को रोकने का भारत का फैसला पूरी तरह गैर-कानूनी है। इससे पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो सकता है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में ये बातें भारत के कड़ा रुख दिखाने के बाद कही हैं। भारत ने यूएन के मंच से साफ किया है कि उसका सिंधु संधि को बहाल करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान आतंक को सपोर्ट कर रहा है।

डॉन के मुताबिक, यूएनएससी की बहस में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'किसी भी देश को साझा जल संसाधनों का इस्तेमाल दबाव बनाने या राजनीतिक दबाव डालने के हथियार के तौर पर करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये तब और खतरनाक हो जाता है, जब इससे संधि की शर्तों का उल्लंघन होता हो।'

पाकिस्तान ने आईडब्ल्यूटी पर भारत के रुख को गैरकानूनी कहा है

प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल टिकाऊ विकास और खुशहाली के लिए होना चाहिए, ना कि वे संघर्ष, जबरदस्ती या शोषण का कारण बनें। कई मामलों में कमजोर प्रशासन, अवैध खनन, बाहरी दखल, अंतरराष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन, और फायदों का असमान बंटवारा अस्थिरता और संघर्ष को बढ़ावा देता है और मानवीय संकट को गंभीर बनाता है।

'भारत पानी को हथियार बना रहा'

इफ्तिखार अहमद ने कहा, 'हमारे पूर्वी पड़ोसी (भारत) ने नदी के ऊपरी हिस्से वाले देश के तौर पर अपनी स्थिति का फायदा उठाकर सिंधु जल संधि को रोका है। इस कदम का ना तो संधि में और ना ही अंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धांतों में कोई आधार है। यह पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार बनाने की कोशिश है।'

अहमद ने आगे कहा कि किसी भी देश को साझा जल संसाधनों का इस्तेमाल दबाव डालने या राजनीतिक दबाव बनाने के हथियार के तौर पर करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। यूएनएससी की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों को रोके, क्या प्राकृतिक संसाधनों का हथियार बनाना अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है।

फर्स्ट सेक्रेटरी ने भी लगाए आरोप

पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी अंसार शाह ने कहा है कि भारत ने यूएन में तथ्यों को तोड़ने-मरोड़कर पेश किया। संधि में इसे कुछ समय के लिए रोकने की इजाजत देने वाला कोई प्रावधान नहीं है। भारत का एकतरफा कदम पूरी तरह से गैर-कानूनी है। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने कहा है कि संधि अपने विवाद निपटान तंत्र के साथ बाध्यकारी और लागू है। शाह ने आगे कह कि राजनीतिक दबाव के लिए, साझा प्राकृतिक संसाधन का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना कानूनी नियमों और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का गंभीर उल्लंघन है, जिसका मकसद पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी को भूखा मारना है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बनती है।

भारतीय जमीन पर 5000 साल पहले विकसित हुई थी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता

पाकिस्तान भी कर रहा दावा

इस्लामाबाद, 23 जुलाई (एजेंसियां)। सिंधु जल संधि पर भारत के साथ गतिरोध के बीच पाकिस्तान में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। पाकिस्तान ने हाल के दिनों में सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी 5000 साल पुरानी विरासत के रूप में पेश करना शुरू किया है। इसके लिए पाकिस्तान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों का हवाला देता है, जिससे वह दावा कर सके कि सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत उसकी है। दरअसल यह पाकिस्तान की सिंधु नदी के पानी पर अधिकार जमाने की एक कूटनीतिक चाल से ज्यादा कुछ नहीं है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को रोक दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता पर दावा भी उसी चाल का हिस्सा है।

दुनिया की सबसे शुरुआती सभ्यताओं में शामिल

सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की शुरुआती सभ्यताओं में एक माना जाता है। इसके साथ ही इतिहासकार इसे भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास की नींव मानते हैं। ऐसे में 5000 साल पुरानी सभ्यता पर पाकिस्तान का दावा हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। खासतौर पर जब उसने 1947 में अपने गठन के बाद से इस सभ्यता से खुद दूरी बनाए रखी है। सिंधु सभ्यता एक सुव्यवस्थित और पूरी तरह से विकसित सभ्यता थी, जिसका शहरी डिजाइन आज भी पुरातत्व के शोधकर्ताओं को आश्चर्यचकित करता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में सबसे पहले खोजे गए इस सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य इसकी गवाही देते हैं। इन शहरों में एक जैसा ग्रिड पैटर्न दिखाई देता है, फिर चाहे वह शहरी श्रेणी में बने घर हों, सामुदायिक सुविधाएं, जल प्रबंधन प्रणाली या पक्की सड़कें हों। सिंधु घाटी सभ्यता की एक और बात जो हैरान करती है, वह यह है कि पूर्ण विकसित सभ्यता होने के बावजूद इसमें न तो कोई मंदिर, महल या अमीर लोगों के घर मिले हैं। यह तत्कालीन दूसरी सभ्यताओं के मुकाबले एक बड़ा अंतर है, जहां राजाओं और पुजारियों के लिए शानदार इमारतों को बहुत महत्व दिया जाता था। ऐसे में उनके समाज का ढांचा, संगठन, शासन व्यवस्था और धार्मिक मान्यताएं अभी भी एक पहेली बनी हुई हैं।

पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता पर दावा कर रहा है

सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता की खोज 19वीं सदी की शुरुआत में हुई, जब इलाके में रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे ब्रिटिश इंजीनियरों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों से बने खंडहर खोजे। ईंटों के सही सलामत और एक ही तरह के आकार से उन्होंने समझा कि ये कुछ सौ साल से ज्यादा पुरानी नहीं हैं और उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। यह सिलसिला 1921 में रुका पर जब पुरातत्वविदों ने दिलचस्पी ली।

इसके बाद दो भारतीय पुरातत्वविदों दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में 1921 और 1922 में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम शुरू हुआ।

थाईलैंड में हिंसाः दक्षिणी प्रांत में सुरक्षा चौकी पर हमला

गोलीबारी-पाइप बम विस्फोट में पांच सैनिकों की मौत

नाराथिवाट, 23 जुलाई (एजेंसियां)। थाईलैंड के दक्षिणी प्रांत नाराथिवाट में सुरक्षा चौकी पर हुए एक बड़े आतंकी हमले में पांच सैनिकों की मौत हो गई। हमलावरों ने पहले सुरक्षा चौकी पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की और फिर पाइप बम फेंककर हमला किया।

घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। थाईलैंड की रॉयल आर्मी की इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस कमांड (आईएसओसी) के अनुसार, यह हमला 22 जुलाई की शाम नाराथिवाट प्रांत के रा-न्गे जिले के बुकेह सामी चेकपॉइंट पर हुआ। उस समय 45वीं रेंजर फोर्स रेजिमेंट के जवान सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान हथियारबंद हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। आईएसओसी ने सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने दक्षिणी सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान अधिकारियों को सी साखोन जिले में एक वाहन मिला, जिसे हमले में इस्तेमाल किए जाने का संदेह है। अधिकारियों के मुताबिक, हमलावरों ने सबूत मिटाने के लिए उस वाहन को आग के हवाले कर दिया था।

फोरेंसिक टीम ने हमले वाली जगह और बरामद वाहन दोनों स्थानों से साक्ष्य जुटाए हैं। इनकी मदद से हमलावरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन जल्द दे सकते हैं इस्तीफा

शेख हसीना से फोन पर बात करना पड़ा भारी, बढ़ा दबाव

ढाका, 23 जुलाई (एजेंसियां)। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन जल्दी ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि शेख हसीना से संपर्क करने को लेकर उन पर पद छोड़ने का दबाव है। शहाबुद्दीन शीर्ष पद पर बैठे शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के समय के अकेले नेता हैं, जो जुलाई-अगस्त 2024 में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद भी काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक सीनियर नेता ने पीटीआई को बताया है कि शहाबुद्दीन के जल्द ही इस्तीफा देने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने इस्तीफे के समय पर कोई जानकारी नहीं दी। कई बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट ने रिपोर्ट किया है कि तारिक रहमान की सरकार शहाबुद्दीन के प्रेसिडेंट के पद पर बने रहने से खुश नहीं है।

शहाबुद्दीन ने शेख हसीना के पीएम रहते राष्ट्रपति पद संभाला था

ढाका के प्रोथोमोलो ने एक सीनियर सरकारी सोर्स का हवाला देते हुए बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन उन खबरों से नाखुश है, जिनमें कहा गया है कि शहाबुद्दीन ने हाल ही में शेख हसीना से फोन पर बातचीत की है। द डेली स्टार ने एक बीएनपी नेता के हवाले से कहा कि शहाबुद्दीन और हसीना के बीच बातचीत के अलावा हसीना के ढाका लौटने के ऐलान ने भी चीजों को बदला है।

इस महीने की शुरुआत में शेख हसीना ने कहा था कि वह साल के आखिर में ढाका लौटना चाहती हैं। बांग्लादेश सरकार ने जवाब में कहा कि वह उनकी वापसी का स्वागत करती है लेकिन उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शेख हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में ढाका की एक अदालत मौत की सजा सुना चुकी है। बांग्लादेश सरकार ने हसीना को वापस आने पर सीधे जेल भेजने की बात कही है।

बांग्लादेश के संविधान के हिसाब से अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक संसद के अध्यक्ष हाफिजुद्दीन अहमद अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 में पांच साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। उस वक्त बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की सरकार थी।

शहाबुद्दीन के राष्ट्रपति बनने के अगले साल अगस्त में छात्र आंदोलन के चलते अवामी लीग की सरकार गिर गई और शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद बांग्लादेश में अवामी लीग के करीबी लोगों को सभी शीर्ष पद छोड़ने पड़े।

राजीव भवन घेराव के दौरान बवाल, पुलिस पर पथराव

रायपुर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। रायपुर में भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस ने कांग्रेस के 12 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। साथ ही कांच की बोतलें, लकड़ी और जूते भी फेंके। जिससे 16 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए।

खम्हारडीह थाना प्रभारी की शिकायत पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं, देर रात रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना।

थाना प्रभारी भावेश कुमार गौतम के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में भाजयुमो के राजीव भवन घेराव कार्यक्रम को देखते हुए खम्हारडीह थाना, रक्षित केंद्र और अन्य थानों का पुलिस बल तैनात किया गया था।

कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग तक पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन वे पुलिस से धक्का-मुक्की करने लगे।भावेश गौतम ने बताया कि इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कांच की बोतलें, पत्थर, लकड़ी और जूते फेंके। इस घटना में पीएसआई देवराज सिंह के सिर में चोट लगी, महिला आरक्षक सीमा बंजारे समेत अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया।

नवाज शरीफ बनेंगे पीओके के अगले प्रधानमंत्री?

बिलावल भुट्टो का बड़ा खुलासा, मरियम पर कसा तंज

मुजफ्फराबाद, 23 जुलाई (एजेंसियां)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताने के बाद अब पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुबानी हमला बोला है। बिलावल भुट्टो ने बुधवार को दावा किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) अपने नेता नवाज शरीफ को पीओके का पीएम बनाने के लिए संविधान में बदलाव करने जा रही है।

नवाज शरीफ तीन बार पाकिस्तान के पीएम रह चुके हैं। पीओके में भारी बवाल के बीच पाकिस्तान सरकार चुनाव कराने पर अड़ी है। बिलावल कई दिनों से प्रदर्शनकारियों को अपने पाले में लाने के लिए सेना विरोधी बयान भी दे रहे हैं। अब नवाज शरीफ के दांव से बिलावल को हार का खतरा महसूस हो रहा है।

मीरपुर शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, 'पीएमएल-एन चाहती है कि रायविंड का एक नागरिक जो पाकिस्तान का तीन बार पीएम रह चुका है, उसे पीओके का प्रधानमंत्री बनाया जाए।' वता दें कि रायविंड शरीफ परिवार का घर है। बिलावल ने यह भी कहा कि पीएमएल-एन नवाज शरीफ को पीओके का पीएम बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहती है। इसके जरिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ को पीओके का पीएम नियुक्त कर सकेंगे।

इससे एक दिन पहले ही नवाज शरीफ ने एक रैली में मजाक के तौर पर कहा था कि वह शहबाज से कहेंगे कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो मुझे पीओके का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। पाकिस्तान सरकार भारी विरोध प्रदर्शन के बाद भी पीओके तीन चरणों में चुनाव कराने जा रही है।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती को ब्लैकमेल किया

रायगढ़, 23 जुलाई (एजेंसियां)। रायगढ़ जिले में युवती इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद साइबर ठगी का शिकार हो गई। आरोपी ने पहले उसे अपने प्रेमजाल में फंसाया, फिर उसकी निजी फोटो और वीडियो लेकर वायरल करने की धमकी दी। डराकर उसने युवती से 13 हजार रुपए ले लिए। परेशान होकर युवती ने साइबर थाना में शिकायत की। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया है। लैलूंगा थाना क्षेत्र की 23 साल की युवती ने 12 जून को साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि करीब 6 साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी पहचान मुजफ्फरपुर के रहने वाले अविनाश उर्फ राजा से हुई थी। दोनों की बातचीत बढ़ी तो आरोपी ने भरोसा जीतकर युवती से निजी फोटो और वीडियो मंगवा लिए।

फ्रांस में कीटनाशक पर बैन हटा, पर्यावरण मंत्री का इस्तीफा

कहा- मधुमक्खियों की जान बचाना जरूरी
सरकार बोली- किसानों को बचाना ज्यादा जरूरी

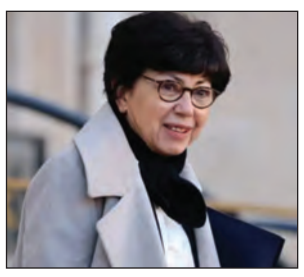

पेरिस, 23 जुलाई (एजेंसियां)। फ्रांस की पर्यावरण मंत्री मोनिक बारबू ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने यह फैसला विवादित कृषि बिल के विरोध में लिया है, जिसमें दो प्रतिबंधित कीटनाशकों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है।

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कीटनाशक मधुमक्खियों और दूसरे परागण करने वाले कीड़ों के लिए नुकसानदायक हैं। पर्यावरण मंत्री बनीं बारबू आज राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंपेंगी। फ्रांस की संसद ने मंगलवार को यह बिल पेश किया था। सीनेट ने 214-111 मतों से विधेयक पारित कर दिया। सरकार ने दावा किया कि ये कानून किसानों की मदद के लिए लाया जा रहा है। उसका कहना है कि किसानों को घटती कमाई और खेती की बढ़ती लागत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

बिल के दो प्रावधानों से सबसे ज्यादा विवाद

कीटनाशकों की मंजूरी: प्रतिबंधित कीटनाशकों एसेटामिप्रिड और फ्लुपाइराडीफ्यूरोन के इस्तेमाल की अस्थायी मंजूरी देना। इसका इस्तेमाल चुकंदर, सेब और चेरी की खेती में किया जा सकेगा।

नुकसान- पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे मधुमक्खियों की संख्या तेजी से घटेगी जिससे परागण पर असर पड़ेगा। इससे किसानों की पैदावार और आय पर उल्टा असर पड़ेगा।

पानी जमा करने की इजाजतः किसानों को सिंचाई के लिए बड़े जलाशय या कृत्रिम तालाब बनाने की अनुमति आसानी से मिले।

नुकसान- पर्यावरणविदों का कहना है कि ये जलाशय भूजल और नदियों से बड़ी मात्रा में पानी भरते हैं। इससे गर्मियों में नदियों और भूजल का स्तर घट सकता है जिससे पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ेगा।

इन्हीं प्रावधानों को लेकर पर्यावरणविदों और सरकार के भीतर भी विरोध बढ़ गया। इसके विरोध में पर्यावरण मंत्री मोनिक बारबू ने पद छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वह कीटनाशक और पानी के भंडारण से जुड़े दोनों प्रस्तावों के खिलाफ थीं। ये दोनों प्रावधान विधेयक में आखिरी समय में जोड़े गए थे, ताकि रूढ़िवादी बहुमत वाली सीनेट से इसे पारित कराया जा सके। बारबू ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनसे किए गए वादे के विपरीत इस प्रावधान को हटाने पर कोई चर्चा ही नहीं होने दी।

बारबू ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले नौ महीनों में मैंने जंगलों, साफ पानी, स्वच्छ हवा, उपजाऊ मिट्टी और जैव विविधता की रक्षा के लिए काम किया। लेकिन विरोधी ताकतें इतनी मजबूत हो गई हैं कि मैं अपने मकसद पूरे नहीं कर पा रही।

इजराइली विरोध के बावजूद सऊदी को परमाणु तकनीक देगा अमेरिका

ट्रम्प ने समझौते की मंजूरी दी, एक्सपर्ट बोले- परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ेगा

वॉशिंगटन, 23 जुलाई (एजेंसियां)। सऊदी अरब ने बुधवार को अमेरिका के साथ एक अहम परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं इसके तहत अमेरिका, सऊदी अरब को असैन्य (बिजली बनाने के लिए) परमाणु तकनीक देगा। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव का माहौल है।

इस समझौते को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। वह पिछले पांच साल से भी ज्यादा समय से यह समझौता चाह रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल समेत अमेरिका के कई अधिकारी और न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यदि सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की तकनीक मिल गई, तो भविष्य में वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में भी बढ़ सकता है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू होने का खतरा पैदा हो सकता है।

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले कई बार कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है, तो सऊदी अरब भी परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में कदम उठाएगा।

अमेरिका अब तक 26 देशों के साथ ऐसा समझौता कर चुका है। भारत के साथ अमेरिका ने 2008 में परमाणु समझौता किया था।

अमेरिका गैर-परमाणु देशों के साथ समझौता करते समय शर्त रखता है कि वे देश यूरेनियम संवर्धन खुद नहीं करेंगे, लेकिन इस समझौते में यह शर्त नहीं है। सऊदी अरब में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। अगर उसे यूरेनियम संवर्धन की इजाजत मिलती है, तो वह आगे परमाणु ईंधन तैयार कर सकेगा।

सऊदी अरब का मकसद 2030 तक अपनी बिजली का बड़ा हिस्सा परमाणु ऊर्जा से पैदा करना है, ताकि तेल पर निर्भरता कम हो।

परमाणु बिजलीघर (न्यूक्लियर रिएक्टर) बनाने में 10 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए इस समझौते के बाद सऊदी अरब लंबे समय तक अमेरिका की परमाणु तकनीक और मदद पर निर्भर रहेगा।

होर्मुज बंद होने से नेपाली किसान बदहाल

भारत के सख्त ऐक्शन से गहराया संकट, टेंशन में बालेन शाह

काठमांडू, 23 जुलाई (एजेंसियां)। नेपाल में धान की बुवाई अपने चरम पर है और किसानों को खाद मिलने में भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही खाड़ी देशों से यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट यानि डीएपी का निर्यात रुक गया है। इससे नेपाल को खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं कई नेपाली भारत से यूरिया और डीएपी की तस्करी कर रहे थे लेकिन अब भारत ने भी सख्त ऐक्शन लेना शुरू कर दिया है। बिहार में नेपाल के 2 कसिनों को खाद की तस्करी करने के आरोप अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद नेपाल में काफी विवाद हो रहा है और बालेन शाह सरकार ने इन दोनों नेपाली नागरिकों को छोड़ने के लिए कूटनीतिक प्रयास को तेज कर दिया है।

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल ने कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली में अपने दूतावास के जरिए अपने दोनों कसिनों को रिहा कराने के लिए प्रयास कर रही है। नेपाली मीडिया ने बताया कि 55 साल के सुरेश प्रसाद सिंह और उनके भाई नागेंद्र प्रसाद सिंह को अरेस्ट किया गया है। नेपाली दूतावास बिहार सरकार से इन दोनों को छुड़ाने के लिए संपर्क में है। इन दोनों को बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनवरसा में अरेस्ट किया गया था। इन लोगों ने बिहार में खाद खरीदी थी ताकि उसे नेपाल ले जाकर खेत में डाल सकें। नेपाल के ये दोनों किसान साइकिल पर यूरिया और डीएपी की बोरी लेकर जा रहे थे। इन्हें सीमा पर एसएसबी के जवानों ने पकड़ लिया। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में खाद की कमी होने की वजह से उन्हें भारत से तस्करी का खतरा उठाना पड़ रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बालेन शाह सरकार को खाद संकट के बारे में पूरी जानकारी थी लेकिन वह समय पर इसको उपलब्ध कराने में फेल रही। इसकी वजह से नेपाल के किसान खासकर तराई इलाके के किसानों को भारतीय बाजार पर निर्भर होना पड़ा है। भारत में खाद पर हजारों करोड़ की सब्सिडी दी जाती है लेकिन इसे नेपाल ले जाना कानूनी अपराध है।

देवशयनी एकादशी कल सही तिथि और पारण का समय

आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई को शुरू तो हो रही है, लेकिन इसका आरंभ सूर्योदय के बाद होता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि व्रत 24 जुलाई को रखा जाए या 25 जुलाई को। आइए जानते हैं इस वर्ष देवशयनी एकादशी की सही तिथि क्या रहेगी।

देवशयनी एकादशी 2026 की तिथि को लेकर 24 और 25 जुलाई के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसकी मुख्य वजह यह है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई को शुरू तो हो रही है, लेकिन इसका आरंभ सूर्योदय के बाद होता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि व्रत 24 जुलाई को रखा जाए या 25 जुलाई को। आइए जानते हैं इस वर्ष देवशयनी एकादशी की सही तिथि क्या रहेगी।

आषाढ़ शुक्ल एकादशी 2026 में कब है?

आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजकर 12 मिनट से प्रारंभ होगी और 25 जुलाई को सुबह 11 बजकर 34 मिनट तक रहेगी। हालांकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि 24 जुलाई को शुरू हो रही है, लेकिन उस दिन सूर्योदय के समय दशमी तिथि विद्यमान रहेगी।

हिंदू परंपरा में व्रत और त्योहारों की तिथि तय करते समय सूर्योदय के समय की तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, जिसे 'उदया तिथि' कहा जाता है। चूंकि 25 जुलाई के सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी, इसलिए व्रत उसी दिन रखना शास्त्रों के अनुसार उचित माना जाएगा।

एकादशी तिथि का समय

एकादशी तिथि प्रारंभः 24 जुलाई 2026, सुबह 9:12 बजे

एकादशी तिथि समाप्तः 25 जुलाई 2026, सुबह 11:34 बजे

व्रत की तिथिः 25 जुलाई 2026

तिथि निर्धारण का आधारः उदया तिथि

24 जुलाई को सूर्योदय के समयः दशमी तिथि

25 जुलाई को सूर्योदय के समयः एकादशी तिथि

सुजीत महाराज बताते हैं कि पंचांग की तिथियां अंग्रेजी तारीखों की तरह रात 12 बजे नहीं बदलतीं, बल्कि दिन या रात में किसी भी समय शुरू और समाप्त हो सकती हैं। यही कारण है कि एक ही तिथि दो अलग-अलग कैलेंडर डेट्स में पड़ सकती है।

इस बार एकादशी तिथि 24 जुलाई को सुबह करीब सवा नौ बजे शुरू हो रही है। ऐसे में कुछ लोग तिथि के आरंभ के आधार पर 24 जुलाई को व्रत मान सकते हैं। लेकिन 24 जुलाई के सूर्योदय पर दशमी तिथि रहेगी, जबकि 25 जुलाई को सूर्योदय एकादशी में होगा। इसलिए 25 जुलाई को व्रत रखना अधिक उचित है।

देवशयनी एकादशी 2026 पारण समय

देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु 26 जुलाई 2026, रविवार को पारण करेंगे। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 5:39 बजे से 8:22 बजे तक रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर 1:57 बजे तक रहेगी।

एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। इसलिए श्रद्धालुओं को निर्धारित समय में भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद दान-पुण्य कर व्रत का समापन करना चाहिए।

देवशयनी एकादशी का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते। इसके बाद कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागरण के साथ मांगलिक कार्य पुनः शुरू होते हैं।

देवशयनी एकादशी पर तुलसी पूजा क्यों है खास?

हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है, लेकिन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का स्थान सबसे विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन से भगवान विष्णु अगले चार महीनों के लिए क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल में जाने से पहले तुलसी की पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है।

देवशयनी एकादशी 2026 कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई, शनिवार को रखा जाएगा। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन से भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसी वजह से इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास के दौरान कई तरह के मांगलिक कार्यों को करने की मनाही बताई गई है। इसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के साथ ही शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।

देवशयनी एकादशी पर तुलसी पूजा क्यों है खास?

धार्मिक मान्यता में तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष स्थान है। देवशयनी एकादशी पर तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलने की मान्यता है। मान्यता है कि इस दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे की साफ-सफाई करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करने के साथ भगवान विष्णु का ध्यान और मंत्र जाप करना भी शुभ माना जाता है।

तुलसी के पास दीपक जलाने की मान्यता

देवशयनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी के पास दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक माहौल बनता है। कहा जाता है कि दीपक की रोशनी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित करने से घर में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार घी या तेल का दीपक जला सकते हैं।

देवशयनी एकादशी पर कैसे करें तुलसी पूजा?

इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो उसके आसपास की जगह को साफ करें और तुलसी माता को प्रणाम करें। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। श्रद्धा के अनुसार तुलसी माता की पूजा करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। पूजा के बाद भगवान विष्णु से परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। शाम के समय भी तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हैं।

चातुर्मास की होती है शुरुआत

देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दौरान भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हैं। इस अवधि में भक्त पूजा-पाठ, व्रत, दान और धार्मिक कार्यों पर विशेष ध्यान देते हैं। चातुर्मास के दौरान सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक महीने आते हैं। इस दौरान भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है।

दिल के बेहद अमीर होते हैं ये 4 मूलांक मदद में रहते हैं सबसे आगे

हम अक्सर लोगों की पर्सनालिटी जानने के लिए उनकी राशि की बात करते हैं, लेकिन अंक ज्योतिष में जन्म तारीख से निकलने वाला मूलांक इंसान के असली स्वभाव और उसके दिल का हाल बयां करता है।अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ खास अंकों से प्रभावित लोग दिल के बेहद साफ़, दयालु और दरियादिल होते हैं। ये लोग दूसरों का दुख-दर्द देखकर चुप नहीं बैठ पाते और मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाते हैं। इनके लिए अपनों से ज्यादा दूसरों की खुशी मायने रखती है। आइए जानते हैं अंक ज्योतिष के उन 4 खास मूलांकों के बारे में, जो दिल के अमीर माने जाते हैं।

मूलांक 2 वाले लोग होते हैं बेहद संवेदनशील जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। अंक ज्योतिष में मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। इस मूलांक के लोग स्वभाव से काफी संवेदनशील और भावुक होते हैं। ये सामने वाले की परेशानी को जल्दी समझ लेते हैं और कई बार बिना कहे ही उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं।मूलांक 2 वाले लोग रिश्तों को काफी अहमियत देते हैं। अगर इनका कोई अपना किसी परेशानी में हो तो ये उसकी मदद करने में पीछे नहीं हटते।

मूलांक 6 वाले लोगों का दिल होता है बड़ा

जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है। अंक ज्योतिष में इस अंक का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। इस मूलांक के लोग आमतौर पर मिलनसार, आकर्षक और दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाले माने जाते हैं। मूलांक 6 वाले लोग किसी जरूरतमंद की मदद करने में आगे रहते हैं। अगर उनके सामने कोई व्यक्ति आर्थिक, भावनात्मक या किसी अन्य परेशानी से जूझ रहा हो तो वे अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करते हैं।

मूलांक 9 वाले लोग दूसरों के लिए कुछ भी करने को तैयार

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है। अंक ज्योतिष में इस अंक का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। मूलांक 9 वाले लोग साहसी और जोशीले स्वभाव के माने जाते हैं। इनके अंदर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा भी काफी मजबूत हो सकता है। इन लोगों के लिए परिवार और दोस्त बहुत मायने रखते हैं। यही कारण है कि अपने करीबियों की मुश्किल घड़ी में ये उनका साथ छोड़ने के बजाय हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं।

मूलांक 3 वाले लोग भी होते हैं मददगार

जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। अंक ज्योतिष में इस अंक का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है। इस मूलांक के लोग समझदार, सकारात्मक सोच वाले और मार्गदर्शन करने वाले स्वभाव के माने जाते हैं।मूलांक 3 वाले लोग सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर सही सलाह देकर भी दूसरों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश करते हैं।

फ्लैट खरीदते समय ध्यान रखें वास्तु शास्त्र के ये जरूरी नियम

एक मध्यवर्गीय परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है कि कब उसके पास अपना घर होगा। एक घर को लेने के लिए आम आदमी अपने पूरे जीवन की जमापूंजी लगा देता है। इतना ही नहीं वो अपने आने वालों सालो की कमाई को भी एक घर को खरीदने में लगा देता है। लोग अपनी मेहनत की कमाई से नया आशियाना तलाशते हैं ताकि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।

मुख्य प्रवेश द्वार

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का मुख्य द्वार उत्तर, उत्तर-पूर्व और पूर्व दिशा में होना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित मुख्य द्वार को सामान्यतः कम शुभ माना जाता है। वहीं ध्यान रखें कि दरवाजे के सामने सीढ़ियां, बंद दीवार या संकरी गैलरी न हो।

रसोई की दिशा

रसोई की दिशा हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में होना सबसे शुभ माना जाता है। दक्षिण-पूर्व दिशा अग्नि तत्व की दिशा मानी जाती है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम दिशा भी रसोई यानी किचन के लिए उत्तम होता है।

मास्टर बेडरूम की दिशा

फ्लैट का मास्टर बेडरूप की दिशा का भी ध्यान रखें। मास्टर बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना अच्छा माना जाता है। इस दिशा में मास्टर बेडरूम होने से आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मजबूत होता है।

टॉयलेट की दिशा

फ्लैट खरीदते समय टॉयलेट की दिशा का जरूर ध्यान रखें। टॉयलेट कभी भी उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। शौचालय का स्थान पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में होना बेहतर माना जाता है।

बालकनी और खिड़कियों की दिशा

उत्तर और पूर्व दिशा में खुलने वाली बालकनी या बड़ी खिड़कियां घर में प्राकृतिक प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा लाने में सहायक मानी जाती हैं।

फ्लैट का आकार

वास्तु शास्त्र के अनुसार, फ्लैट का आकार वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए। ऐसे फ्लैट सबसे अच्छे माने जाते हैं। वहीं फ्लैट का उत्तर-पूर्व दिशा खुला होना चाहिए तभी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) को सबसे पवित्र दिशा माना गया है।

चातुर्मास क्या होता है?

चातुर्मास का अर्थ है "चार महीने"।

यह आषाढ़ शुक्ल एकादशी (देवशयनी एकादशी) से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी (देवउठनी एकादशी) तक चलता है।

इस साल चातुर्मास की शुरुआत 25 जुलाई 2026 से हो रही है और इसका समापन 21 नवंबर को होगा।

इस दौरान क्या होता है विशेष?

- भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं।
- भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं।
- इस समय को धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है।

चातुर्मास 2026 : 4 महीने राशि अनुसार कर लें कुछ खास उपाय

इस साल चातुर्मास की शुरुआत 25 जुलाई 2026 से हो रही है और इसका समापन 21 नवंबर को होगा। बता दें हर साल देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास शुरू होता है और देवउठनी एकादशी तक यह रहता है। चातुर्मास में कई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। कहते हैं इस दौरान किए गए शुभ और मांगलिक कार्यों के सफल होने की संभावना कम रहती है। हालांकि यह समय जप, तप, ध्यान, दान-पुण्य करने आदि कार्यों के लिए अनुकूल होता है। इसके अलावा ये 4 महीने भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी खास माने जाते हैं। ज्योतिष अनुसार अगर इस दौरान आप अपनी राशि के हिसाब से कुछ खास उपाय करते हैं तो इससे जीवन में सुख-समृद्धि ला सकते हैं।

चातुर्मास 2026 राशि अनुसार उपाय

राशि का नाम उपाय

मेष चातुर्मास के प्रत्येक मंगलवार को मसूर की दाल या लाल रंग के वस्त्र का दान करें। साथ ही रोजाना सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएं।

वृषभ चातुर्मास के प्रत्येक शुक्रवार को सफेद रंग के वस्त्रों या चावल का दान करें। साथ ही गाय को चारा खिलाएं।

मिथुन चातुर्मास के हर बुधवार के दिन हरे फल या मूंग की दाल का दान करें। गायों की सेवा करें। झूठ बोलने से बचें।

कर्क चातुर्मास के हर सोमवार को दूध या चावल का दान करें। साथ ही अपने बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें।

सिंह चातुर्मास के प्रत्येक रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या चातुर्मास के हर बुधवार के दिन हरी सब्जियां दान करें और जरूरतमंदों को भोजन खिलाएं

तुला तुला वाले चातुर्मास के प्रत्येक शुक्रवार के दिन मिठाई या इत्र का दान करें। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें।

वृश्चिक चातुर्मास के हर मंगलवार के दिन काले तिल का दान करें। गरीबों को भोजन खिलाएं।

धनु चातुर्मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र और हल्दी का दान करें। साथ ही इस दिन गले पर हल्दी का तिलक भी लगाएं।

मकर चातुर्मास के प्रत्येक शनिवार को काले रंग के वस्त्रों, काले तिल, सरसों के तेल या काली उड़द की दाल का दान करें।

कुंभ चातुर्मास के प्रत्येक शनिवार तेल या काले तिल का दान करें। भूखों को भोजन कराएं।

मीन चातुर्मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन चने की दाल या केले का दान करें। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें।

स्वतंत्र वार्ता

शुक्रवार, 24 जुलाई - 2026

जंतर-मंतर : आंदोलन की आड़ में अराजकता का खेल...!

सुरेश गांधी

दिल्ली का जंतर-मंतर दशकों से लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक रहा है। यह वह मंच है जहां असहमति ने संविधान की मर्यादाओं के भीतर अपनी आवाज बुलंद की है। किसानों से लेकर कर्मचारियों तक, छात्रों से लेकर सामाजिक संगठनों तक-हर वर्ग ने यहां अपनी बात रखी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने केवल एक आंदोलन को नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विरोध की पूरी संस्कृति को कठघरे में खड़ा कर दिया है। पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन लगभग एक महीने तक शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। देश के लाखों युवाओं ने इसे अपना संघर्ष माना। सोशल मीडिया से लेकर विश्वविद्यालय परिसरों तक इसकी गूंज सुनाई दी। यह आंदोलन सरकार से जवाब मांग रहा था, व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा था और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा चाहता था। लेकिन अचानक तस्वीर बदल गई। जंतर-मंतर से निकलकर टॉलस्टॉय मार्ग और राजधानी के अन्य हिस्सों तक तनाव फैलने लगा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें आने लगीं। पथराव हुआ, पुलिस अधिकारियों के घायल होने की सूचना आई, डंडों से हमले के आरोप लगे और देर रात तक तनाव का माहौल बना रहा। देखते ही देखते चर्चा का केंद्र पेपर लीक नहीं, बल्कि हिंसा बन गई। यहीं से देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है-एक महीने तक शांतिपूर्ण रहा आंदोलन अचानक हिंसक कैसे हो गया?

यह प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं है। यह लोकतंत्र, कानून-व्यवस्था और जन आंदोलनों की विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पेपर लीक के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा की। संसद में इस मुद्दे पर

विस्तृत चर्चा की पेशकश भी की गई। सरकार ने विपक्ष से यहां तक कहा कि चर्चा का समय और अवधि भी वही तय कर ले। यानी संवाद का रास्ता खुला रखा गया। ऐसी स्थिति में एक और प्रश्न सामने आता है—जब बातचीत और समाधान की दिशा खुल रही थी, तब भी टकराव क्यों जारी रहा? इसका उत्तर अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन सवाल पूरी तरह जायज है। इसी बीच आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए बाहरी तत्व भेजे गए। उनका दावा है कि जो लोग पथराव और हिंसा कर रहे थे, वे मूल आंदोलनकारी नहीं थे। ये आरोप बेहद गंभीर हैं। यदि इनमें सच्चाई है तो यह केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आंदोलनों की पवित्रता पर हमला है। यदि ऐसा नहीं है, तो जांच में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तविकता क्या थी। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके कई अधिकारी घायल हुए, पथराव हुआ और सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाई गई। पुलिस का दावा है कि हमलावरों की पहचान की जा रही है। यानी एक ओर आंदोलनकारी बाहरी तत्वों की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर पुलिस हिंसक हमले का आरोप लगा रही है। इन दोनों दावों के बीच कहीं न कहीं वह सच मौजूद है, जिसे देश जानना चाहता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कुछ वीडियो और रिपोर्टों में ऐसे लोगों की मौजूदगी की चर्चा भी सामने आई है जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि बताई जा रही है। यदि ऐसे लोग वास्तव में आंदोलन में मौजूद थे, तो यह जांच का गंभीर विषय है कि वे वहां किस उद्देश्य से आए थे।

लेकिन केवल किसी की मौजूदगी से उसकी हिंसा में भूमिका स्वतः सिद्ध नहीं हो जाती। इसलिए जांच का निष्पक्ष और पारदर्शी होना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक जन आंदोलनों में समय-समय पर ऐसे तत्व घुसने की आशंका जताई जाती रही है जो मूल उद्देश्य को पीछे धकेलकर टकराव को आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए लोकतंत्र में हर बड़े आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल अपनी मांगों को लेकर नहीं होती, बल्कि अपनी विश्वसनीयता और अनुशासन को बनाए रखने की भी होती है। आज देश का युवा केवल पेपर लीक का समाधान नहीं चाहता, बल्कि यह भी जानना चाहता है कि उसकी आवाज के साथ आखिर हुआ क्या? यदि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हुई, तो किसने की? यदि हिंसा स्वतःस्फूर्त थी, तो क्यों हुई? यदि बाहरी तत्व सक्रिय थे, तो वे कौन थे? यदि राजनीतिक हित बीच में आ गए, तो उसका खामियाजा छात्रों को क्यों भुगतना पड़ा? इन सवालों के जवाब केवल जांच एजेंसियों के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए भी आवश्यक हैं। क्योंकि जब किसी छात्र आंदोलन की पहचान उसके मूल मुद्दे से हटकर हिंसा से होने लगे, तब सबसे बड़ी हार किसी सरकार या विपक्ष की नहीं, बल्कि उस छात्र की होती है जिसने अपने भविष्य के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष शुरू किया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष केवल हिंसा नहीं है, बल्कि वह राजनीति है जो हिंसा की छाया में तेजी से आकार लेती दिखाई दे रही है। पेपर लीक का मुद्दा करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह ऐसा विषय है जिस पर स्वाभाविक रूप से सत्ता और विपक्ष दोनों को एक मंच पर दिखाई देना चाहिए था। सरकार को जवाब देना था, विपक्ष को सवाल पूछने थे और संसद को समाधान का रास्ता निकालना था। लेकिन घटनाक्रम ने जिस दिशा में मोड़ लिया, उसने कई नए प्रश्न खड़े कर दिए।

एक ओर सरकार ने पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, कठोर कार्रवाई और संसद में चर्चा की बात कही। दूसरी ओर विपक्ष ने यह कहते हुए आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं और जवाबदेही तय होनी चाहिए। लोकतंत्र में यह अधिकार विपक्ष को प्राप्त है। लेकिन इसी के साथ यह जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि आंदोलन अपनी मूल भावना से भटके नहीं। यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है—क्या छात्र आंदोलन का केंद्र छात्र रहे या राजनीति? जब किसी जन आंदोलन में अलग-अलग राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति के साथ उतरते हैं, तब यह खतरा हमेशा बना रहता है कि मूल मुद्दा धीरे-धीरे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के शोर में दब जाए। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं में भी यही आशंका दिखाई दी।

पानी घटा तो अन्न भी घटेगा

गिरता भूजल स्तर केवल पंजाब का संकट नहीं, बल्कि पूरे देश की तस्वीर पेश कर रहा है। इसने कृषि, पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है। जिस पंजाब ने हरित क्रांति के दम पर देश की खाद्य सुरक्षा की मजबूत नींव रखी, वही आज गिरते भूजल स्तर के कारण अपने सबसे बड़े पर्यावरणीय और कृषि संकट से जूझ रहा है। कभी देश का अन्न भंडार भरने वाला यह राज्य आज जल संकट की भयावह तस्वीर पेश कर रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के 153 में से 111 ब्लॉक 'ओवर-एक्सप्लॉइटेड' श्रेणी में पहुंच चुके हैं, जबकि लुधियाना सर्वाधिक भूजल दोहन वाला जिला बन गया है। जालंधर, संगरूर, पटियाला और तरनतारन जैसे कृषि प्रधान जिले भी तेजी से जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं। इस स्थिति की सबसे बड़ी वजह दशकों से चली आ रही कृषि व्यवस्था है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सरकारी खरीद की नीति ने किसानों को बड़े पैमाने पर धान की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। धान की फसल के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। लगातार एक ही फसल उगाने, भूजल पर बढ़ती निर्भरता, अनियमित वर्षा और जलवायु परिवर्तन ने मिलकर भूजल स्तर को पाताल लोक तक नीचे पहुंचा दिया है। नतीजतन प्राकृतिक जल भंडार अपनी भरपाई की क्षमता खोते जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इस संकट को लेकर वर्षों से चेतावनियां दी जाती रही हैं, लेकिन समाधान आज भी कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया है। फसल विविधीकरण, माइक्रो-इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, वर्षा जल संचयन तथा भूजल पुनर्भरण जैसी योजनाओं की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन उनका प्रभाव जमीन पर अपेक्षित स्तर तक दिखाई नहीं देता। जब तक इन योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक केवल घोषणाएं हालात नहीं बदल सकतीं। इस संकट का पूरा दोष किसानों पर डालना भी न्यायसंगत नहीं है। किसानों ने वही फसल उगाई, जिसे सरकारी नीति और बाजार ने सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया। इसलिए समाधान भी नीति-आधारित होना चाहिए। यदि सरकार मक्का, दालें, तिलहन और अन्य कम पानी वाली फसलों की खरीद सुनिश्चित करे, उनके लिए लाभकारी मूल्य और मजबूत बाजार उपलब्ध कराए तथा तकनीकी सहायता और प्रोत्साहन दे, तो किसान बदलाव अपनाने के लिए आखिर क्यों तैयार नहीं होंगे? इसके साथ ही भूजल दोहन पर प्रभावी निगरानी, अवैध बोरवेल पर सख्ती, उद्योगों में जल पुनर्चक्रण, शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना और देश के हर गांव में भूजल पुनर्भरण की वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। धरती से पानी निकालना जितना आसान है, उतना ही कठिन उसे दोबारा प्राकृतिक रूप से भरना है। इसलिए जल संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनआंदोलन का स्वरूप देना होगा। यदि आज भी सरकारें, किसान, उद्योग और समाज मिलकर जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देते, तो आने वाले वर्षों में संकट केवल पानी का नहीं रहेगा, बल्कि खेती, रोजगार, अर्थव्यवस्था और देश की खाद्य सुरक्षा का भी होगा। पंजाब का भूजल संकट हमें स्पष्ट संदेश देता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन विकास का आधार नहीं बन सकता। समय रहते वैज्ञानिक जल प्रबंधन, दूरदर्शी कृषि नीति और जनभागीदारी के साथ ठोस कदम उठाना ही भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पंजाब की यह चेतावनी पूरे देश के लिए एक सबक है, यदि आज पानी नहीं बचाया गया, तो कल अन्न बचाना भी संभव नहीं होगा।

नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी के बयान से विवाद

स्नेहा सिंह

न्यूयार्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध अपराधी हैं। उन्होंने बताया कि वे कानूनी विशेषज्ञों से यह सलाह ले रहे हैं कि न्यूयार्क आने पर किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के संबंध में मेयर के अधिकार क्या हैं। उनके इस बयान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में नेतन्याहू की गिरफ्तारी नहीं होने दी जाएगी।

सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक न्यूयार्क में होने वाली है, जिसमें नेतन्याहू के शामिल होने की संभावना है। एक अखबार को दिए साक्षात्कार में ममदानी ने कहा कि नेतन्याहू की जगह न्यूयार्क नहीं, बल्कि हेग में है, जहां अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) स्थित है। उन्होंने यह भी कहा कि वे कानून की सीमाओं के भीतर ही कार्य करेंगे और कोई नया कानून बनाने की बात नहीं कर रहे हैं।

ममदानी के बयान पर संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने इसे निरर्थक बताया। वहीं अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूयार्क के मेयर के पास किसी विदेशी नेता को गिरफ्तार कराने का अधिकार नहीं है। माना जा रहा है कि ममदानी का यह बयान ट्रम्प को राजनीतिक चुनौती देने के उद्देश्य से दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने 21 नवंबर, 2024 को नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन पर गाजा युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों के आरोप हैं। आरोप है कि इजरायली सेना ने नागरिक आबादी पर हमले किए तथा गाजा में भोजन, दवाइयों, पानी, ईंधन और बिजली की आपूर्ति बाधित करने की कोशिश की।

वारंट जारी होने के बाद नेतन्याहू ने अपनी विदेश यात्राएं सीमित कर दी हैं। वे मुख्य रूप से अमेरिका और हंगरी गए हैं। अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, क्योंकि उसने 1998 की रोम संधि (रोम स्टैच्यूट) पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत, चीन, रूस और इजरायल सहित कई देश भी इस संधि के सदस्य नहीं हैं।

आईसीसी के अनुसार अब तक 61 लोगों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चुके हैं। हालांकि किसी दूसरे देश में किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। आमतौर पर जिन देशों में गिरफ्तारी की आशंका नहीं होती, नेता वहीं की यात्रा करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में नेतन्याहू की गिरफ्तारी की संभावना नहीं है और ममदानी ने केवल इस मुद्दे को उठाकर नया विवाद खड़ा किया है।

विश्लेषकों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की साख लगातार कमजोर हुई है। संयुक्त राष्ट्र और आईसीसी के फैसलों को कई देश अपनी सुविधानुसार मानते या अनदेखा करते हैं।

पुतिन के खिलाफ भी वारंट

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने 17 मार्च, 2023 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन पर यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से हजारों बच्चों को अवैध रूप से रूस भेजने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में रूस की बाल अधिकार आयुक्त मारिया ल्वोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ था। रूस का कहना था कि बच्चों को युद्धग्रस्त इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया।

गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पुतिन चीन, भारत, उत्तर कोरिया, ईरान और सऊदी अरब सहित 15 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। वे यूक्रेन युद्ध पर चर्चा के लिए अमेरिका जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से भी मिल चुके हैं। इससे एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंटों की प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं।

लोकतंत्र में टकराव नहीं, संवाद ही समाधान ।

डॉ घनश्याम बादल

देश की राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर हुए धरना-प्रदर्शन, उस दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज, उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास की ओर किए गए विरोध मार्च तथा उसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशभर में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर आयोजित प्रदर्शनों ने भारतीय राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां लोकतांत्रिक असहमति और राजनीतिक टकराव के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती दिखाई दे रही है। कई शहरों में हुई झड़पें और हिंसक घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब सड़क पर शक्ति प्रदर्शन में बदलती जा रही है।

इतिहास बताता है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता बल्कि संवाद, सहिष्णुता और संस्थाओं के प्रति सम्मान से संचालित होता है। जब विरोध को केवल शक्ति से दबाने और जवाब में प्रतिरोध को और अधिक आक्रामक बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि वर्तमान घटनाक्रम को देखकर अनेक लोगों को वर्ष 1974 का दौर याद आने लगा है।

1974 का भारत भी राजनीतिक असंतोष, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोपों और सरकार तथा विपक्ष के बीच गहरे अविश्वास का दौर था। छात्र आंदोलनों से शुरू हुई असंतुष्टि ने व्यापक जन आंदोलन का रूप लिया। राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना बढ़ा कि अंततः देश ने आपातकाल जैसी असाधारण परिस्थिति का सामना किया। इतिहास कभी स्वयं को हूबहू नहीं दोहराता लेकिन उससे मिलने वाली चेतावनियों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती।

आज का भारत निश्चित रूप से 1974 वाला भारत नहीं है। संस्थाएं अधिक विकसित हैं, मीडिया का स्वरूप बदल चुका है और डिजिटल माध्यमों ने सूचना के प्रवाह को अत्यंत तेज बना दिया है लेकिन यही डिजिटल माध्यम अफवाहों, उत्तेजक संदेशों और राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। परिणामस्वरूप किसी भी राजनीतिक घटना का प्रभाव कुछ ही घंटों में पूरे देश में दिखाई देने लगता है। यदि विरोध-प्रदर्शन लगातार हिंसक रूप लेते हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव सामान्य बात बन जाती है तथा राजनीतिक दल एक-दूसरे के कार्यालयों, सभाओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने लगते हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र को होगा। लोकतंत्र का अर्थ प्रतिद्वंद्वी का अस्तित्व समाप्त करना नहीं, बल्कि उसके विचारों से लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करना है।

सरकार के लिए भी यह स्थिति अनुकूल नहीं कही जा सकती। कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है लेकिन यदि बार-बार बल प्रयोग की तस्वीरें सामने आती हैं तो विपक्ष को सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाने का अवसर मिलता है। दूसरी ओर, यदि हिंसक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता, तो सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर भी प्रश्न उठते हैं। इसलिए सरकार के सामने संतुलित, संयमित और संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाने की चुनौती है।

विपक्ष के लिए भी यह समय आत्ममंथन का है। लोकतांत्रिक विरोध प्रत्येक राजनीतिक दल का अधिकार है किंतु यदि आंदोलन हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति या टकराव में बदल जाए तो उसका नैतिक आधार कमजोर पड़ जाता है। विपक्ष की सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास होता है और वह केवल शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक राजनीति से ही अर्जित किया जा सकता है।

इन सबसे अधिक नुकसान आम नागरिक को उठाना पड़ता है। सड़कें बंद होती हैं, यातायात प्रभावित होता है, व्यापार ठप पड़ता है, दैनिक मजदूरी करने वालों की आय रुक जाती है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है और निवेश का वातावरण भी प्रभावित होता है। राजनीतिक दल अंततः अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं लेकिन आम आदमी को रोजमर्रा की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी ऐसे घटनाक्रमों से प्रभावित हो सकती है। दुनिया भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखती है। यदि लगातार राजनीतिक हिंसा, सड़क संघर्ष और संस्थागत टकराव की तस्वीरें सामने आती हैं, तो विदेशी निवेशकों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक समुदाय के बीच भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता पर अनावश्यक प्रश्न खड़े हो सकते हैं। हालांकि किसी भी लोकतंत्र में विरोध और आंदोलन स्वाभाविक हैं, किंतु उनका शांतिपूर्ण और संवैधानिक होना ही लोकतंत्र की वास्तविक पहचान है। इन परिस्थितियों के मूल कारणों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। राजनीतिक दलों के बीच संवाद का लगभग समाप्त हो जाना, चुनावी राजनीति का अत्यधिक आक्रामक स्वरूप, सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ता वैचारिक ध्रुवीकरण, हर मुद्दे को राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से देखने की प्रवृत्ति तथा सार्वजनिक विमर्श में संयम की कमी ऐसे प्रमुख कारण हैं जिन्होंने वातावरण को अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। जब संसद और विधानसभाओं में संवाद कम होता है, तब सड़कें राजनीतिक संघर्ष का मुख्य मंच बन जाती हैं।

मेरा आकलन है कि भारत अभी भी उस स्थिति से बच सकता है जिसकी आशंका कुछ लोग 1974 से जोड़कर व्यक्त कर रहे हैं। इसके लिए सरकार, विपक्ष, प्रशासन, मीडिया और नागरिक समाज—सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार को असहमति को लोकतांत्रिक अधिकार मानते हुए कानून का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना चाहिए। विपक्ष को शांतिपूर्ण आंदोलनों की परंपरा को मजबूत करना चाहिए। राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को संयम का संदेश देना चाहिए और मीडिया को भी उत्तेजना के बजाय तथ्य और संतुलन को प्राथमिकता देनी चाहिए।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत विरोध नहीं बल्कि विरोध के बीच भी संवाद बनाए रखने की क्षमता है। यदि राजनीतिक मतभेद स्थायी शत्रुता में बदल गए, तो उसका मूल्य केवल सरकार या विपक्ष नहीं, बल्कि पूरा राष्ट्र चुकाएगा। भारत का लोकतंत्र अनेक कठिन दौरों से गुजरकर मजबूत हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहे, क्योंकि अंततः सत्ता बदल सकती है, विपक्ष बदल सकता है, लेकिन राष्ट्र और लोकतंत्र दोनों स्थायी हैं। इन्हें कमजोर करना किसी भी राजनीतिक विजय से कहीं अधिक महंगा साबित हो सकता है।

थर्मल इंजीनियरिंग का नया मंत्र क्लीन एनर्जी, सुरक्षित भविष्य

योगेश कुमार गोयल

थर्मल इंजीनियरिंग के महत्व और योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष 24 जुलाई को 'राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस' मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य थर्मल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना और इसके महत्व को सार्वजनिक स्तर पर उजागर करना है। दरअसल थर्मल इंजीनियरिंग ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा प्रबंधन इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होती है। थर्मल इंजीनियरिंग उन अवस्थाओं के अध्ययन और उपयोग को समझने में सहायक होती है, जहां ऊष्मा, ऊर्जा और उसकी व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। थर्मल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही एक विशेष उप-विषय है, जो ऊष्मा ऊर्जा की गति और स्थानांतरण से संबंधित है। ऊर्जा को दो माध्यमों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है अथवा ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है।

एक थर्मल इंजीनियर का कार्य यांत्रिक प्रणालियों का रखरखाव, निर्माण या मरम्मत करना है, जिसमें ऊर्जा के अन्य रूपों में ऊष्मा हस्तांतरण प्रक्रिया शामिल होती है। थर्मल इंजीनियर विश्लेषण करता है कि यांत्रिक ऊष्मा स्रोत विभिन्न भौतिक और औद्योगिक प्रणालियों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। घरों तथा गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले एयरकंडीशनर तथा रेफ्रिजरेटरों में थर्मल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। थर्मल इंजीनियरिंग के जरिये इंजीनियर ऊष्मा को अलग-अलग माध्यमों में उपयोग करने के अलावा ऊष्मीय ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग वास्तव में बंद या खुले वातावरण में वस्तुओं को गर्म या ठंडा रखने की प्रक्रिया है और थर्मल इंजीनियर ऊष्मीय ऊर्जा को केमिकल, मैकेनिकल या विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें तैयार करते हैं, जिनके जरिये वे ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं।

हमारे घरों या दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली इसी ऊष्मीय ऊर्जा से बनती है और यह बिजली बनाने का काम करते हैं थर्मल पावर स्टेशन। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र या ताप विद्युत केन्द्र के नाम से भी जाने जाने वाले थर्मल पावर स्टेशन ऐसे विद्युत उत्पादन संयंत्र होते हैं, जिनमें प्रमुख टरबाइनें भाप से चलाई जाती हैं और यह भाप कोयला, गैस इत्यादि को जलाकर पानी को गर्म करके प्राप्त की जाती है। पानी गर्म करने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जिससे उच्च दाब पर भाप बनती है और बिजली पैदा करने के लिए इसी भाप से टरबाइनें चलाई जाती हैं। थर्मल पावर स्टेशनों में ऊष्मीय ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है और इसके लिए भाप से चलने वाली टरबाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। भाप बनाने के लिए पानी को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिसके लिए कोयला, सोलर हीट, न्यूक्लियर हीट, कचरा तथा बायो ईंधन उपयोग किया जाता है। दुनिया के कई देशों में अभी भी बिजली पैदा करने के लिए भाप से चलने वाली टरबाइनों का उपयोग किया जाता है किन्तु पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए अब धीरे-धीरे बिजली पैदा करने के लिए सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोतों को ही महत्व दिया जाने लगा है। भारत में इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हजारों मेगावाट क्षमता की कुछ अत्याधुनिक मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू भी की गई हैं। हजारों मेगावाट के कुछ सोलर प्लांट पहले से ही ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे भी रहे हैं। दरअसल थर्मल पावर स्टेशनों में भाप पैदा करने के लिए कोयला जलाने से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचती है क्योंकि इस प्रक्रिया में निकलने वाली हानिकारक गैसें हवा में मिलकर पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित करती हैं, साथ ही कोयला या अपशिष्ट जलाने के बाद बचने वाले अवशेषों के निबटारे की भी बड़ी चुनौती मौजूद रहती है।

हालांकि भारत में थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली पैदा करने के लिए कोयले के अलावा ऊर्जा के अन्य स्रोतों का भी इस्तेमाल किया जाता है किन्तु अधिकांश बिजली कोयले के इस्तेमाल से ही पैदा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोयले को जलाया जाना और इससे होने वाली गर्मी, पारे के प्रदूषण का मुख्य कारण है। विश्वभर में करीब चालीस फीसदी बिजली कोयले से प्राप्त होती है जबकि भारत में करीब साठ फीसदी बिजली कोयले से, सोलह फीसदी अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बायो गैस से, चौदह फीसदी पानी से, आठ फीसदी गैस से, 1.8 फीसदी न्यूक्लियर ऊर्जा से तथा 0.3 फीसदी डीजल से पैदा होती है। वैसे बिजली पैदा करने के लिए भले ही ऊर्जा के किसी भी स्रोत का इस्तेमाल किया जाए, प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट में इसके लिए बॉयलर का इस्तेमाल होता है, जिसमें ईंधन को जलाकर ऊष्मीय ऊर्जा पैदा की जाती है, जिससे पानी को गर्म कर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को चलाने में इस्तेमाल होती है। वायु प्रदूषण आज दुनियाभर में एक बड़े स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर रहा है और इस समस्या के लिए थर्मल पावर प्लांटों से निकलने वाला उत्सर्जन भी एक बड़ा कारण है। इस समस्या से निपटने के लिए एक दशक से भी अधिक समय से उत्सर्जन मानकों को पूरा करने और नए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को रोककर अक्षय ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।

गोलगप्पों के बहाने

डॉ. शैलेश शुक्ला

हमारे देश में शोध करने के लिए जेएनयू या डीयू जाने की कोई जरूरत नहीं है। असली रिसर्च तो मोहल्ले के उस चौराहे पर होती है जहां एक तरफ नगर निगम का बारहमासी नाला अपनी पूरी सुगन्ध के साथ बहता है और दूसरी तरफ से धूल के बवंडर आते-जाते वीआईपी लोगों का स्वागत करते हैं। इसी दिव्य संगम के बीचों बीच खड़े होते हैं हमारे गोलगप्पा उस्ताद जिन्हें हम प्यार से फुचका साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। गौर से देखिए तो इस दुकान का पूरा भूगोल ही मोक्ष की राह दिखाता है। नाले से आती उस चिर-परिचित महक को लोग ऐसे नजरअंदाज करते हैं मानो वह कोई वीआईपी बदबू न होकर सीधे स्वर्ग से उतरी पारिजात की खुशबू हो। लोग वहां जाकर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे किसी दिव्य संत के दरबार में मुक्ति की भीख मांग रहे हों। अपनी स्टील की छोटी सी कटोरी को दोनों हाथों से ऐसे थामते हैं जैसे उसमें गंगाजल अमृत बनकर गिरने वाला हो। उस्ताद अपने अंगूठे से उस उबले हुए आलू को कसमसाते हैं और फिर उसे तीखे पानी के गहरे समंदर में डुबोकर जब बाहर निकालते हैं तो लाइन में खड़े हर इंसान की लार टपकने लगती है। वहां खड़ा हर व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भूलकर बस इसी जुगाड़ में रहता है कि अगला नंबर उसका ही हो।

इस अद्भुत दरबार का पहला नियम है कि आपको अपनी जीभ के साथ-साथ अपने आत्मसम्मान को भी दांव पर लगाना पड़ता है। एक दिन रमेश बाबू अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वहां पहुंचे और बोले ₹भैया जरा हाइजीनिक तरीके से खिलाना।₹ उस्ताद ने उन्हें पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक ऐसे घूरकर देखा जैसे किसी ने चांद पर थूकने की हिमाकत कर दी हो। उस्ताद ने अपनी मैली सी गंजी के कोने से हाथ पोंछा और कड़क आवाज में बोले साहब यह स्वाद तो इसी नाले की हवा और चौराहे की धूल से आता है। अगर ज्यादा फिल्टर चाहिए तो सामने वाले मॉल में जाकर प्लास्टिक का गोलगप्पा चबाइए। रमेश बाबू की पत्नी ने तुरंत उनके कुर्ते को खींचकर फुसफुसाया अरे तुम चुप रहो ना यार। भैया की बात एकदम सही है। तुम तो बस खिलाओ भैया। जरा तीखा ज्यादा रखना। इसके बाद तो जो नजारा शुरू हुआ वह किसी शास्त्रीय नृत्य से कम नहीं था। जैसे ही तीखे पानी से लबालब भरा गोलगप्पा रमेश बाबू के सामने आया उन्होंने अपने मुंह को किसी अजगर की तरह इतना बड़ा खोला कि लगा पूरा चौराहा ही अंदर समा जाएगा। आंखों से आंसू बह रहे थे कान से धुआं निकल रहा था पर मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी आहा भैया क्या बात है मजा आ गया।वहां खड़े हर ग्राहक की शक्ल गोलगप्पा खाते समय देखने लायक होती है। कोई अपनी आंखें बंद करके समाधि में चला जाता है तो कोई आसमान की तरफ देखकर भगवान को धन्यवाद देता है। सबसे ज्यादा रोमांच तो तब होता है जब प्लेट खत्म होने की कगार पर पहुंचती है। यह वह समय होता है जब अच्छे-भले रईस लोग भी एक सूखी पापड़ी के लिए फकीर बन जाते हैं। कटोरी को उस्ताद के ठीक नाक के नीचे ले जाकर ऐसे तानते हैं मानो वह कोई टैक्स वसूल रहे हों। एक मैडम ने तो हद ही कर दी।

उन्होंने मुझे जबरदस्ती किस किया, थप्पड़ मारा और गाली दी ...

इस एक्ट्रेस ने करण कुंद्रा पर लगाए गंभीर आरोप

टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता करण कुंद्रा और अभिनेत्री सान्वी तलवार ने साल 2015 में प्रसारित हुए सीरियल ये कहा आ गए हम में साथ काम किया था। उस समय दोनों के बीच हुए कथित विवाद ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता करण कुंद्रा और अभिनेत्री सान्वी तलवार ने साल 2015 में प्रसारित हुए सीरियल ये कहा आ गए हम में साथ काम किया था। उस समय दोनों के बीच हुए कथित विवाद ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। खबरें थीं कि शूटिंग के दौरान दोनों के बाच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला थप्पड़ मारने तक पहुंच गया। अब कई वर्षों बाद सान्वी तलवार ने इस पूरे विवाद पर खुलकर बात की है और बताया है कि उस दिन सेट पर वास्तव में क्या हुआ था ?

सान्वी तलवार ने करण पर लगाए गंभीर आरोप

हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस सान्वी तलवार ने खुलासा किया कि वह शूटिंग के दौरान करण कुंद्रा से केवल काम तक ही सीमित रहती थीं और ज्यादा बातचीत नहीं करती थीं। उनके मुताबिक, करण को उनका यह व्यवहार पसंद नहीं था। सान्वी ने आरोप लगाया कि इसी वजह से करण और शो के डायरेक्टर उन्हें परेशान करने लगे। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी बताया गया था कि शो में उनकी जगह किसी दूसरी अभिनेत्री को लेने की तैयारी चल रही है।

करण कुंद्रा ने एक्ट्रेस किया था जबरदस्ती किस

सान्वी तलवार ने इंटरव्यू में शो के किसिंग सीन से जुड़े विवाद पर भी खुलकर बात की। उन्होंने दावा किया कि एक सीन की शूटिंग के दौरान करण कुंद्रा ने डायरेक्टर के एक्शन बोलने या निर्देश देने से पहले ही उन्हें किस कर लिया। सान्वी के मुताबिक, यह पूरी तरह अनुचित था क्योंकि उस समय ऐसा करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था।

इसके बाद एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि इस हरकत से वह बेहद नाराज हो गईं और उन्होंने तुरंत थप्पड़ मार दिया। सान्वी के अनुसार, थप्पड़ पड़ने के बाद करण ने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बिना कुछ कहे वहां से चले गए।

इसके बाद करण ने मारा थप्पड़

इसके बाद सान्वी तलवार ने आगे आरोप लगाया की कुछ देर बाद करण कुंद्रा लौटे और सभी के सामने उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। उनके मुताबिक, थप्पड़ इतनी जोर से था कि वो नीचे गिर गईं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया।

बात यहां खत्म नहीं हुई इसका बाद करण ने एक्ट्रेस को बहुत बुरा भला बोला और गालियां भी निकालीं। मेरे साथ-साथ मेरे माता-पिता के लिए भी अपमानजनक बातें कहीं। इस घटना से आहत होकर वह तुरंत शूटिंग छोड़कर अपने घर चली गईं और फैसला कर लिया कि अब वह इस शो में काम नहीं करेंगी।

हालांकि, बाद में प्रोड्यूसर एकता कपूर ने उनसे बातचीत की और करण कुंद्रा की ओर से माफ़ी मांगते हुए शो बीच में न छोड़ने की अपील की। सान्वी ने बताया कि एकता कपूर के समझाने पर उन्होंने अपना फैसला बदला और दोबारा शो की शूटिंग शुरू कर दी।

कौन है इंडिया का सबसे पॉपुलर एक्टर ?

साउथ का ये सुपरस्टार लगातार दे रहा शाहरुख-समलान को टक्कर

ऑरमैक्स टॉप 10 लिस्ट का फैंस को काफी इंतजार होता है। उन्हें ये जानने की एक्साइटमेंट होती है कि उनके फेवरेट हीरो इस बार किस नंबर पर हैं। ऐसे में अब फैंस का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट जून 2026 की है। ये लिस्ट काफी दिलचस्प है। साउथ के स्टार्स को शाहरुख खान ने जमकर टक्कर दी है। तो चलिए जानते हैं मई मंथ में पर किस एक्टर ने नंबर 1 पर जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

प्रभास

ऑरमैक्स टॉप 10 मीडिया की रिपोर्ट में बीते कई महीनों से प्रभास अपनी जगह से हिले नहीं हैं। नंबर 1 पर कोई और नहीं, बल्कि बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार यानी प्रभास हैं। इस मंथ भी प्रभास नंबर वन पर हैं।

शाहरुख खान

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।

थलापति विजय

'जन नायकन' के लिए के बीच थलापति विजय लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। ये भी लगातार इस लिस्ट में टॉप 5 में बने हुए हैं।

अल्लू अर्जुन

'पुष्पा 2' एक्टर अल्लू अर्जुन इस बार चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं।

राम चरण

आरआरआर फेम रामचरण इस लिस्ट में इस बार पांचवे पर है। पिछले महीने सातवें पर थे। रामचरण साउथ के सुपरस्टार हैं। अपने करियर में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।

महेश बाबू

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू लिस्ट में छठे नंबर पर हैं।

सूर्या

एक्टर सूर्या इस लिस्ट में सातवें पर हैं।

सलमान खान

बॉलीवुड दबंग सलमान खान इस बार ऊपर आ गए हैं। लिस्ट में सलमान आठवें पर हैं। एक्टर हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं। अपने करियर में सलमान ने कई हिट फिल्में दी हैं।

अक्षय कुमार

अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस लिस्ट में अक्षय 9वें नंबर पर हैं।

रणवीर सिंह

'धुरंधर' फिल्म से पूरा बॉक्स ऑफिस हिलाने वाले एक्टर रणवीर सिंह ने भी ऑरमैक्स की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। रणवीर से 10वें नंबर पर आ गए हैं।

आखिरी फिल्म के लिए विजय ने वसूली मोटी फीस

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में लग गई है और बड़ी संख्या में इसे देखने दर्शक पहुंचे हैं। इसे विजय की बतौर एक्टर आखिरी फिल्म कहा जा रहा है, क्योंकि अब वे पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने तगड़ी फीस वसूली है। जानिए विजय और बाकी स्टारकास्ट को क्या मिला?

थलापति विजय की फीस कितनी?

इस फिल्म में थलापति विजय मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के जरिए उन्होंने छप्परफाड़ कमाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय को इस फिल्म के लिए करीब 220 करोड़ से 275 करोड़ रुपये फीस दी गई है। अगर रिपोर्ट्स में दिए गए फीस के आंकड़ों पर भरोसा करें तो विजय

भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए हैं। फीस की यह रकम विजय को बिना किसी प्रॉफिट-शेयरिंग मॉडल के पेमेंट के रूप में दी गई है।

निर्देशक को कितने मिले?

फिल्म 'जन नायकन' के निर्देशन की कमान एच विनोद ने संभाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इस फिल्म के लिए 25 करोड़ रुपये फीस दी गई है। कहा जा रहा है कि यह निर्देशक के करियर की अब तक की सबसे बड़ी राशि है।

फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी अनिरुद्ध रविचंदर ने निभाई है। फिल्म के संगीतकार को 13 करोड़ रुपये फीस दी गई है। बता दें कि अनिरुद्ध ने इससे पहले 'लियो' और 'जेलर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का संगीत भी दिया है। वे साउथ के महंगे संगीतकारों में शामिल हैं।

पूजा हेगड़े की फीस इतनी

चर्चित अभिनेत्री पूजा हेगड़े फिल्म में लीड अभिनेत्री के किरदार में हैं। उनकी फीस को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें 6 करोड़ रुपये मिले हैं। बता दें कि तमिल और तेलुगु के अलावा पूजा हेगड़े बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।

बॉबी देओल और अन्य सितारों की फीस

इस फिल्म में बॉबी देओल भी अहम भूमिका में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉबी को पांच से 10 करोड़ रुपये फीस दी गई है। इसके अलावा प्रकाश राज को पांच करोड़ रुपये, प्रियामणि को तीन करोड़ रुपये और गौतम वासुदेव मेनन को तीन करोड़ रुपये फीस दी गई है।

जब मीना कुमारी के घर टेबल टेनिस सिखाने जाते थे कॉमेडियन, देखते ही उनकी बहन पर हार बैठे थे दिल

हिंदी सिनेमा में जब भी शानदार कॉमेडी कलाकारों की बात होती है, तो महमूद का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। अपने बोलने का अंदाज, चेहरे के एक्सप्रेशन और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने करोड़ों लोगों को हंसाया। लेकिन, फिल्मों में बड़ा नाम बनने से पहले महमूद ने कई छोटे काम किए। इन्हीं संघर्ष भरे दिनों में एक ऐसा मोड़ आया, जिसने उनकी निजी जिंदगी को भी बदल दिया। कम लोग जानते हैं कि कभी महमूद को मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के घर टेबल टेनिस सिखाने का काम मिला था, और वहीं से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता मुमताज अली अपने समय के मशहूर अभिनेता थे। घर में फिल्मों का माहौल था, इसलिए बचपन से ही महमूद का झुकाव अभिनय की तरफ था। हालांकि, पिता के कलाकार होने के बावजूद महमूद के लिए सफलता का रास्ता आसान नहीं था। बचपन में ही महमूद ने फिल्मों में कदम रख दिया था। उन्होंने साल 1943 में आई फिल्म 'किस्मत' में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता अशोक कुमार के बचपन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में छोटे-छोटे किरदार किए, लेकिन उन्हें पहचान मिलने में काफी समय लगा।

संघर्ष के दिनों में महमूद ने घर चलाने के लिए कई तरह के काम किए। उन्होंने लोकल ट्रेनों में टॉफियां बेचीं, ड्राइवर की नौकरी की और फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। इसी दौरान उन्हें मीना कुमारी के घर टेबल टेनिस सिखाने का मौका मिला। उस समय महमूद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। मीना कुमारी के घर आने-जाने के दौरान उनकी मुलाकात उनकी बहन मधु से हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच रिश्ता मजबूत हुआ और साल 1953 में महमूद ने मधु से शादी कर ली।

हालांकि, शादी और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ उनका संघर्ष भी जारी रहा। वह लगातार छोटे किरदार करते रहे और अपने लिए एक बड़ी पहचान बनाने की कोशिश करते रहे।

साल 1950 और 60 के दशक में महमूद ने कई फिल्मों में काम किया और धीरे-धीरे दर्शकों के बीच लोकप्रिय होने लगे। फिल्म 'छोटी बहन' ने उनके करियर को नई दिशा दी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 'गुमनाम', 'पड़ोसन', 'बॉम्बे टू गोवा', 'भूत बंगला', 'कुंवारा बाप', 'हमजोली' और 'नौकर' जैसी फिल्मों में उनके किरदारों को खूब पसंद किया गया।

महमूद सिर्फ कॉमेडी कलाकार नहीं थे, बल्कि वह एक अच्छे अभिनेता, निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उन्होंने कई नए कलाकारों को मौका दिया। उन्होंने फिल्म 'बॉम्बे टू गोवा' में अमिताभ बच्चन को मुख्य भूमिका दी। वहीं, उन्होंने फिल्म 'छोटे नवाब' के जरिए आरडी बर्मन को भी शुरुआती मौका दिया।

अपने शानदार अभिनय के लिए महमूद को कई सम्मान मिले। उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया। करियर के आखिरी दौर में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्होंने फिल्मों में काम कम कर दिया। साल 2004 में इलाज के लिए वह अमेरिका गए थे। 23 जुलाई 2004 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में उनका निधन हो गया।

सीजेपी के प्रदर्शन पर इब्राहिम अली खान ने जताई चिंता, छात्रों के समर्थन में बोले- 'शिक्षा के लिए डर का माहौल नहीं होना चाहिए'

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान भले ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत को लेकर चर्चा में रहते हों, लेकिन इस बार वह एक सामाजिक मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने की वजह से सुर्खियों में हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन और छात्रों के विरोध को लेकर इब्राहिम ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

इब्राहिम अली खान ने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ''छात्रों और उनके परिवारों को इस तरह अशांति के बीच फंसा देखना बेहद दुखद है। सिर्फ पढ़ाई जारी रखने या शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध-प्रदर्शन करने के लिए किसी को भी डर या अनिश्चितता का सामना नहीं करना चाहिए।

हमारी अपनी-अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सभी सुरक्षित रहें, सबकी बात शांति से सुनी जाए और बिना किसी और नुकसान के इस स्थिति का समाधान निकले। इस मुश्किल समय से प्रभावित सभी लोगों के लिए मैं हिम्मत की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे का रास्ता सकारात्मक होगा। जय हिंद।'' बॉलीवुड से कई सितारे छात्रों के समर्थन में सामने आए हैं। आलिया भट्ट, सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई कलाकारों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

खुशाली कुमार ने चुनी अलग राह

कंटेंट-ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के बाद फिल्म दुल्हनिया ले आएगी में आएंगी नजर

अभिनेत्री खुशाली कुमार बीते कुछ वर्षों से ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रही हैं, जो मजबूत कहानी और दमदार कंटेंट की वजह से चर्चा में रहे हैं। कमर्शियल फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने इंडिपेंडेंट फिल्मों और नए फिल्मकारों के साथ भी काम करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। अलग-अलग विषयों पर आधारित फिल्मों का चयन उनकी बदलती फिल्मी सोच को दर्शाता है।

'सपने Vs एवरीवन 2' में अभिनय को मिली सराहना

हाल ही में खुशाली कुमार चर्चित ओटीटी सीरीज 'सपने Vs एवरीवन 2' में नजर आईं। इस सीरीज में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने पसंद किया। उनके किरदार ने यह साबित किया कि वह सिर्फ पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना पसंद करती हैं जिनमें अभिनय की पर्याप्त गुंजाइश हो।

अब 'दुल्हनिया ले आएगी' से करेंगी कॉमेडी जॉनर में एंट्री

खुशाली कुमार अब अपनी नई फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन आकाश आदित्य लांबा ने किया है। फिल्म का निर्माण एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले किया गया है, जो कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा पर फोकस करता है।

महेश मांजरेकर और पियूष मिश्रा के साथ आएंगी नजर

फिल्म में खुशाली कुमार के साथ दिग्गज अभिनेता महेश मांजरेकर और पियूष मिश्रा भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। अनुभवी कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करना खुशाली के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिल्म की स्टारकास्ट और इसकी कहानी को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही उत्सुकता बनी हुई है।

हर जॉनर में खुद को कर रही हैं साबित

खुशाली कुमार ने अब तक अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में काम किया है। उन्होंने आर. माधवन के साथ थ्रिलर फिल्म 'धोखाः राउंड डी कॉर्नर', प्रतीक गांधी के साथ सामाजिक विषय पर आधारित 'डेढ़ बीघा ज़मीन', ओटीटी सीरीज 'सपने Vs एवरीवन 2' और अब कॉमेडी फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' के जरिए अपने अभिनय का अलग-अलग अंदाज पेश किया है।

24 जुलाई यानी आज को सिनेमाघरों में होगी रिलीज

खुशाली कुमार की आगामी फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' आज सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में काम करने की दिशा में यह फिल्म उनके करियर का एक और अहम पड़ाव मानी जा रही है। दर्शकों को उम्मीद है कि इस बार खुशाली कॉमेडी अंदाज में भी अपनी छाप छोड़ने में सफल रहेंगी।

नीट पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन सही लेकिन उसे राजनीतिक रंग न दें : सलमान खान

नीट पेपर लीक के आरोपों और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर देशभर में बहस जारी है। अब इस मुद्दे पर मनोरंजन जगत की कई हस्तियां भी खुलकर अपनी राय रख रही हैं। इसी बीच बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी पहली बार इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसका पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पिछले कई दिनों से लोग सवाल उठा रहे थे कि आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सलमान खान आखिर चुप क्यों हैं। अब अभिनेता ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक लंबा पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले पर विस्तार से अपनी बात रखी है।

सलमान खान ने पोस्ट करते हुए लिखा की- यह एक बेहद शांतिपूर्ण आंदोलन था। यह देखकर बहुत दुःख हुआ कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा। मेरी संवेदनाएं उन सभी छात्रों और उनके परिवारों के साथ हैं जो इस दौरान प्रभावित हुए। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है और मुझे ख़ुशी है कि हमारे देश के बाचे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट होकर खड़े हैं, उनके माता-पिता के भी उनका पूरा साथ दिया।

मैं छात्रों के इस कदम की दिल से सराहना करता हूं। उन्होंने जिस समर्पण, ईमानदारी और पढाई के पार्टी लगन का परिचय दिया, वह सराहनीय है। बेहतर भविष्य और शिक्षित भारत के लिए किया गया यह आंदोलन सही दिशा में उठाया गया कदम है, बशर्ते यह शांतिपूर्ण रहे। छात्रों ने साहस और समझदारी दिखाई है। शिक्षा के प्रति उनका जुनून और समर्पण आने वाले समय में भारत को गर्व महसूस कराएगा।

यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इस आंदोलन का श्रेय केवल देश के छात्रों को मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए उनका पूरा सहयोग करेगी। यह सभी के लिए फायदे का सौदा होगा। मैं सकारात्मक फैसले की उम्मीद करता हूं। भगवान उन सभी का भला करें जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

शिक्षा ही अगला ट्रेंड और फैशन बनना चाहिए। हर साल यह और लोकप्रिय हो, ताकि दुनिया भर से लोग भारत पढ़ने आएं और हमारा देश एक वैश्विक एजुकेशन हब बन सके।

छात्रों के समर्थन में उतरीं आलिया भट्ट

कमल हासन बोले-बच्चों को जवाब की जगह मिल रही हैं लाठियां

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट देश में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर अपनी आवाज उठाई है। वहीं अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों की परेशानियों को समय रहते सुना जाना चाहिए था। दरअसल, देश में परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसी बीच कई छात्र संगठन और समर्थक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब मनोरंजन जगत की कई हस्तियां भी प्रतिक्रिया दे रही हैं।

आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट साझा करते हुए लिखा, "पिछले कुछ दिनों ने मेरा दिल कई बार तोड़ा और फिर उम्मीद के साथ उसे जोड़ा। हर उस छात्र के पीछे एक सपना, परिवार की उम्मीद, वर्षों की मेहनत और त्याग की कहानी छिपी होती है। छात्र सिर्फ अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वे उन लोगों की उम्मीदों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने उनका साथ दिया है। छात्रों का साहस समाज के सामने यह सवाल रखता है कि क्या हम वास्तव में उन लोगों की बात सुन रहे हैं, जो देश का भविष्य संभालने वाले हैं।"

वहीं, अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाए। कमल हासन ने कहा कि जब बच्चों की परेशानियों को समय रहते नहीं सुना जाता, तो हालात गंभीर हो जाते हैं।

उन्होंने लिखा, "हमें तब सुनना चाहिए था, जब एक बच्चा रोया था लेकिन हमने तब तक इंतजार किया, जब तक बहुत सारे बच्चों की आवाज खामोश नहीं हो गई।

कमल हासन ने शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसी व्यवस्था, जहां पढ़ाई और सीखने की जगह सिर्फ कोचिंग का दबाव बढ़ जाए, जहां जिज्ञासा की जगह डर पैदा हो और जहां योग्यता की जगह गलत तरीके आगे आने लगें, वह व्यवस्था कमजोर हो जाती है। जब बच्चों को जवाब देने की जगह बैरिकेड और लाठियां मिलती हैं तो यह देश की विफलता है।

कमल हासन ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की अपील भी की। उन्होंने लिखा, वांगचुक जी, आने वाले समय के लिए देश को आपके विवेक की जरूरत होगी। कृपया अपना अनशन खत्म करें। भारत के बच्चों, आप हमारे बीच के सबसे अच्छे इंसान हैं। आपने अपना कर्तव्य निभाया है। अब समय है कि देश आपके लिए अपना कर्तव्य निभाए। आपके सपने हमेशा हमारी कमियों से बड़े होने चाहिए।

संघर्ष, लगातार मिले रिजैक्शन व मां की सीख से सफलता मिली

शरवरी वाघ

कुछ साल पहले तक शरवरी वाघ उन चेहरों में शामिल थी, जो हर ऑडिशन के बाद अगले मौके का इंतजार करते थे। आज वही शरवरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित यंग एक्ट्रेसेस में गिनी जा रही है । 'मुंज्या ' की जबरदस्त सफलता ने उसके करियर को नई उड़ान दी और इस साल वह 'अल्फा' और 'मैं वापस आऊंगा' जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आ चुकी है लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में शरवरी ने अपने संघर्ष, लगातार मिले रिजैक्शन, मां की सीख और सफलता के बाद बदले करियर पर खुलकर बात की ।

हर ऑडिशन मेरे लिए एक नई उम्मीद होता था

शरवरी ने माना कि इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उसने बताया कि शुरुआती पांच साल उसके करियर के सबसे कठिन दौर थे ।

उसने कहा, ₹मैं लगभग हर दिन ऑडिशन देने जाती थी. लेकिन ज्यादातर जगहों से सिर्फ रिजैक्शन ही मिलता था। कई बार ऐसा लगता था जैसे रोज किसी परीक्षा में फेल हो रही हूं। लेकिन अगले ही दिन फिर उसी भरोसे के साथ ऑडिशन देती थी कि शायद यही मेरी फिल्म होगी ।

उसके अनुसार सही तरह का काम मिलने का इंतजार सबसे मुश्किल था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी।

मैं लगभग हर दिन ऑडिशन देने जाती थी, लेकिन ज्यादातर जगहों से सिर्फ रिजैक्शन ही मिलता था

मुंबई में घर होना मेरी सबसे बड़ी ताकत थी

शरवरी का मानना है कि हर कलाकार का संघर्ष अलग होता है। उसने स्वीकार किया कि मुंबई में परिवार का साथ और अपना घर होना उसके लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ।

उसने कहा कि इस वजह से वह जल्दबाजी में कोई भी प्रोजैक्ट स्वीकार करने के दबाव में नहीं थीं। वह सही स्क्रिप्ट और बेहतर मौके का इंतजार कर सकी, जिसे वह अपने करियर की सबसे बड़ा 'प्रिविलेज' मानती है।

मां की एक सीख ने बदल दिया नजरिया

शरवरी ने यह भी बताया कि वह अपने संघर्ष की कहानी को बार-बार सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं दोहराती ।

उसने कहा कि बचपन में उसकी मां ने उसे एक ऐसी बात सिखाई, जिसने जिंदगी को देखने का उसका नजरिया बदल दिया। उसने कहा, “मां हमेशा कहती थीं कि कभी खुद को विक्टिम मत बनने देना । शायद यही वजह है कि मैंने मुश्किल वक्त को भी शिकायत की तरह नहीं देखा । मैंने हमेशा उसे सीख और तैयारी का हिस्सा माना । ₹

शरवरी का कहना है कि यह सीख आज भी उसे हर चुनौती का सामना सकारात्मक सोच के साथ करने की ताकत देती है।

'शरवरी वाघ'

जहां लौटकर मिलता है सुकून ....

बॉलीवुड की चकाचौंध के बीच शरवरी के दिल के सबसे करीब आज भी उसका पैतृक घर है।

उसने बताया कि महाराष्ट्र के मोरगांव स्थित उसका लगभग 100 साल पुराना पुश्तैनी घर उसके लिए किसी भावनात्मक विरासत से कम नहीं है । उसने कहा, ₹हम हर साल गणपति पर वहां जरूर जाते हैं। उस पुराने वाड़े में मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है। वहां दादा परदादा की तस्वीरें, उनकी डिग्रियां और पुराने दौर की यादें आज भी संभालकर रखी गई हैं। कई बार सोचती हूं कि काश समय में पीछे जाकर देख पाती कि उस दौर में यह घर कैसा दिखता था और लोग वहां कैसे रहते थे।

फोटोग्राफर के मजाक पर फूटा जरीन खान का गुस्सा

जरीन खान का एक वीडियो मुंबई में एक इवेंट के दौरान टोकती हुई दिख रही है। से कहा कि वह ' अपनी भाषा पर नी दी कि वह ऐसा बर्ताव बर्दाश्त

दोन एक कपड़ों के ब्रांड के

लॉन्च थी । वह ब्रांड के डैनिम जम्पसूट साथ फोटोग्राफरों के लिए पोज भी एक फोटोग्राफर ने मजाक में ड्रैस ट्राई करके दिखाइए कहते ही जरीन नाराज हो गई। जरीन तौर पर जवाब दिया, जरीन यहीं नहीं रुकी। उसने टोग्राफर्स को सख्त लहजे में कहा, रे साथ ऐसी फालतू बातें मत किया करो, क्योंकि मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हद में रहकर करना, सब के सब। यह जवाब सुनकर वहां लोग भी हैरान रह गए। चेहरे पर गुस्सा साफ दिख और उसने मौके पर ही उस घटिया आपत्ति जता दी थी।

जरीन का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उसके सपोर्ट में उतर आए। एक यूजर ने लिखा- जरीन बिल्कुल सही हैं। दूसरे ने कहा- फोटोग्राफर इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? कोई कैमरा के सामने कपड़े बदलेगा। वहीं एक और ने क्यों लिखा- उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। किसी को भी अपनी हद नहीं पार करनी चाहिए।

जरीन की तारीफ यूजर्स इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उसने फोटोग्राफरों को बिना कोई ड्रामा किए सख्त लहजे में समझा दिया। यूजर्स ने लिखा- एक लाइन में अपनी नाराजगी जाहिर की जा सकती है ये जरीन से सीखना चाहिए।

मुझे अटैंशन पसंद है: अनन्या पांडे

समय के साथ उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। अब वह हर जगह दिखने या हर इवैंट का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करती

अनन्या पांडे अक्सर अपनी फिल्मों, फैशन और सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर चर्चा में रहती है लेकिन इस बार उसने अपनी निजी जिंदगी, खूबसूरती, लाइमलाइट और बदलती सोच को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्होंने उसके फैंस को भी हैरान कर दिया है। अनन्या ने माना कि पहले उसे हर जगह मौजूद रहने की आदत थी, लेकिन अब वह खुद के लिए समय निकालना सीख चुकी है। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि अब उसे 'फेक पार्टी कल्चर' बिल्कुल पसंद नहीं आता ।

उसकी बातचीत से साफ है कि ग्लैमर की दुनिया में रहते हुए भी अनन्या अब अपनी जिंदगी को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रही है । आइए जानते हैं आखिर उसने क्या-क्या कहा ।

अनन्या ने सबसे पहले उस बात को स्वीकार किया, जिसे शायद कई सितारे खुलकर कहने से बचते हैं। उसने हंसते हुए कहा कि बचपन में उसके माता-पिता उसे मजाक में ' अटैंशन प्रॉब्लम्स' कहते थे, क्योंकि उसे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना अच्छा लगता था । उसने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे अटेंशन पसंद है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लाइफस्टाइल की ओर था।

मैं जैसी हूं, वैसी ही दिखना चाहती हूं

आजकल सोशल मीडिया फिल्टर्स और परफैक्ट लुक्स का दौर है, लेकिन अनन्या का कहना है कि उसे अपनी असली त्वचा और असली चेहरा ज्यादा पसंद है।

उसने कहा कि वह भारी मेकअप और पूरी तरह चेहरा छिपा देने वाले फाउंडेशन से दूरी बना रही है। उसे अच्छा लगता है जब उसकी नैचुरल स्किन और उसकी बनावट भी दिखाई दे । अनन्या का मानना है कि हर छोटी कमी को छिपाने की जरूरत नहीं होती बल्कि इंसान की पहचान उसी की अलग- अलग खूबियों और कमियों से बनती है।

बहुत ज्यादा परफैक्ट दिखना सबसे थकाऊ खूबसूरती है अनन्या ने खूबसूरती को लेकर भी एक अलग सोच सामने रखी। उसके अनुसार आज हर कोई एक जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन असली खूबसूरती वही है, जिसमें इंसान अपनी अलग पहचान बनाए रखे है उसने कहा कि उसे थोड़ा बिखरे बाल, हल्की-सी अव्यवस्था और नैचुरल लुक पसंद है । उसका कहना कि 'बहुत ज्यादा परफैक्ट दिखना खूबसूरती का सबसे थकाऊ रूप है।' यानी उसके लिए सुंदरता का मतलब बिना किसी फिल्टर के खुद को स्वीकार करना है ।

सैट पर नहीं, असल जिंदगी में घबराती है

अनन्या हाल ही में टैनिस का ग्रैंड स्लैम . टूर्नामैंट 'विम्बलडन' देखने लंदन पहुंची हालांकि, उसने यह भी माना कि समय के साथ अटैंशन को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। अब वह हर जगह दिखने या हर इवैंट का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करती।

'फेक पार्टी कल्चर' से मैं पूरी तरह ऊब चुकी हूं यही नहीं, अनन्या ने बॉलीवुड के पार्टी कल्चर पर भी बिना नाम लिए अपनी राय रखी। उसने कहा कि अब उसे वह पार्टी कल्चर पसंद नहीं आता, जहां रिश्ते सिर्फ दिखावे या मतलब के लिए बनाए जाते हैं। उसके अनुसार, ऐसे माहौल में असली जुड़ाव कम और औपचारिकता ज्यादा होती है।

उसके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अनन्या का इशारा फिल्म इंडस्ट्री की चमक-दमक वाली थी

दिलचस्प बात यह है कि कैमरे के सामने बिल्कुल सहज नजर आने वाली अनन्या ने माना कि उसे शूटिंग सैट पर कभी घबराहट नहीं होती । उसने कहा कि फिल्म का सैट उसके लिए एक सुरक्षित जगह की तरह है। वहां उसे पता होता है कि क्या करना है और कैसे करना है लेकिन असली परेशानी तब होती है, जब वह सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करती है ।

अनन्या ने बताया कि वह पहली बार अकेले फिल्म देखने जाने की योजना बना रही थी और इस बात को लेकर काफी नर्वस थी । उसने हंसते हुए कहा कि जब कोई उसे निर्देश नहीं देता, तब उसे समझ नहीं आता कि हाथ कहां रखे, कैसे चले या कैसे व्यवहार करे । उसकी यह बात सुनकर कई लोग हैरान रह गए, क्योंकि पर्दे पर आत्मविश्वास से भरी दिखने वाली अनन्या निजी जिंदगी में भी इतनी सहज नहीं है ।

सीख लिया है नफरत बर्दाश्त करना : 'प्राजक्ता'

सोशल मीडिया पर 'मोस्टलीसेन' के नाम से पहचान बनाने वाली प्राजक्ता कोली की लोकप्रियता अब सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रही।

वै सीरीज से लेकर फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने के बाद वह करियर का एक नया अध्याय शुरू करने जा रही है। हालांकि, उसके लिए यह सफर आसान नहीं रहा ।

उसका कहना है कि एक कंटैंट क्रिएटर और अब एक अभिनेत्री के तौर पर अपने 11 साल के सफर में उसने नैगेटिविटी और बिना वजह की नफरत को बर्दाश्त करना सीख लिया है। उसने कहा, ₹मुझे बिना वजह की नफरत की आदत हो गई है, इसलिए अब यह मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं करती।

उसने आगे कहा, “मैं 11 सालों से क्रिएटर हूं और अब मैं मोटी चमड़ी की हो गई हूं। मैंने इतने लंबे समय से सब कुछ सबके सामने रखा है लेकिन इसके बावजूद, आलोचना मेरे लिए हमेशा बहुत जरूरी रही है । अब, मैं जो करती हूं उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्रिएटर बनना सीखा या मैं फिल्म स्कूल गई और एक्टिंग करना सीखा। मैंने जो कुछ भी सीखा है, वह काम करते-करते सीखा है, इसी वजह से मैं उतनी कुशलता से काम नहीं कर पाती ।

फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़

यूएस नागरिकों से ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार

लखनऊ, 23 जुलाई (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश पुलिस के ' ऑपरेशन सीवाई-वज्र ' के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में राजधानी लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कमिश्नरेट पुलिस ने विभूतिखंड इलाके में संचालित एक हाईटेक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड समेत चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह गिरोह अमेरिकी नागरिकों को फर्जी एप्पल कस्टमर सपोर्ट और अमेरिकी जांच एजेंसियों के अधिकारी बनकर डराता था और उनसे हजारों डॉलर की ठगी करता था।

डीसीपी पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा के मुताबिक, 22 जुलाई की रात मुखबिर की सूचना पर पूर्वी जोन की क्राइम टीम, सर्विलांस टीम और विभूतिखंड थाना पुलिस ने साइबर हाइट बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 420ए में छापेमारी की। यहां एक हाईटेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर संचालित होता मिला, जहां से अमेरिकी नागरिकों को निशाना

लखनऊ में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़

बनाया जा रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने एप्पल कस्टमर सपोर्ट के नाम से एक फर्जी वेबसाइट तैयार कर उसे गूगल विज्ञापन के जरिए प्रमोट किया था। जब कोई अमेरिकी नागरिक टोल-फ्री नंबर पर कॉल करता, तो वीओआईपी तकनीक के माध्यम से कॉल सीधे लखनऊ स्थित कॉल सेंटर पर पहुंचती थी। यहां एजेंट पहले पीड़ित का डेटा सत्यापित करते और फिर कॉल वरिष्ठ सदस्यों को ट्रांसफर कर दी जाती थी। गिरोह के सदस्य खुद को अमेरिकी फ़ेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) या यूएस सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बताकर पीड़ितों को कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी और जेल भेजने का डर दिखाते थे। भयभीत हुए लोगों से गिफ्ट कार्ड, सोना या नकद के रूप में रकम वसूली जाती थी। इसके बाद अमेरिका में मौजूद नेटवर्क के जरिए हवाला माध्यम से रकम भारत भेजी जाती थी।

पुलिस के अनुसार, गिरोह का मास्टरमाइंड प्रतापगढ़ निवासी सूरज त्रिपाठी है, जिसने 2012-13 में अहमदाबाद में कॉल सेंटर का काम सीखा था। उसके साथ उसके मामा राहुल त्रिपाठी, बुआ का बेटा विवेक पांडेय और मुंबई निवासी तकनीकी विशेषज्ञ आकाश अरुण दत्ता उर्फ रिक्की इस नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। पुलिस के अनुसार यह एक पारिवारिक साइबर सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 31 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 2 वाई-फाई राउटर और 18.50 लाख रुपये नकद बरामद किए। साथ ही मास्टरमाइंड की हुंडई वरना कार भी जब्त की गई। मौके पर 35 वर्कस्टेशनों पर कॉलिंग एजेंट काम करते मिले, जिन्हें उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड, मध्य प्रदेश समेत नेपाल से भी भर्ती किया गया था। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कॉल सेंटर में काम करने वाले एजेंटों को साइबर ठगी की पूरी जानकारी थी या वे केवल कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। सभी मुख्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सीतामढ़ी का चोर रांची में करोड़ों की चोरी का आरोपी

चोरी के पैसों से लोगों की करता है मदद सीएम-राज्यपाल को भी बना चुका है निशाना

रांची, 23 जुलाई (एजेंसियां)। रांची के कारोबारी सह समाजसेवी अखिलेश पांडेय के अशोक नगर स्थित आवास पर करोड़ों रुपए की चोरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी को इस मामले के मास्टरमाइंड को चिह्नित कर लिया है।

इस घटना को बिहार के सीतामढ़ी निवासी मो. इरफान उर्फ उजाले ने अंजाम दिया है। पुलिस ने इरफान की पत्नी और प्रेमिका सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर 20 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं।

बताया जाता है कि इरफान पर दिल्ली, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और बिहार सहित 20 राज्यों में 100 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि इरफान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्दी ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा।

पूर्व प्रधान के साथ मारपीट

जूतों की माला पहनाकर अपमानित करने का आरोप, 10 नामजद समेत 14 पर एफआईआर

जालौन, 23 जुलाई (एजेंसियां)। जालौन में पूर्व प्रधान के साथ मारपीट, लूटपाट और सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि पहले उसे रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटा गया, फिर उसका मोबाइल, सोने की चेन और अंगूठी छीन ली गई। इसके बाद उसे फार्महाउस ले जाकर दोबारा मारपीट की गई, जूतों की माला पहनाई गई और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई। पुलिस ने 10 नामजद और 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पीड़ित वीरसिंह के अनुसार, 19 जुलाई को वह एक परिचित महिला के घर शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। वहां कुछ समय रुकने के बाद शाम करीब 7:30 बजे वह अपने गांव लौट रहे थे।

आरोप है कि रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने तीन-चार चारपहिया वाहनों और चार-पांच मोटरसाइकिलों से उनका रास्ता रोक लिया।

पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उसे बाइक से नीचे गिराकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि हमलावरों में चंद्रपाल, श्याम सिंह, बबलू राणा, श्रीकांत उर्फ सल्लू सहित अन्य लोग शामिल थे। मारपीट के दौरान उसका मोबाइल फोन, गले की सोने की चेन, अंगूठी और नकदी भी छीन ली गई।

पीड़ित ने घटनाक्रम बताते हुए कहा कि इसके बाद उसे जबरन एक फार्महाउस (कालपी क्षेत्र) ले जाया गया, जहां उसके साथ फिर से मारपीट की गई। आरोप है कि उसके चेहरे पर चप्पलों से प्रहार किए गए, गले में जूतों की माला पहनाकर उसका अपमान किया गया और पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

पूर्व प्रधान ने अपनी शिकायत में चन्द्रपाल सिंह रूरा, कृष्णपाल सिंह उर्फ बल्लू राणा, श्रीकांत, शशिकांत, अनुज सिंह, सुरजीत वरनाले, वीर सिंह, राजेश सिंह, विश्वनाथ सिंह गपोचे, राजेश सिंह समेत 10 नामजद और चार अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। उनका आरोप है कि घटना 5 जुलाई को हुई जुगनू महापंचायत की रंजिश का परिणाम है और पहले भी उन्हें धमकियां मिल चुकी थीं।

पीड़ित व्यक्ति ने प्रशासन से सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं, इस पूरे प्रकरण में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सबूतों और गवाहों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शादी के दबाव, धमकियों से युवती ने लगाई फांसी

एचसी ने कहा- सुसाइड के सिवा रास्ता नहीं बचा लोअर-कोर्ट का फैसला बदला, आरोपी दोषी करार

बिलासपुर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके ब्यास ने कहा कि आरोपी की लगातार प्रताड़ना के कारण युवती के पास आत्महत्या जैसा कदम उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसी वजह से उसने फांसी लगाकर जान दे दी।

हाईकोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने एकतरफा प्यार में युवती पर शादी का दबाव बनाया, लगातार उसका पीछा किया, धमकियां दीं और प्रताड़ित किया। जिससे तंग आकर युवती ने आत्महत्या कर ली।

दरअसल, कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती 29 जनवरी 2018 की रात खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने गई थी। अगले दिन सुबह उसकी मां रुकनी बाई ने दरवाजा खोला तो बेटी का शव स्कार्फ के फंदे से पाइप पर लटका मिला।

जांच के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट और मोबाइल मिला। मां की शिकायत पर पुलिस ने मो. सेराज के खिलाफ मामला दर्ज किया।

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान सामने आया कि मो. सेराज युवती से एकतरफा प्यार करता था और उससे शादी करने का लगातार दबाव बना रहा था। युवती के मना करने पर वह उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी देता था। प्रताड़ना से परेशान होकर मई 2017 में युवती ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की थी। उसका अस्पताल में इलाज कराया गया था। इसी दौरान मानसिक तनाव से परेशान होकर उसकी मां ने भी नींद की गोलियां खा ली थीं।

कोरबा के सत्र न्यायालय ने जनवरी 2019 में आरोपी को बरी कर दिया था। अदालत का कहना था कि सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की एक्सपर्ट से जांच नहीं कराई गई और आत्महत्या के लिए सीधे तौर पर उकसाने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने मृतका की मां की गवाही को केवल इसलिए नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि किसी स्वतंत्र गवाह ने उसका समर्थन नहीं किया।

हाईवे पर बस-ट्रक समेत चार वाहनों की जोरदार भिड़ंत

एक यात्री की मौत और सात घायल

मथुरा, 23 जुलाई (एजेंसियां)। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में नरहौली पुल के पास गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से आगरा की ओर जा रहे मार्ग पर चार वाहनों की जोरदार भिड़ंत में एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार नरहौली पुल के पास दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक, मध्य प्रदेश की एक निजी बस, दूसरे ट्रक और एक कार की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार करीब 40 से 45 यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कई यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही थाना हाईवे पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची।

अतिथि शिक्षकों को बसों में भरकर ले गई पुलिस

देर रात टेंट उखाड़ा, धरनास्थल पर जवान तैनात, 22 दिन से आंदोलन कर रहे थे

दुर्ग-भिलाई, 23 जुलाई (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ अतिथि शिक्षकों के धरने पर देर रात पुलिस ने कार्रवाई की। हिंदी भवन के सामने पिछले 22 दिनों से चल रहे धरना स्थल से पुलिस ने टेंट हटाकर जब्त कर लिया।

इसके बाद आज (गुरुवार) सुबह धरना स्थल पहुंचे करीब 50 अतिथि शिक्षकों को पुलिस बसों में बैठाकर ले गई। धरनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि कोई नया प्रदर्शनकारी आंदोलन में शामिल न हो सके।

इससे पहले दिन में पुलिस ने धरना समाप्त करने की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बावजूद शिक्षक धरने पर डटे रहे, जिसके बाद देर रात यह कार्रवाई की गई।

पुलिस की कार्रवाई के बाद भी अतिथि शिक्षकों ने साफ कहा कि उनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है।

शिक्षकों का कहना है कि वे फिर से धरना देने की कोशिश करेंगे और जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि अब तक सरकार के साथ केवल चर्चा हुई है, लेकिन किसी भी मांग पर फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले अतिथि शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के दुर्ग स्थित निवास का करीब 24 घंटे तक घेराव किया था। मंत्री से चर्चा कराने के आश्वासन के बाद शिक्षक वहां से लौटकर हिंदी भवन के सामने फिर धरने पर बैठ गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि बातचीत के बाद उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बुधवार दोपहर दुर्ग पुलिस बड़ी संख्या में जवानों के साथ धरना स्थल पहुंची।

प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें शाम तक धरना समाप्त करने के लिए कहा था। साथ ही चेतावनी दी थी कि धरना जारी रहा तो अगले दिन से वहां बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धरना स्थल से टेंट हटाकर जब्त कर लिया।

अतिथि शिक्षक संघ का कहना है कि उनका आंदोलन संविलियन, सेवा सुरक्षा, समान कार्य के बदले समान वेतन और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक कई सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

बिलासपुर चौकीदार-हत्याकांड, 11 दिन बाद हुआ पोस्टमॉर्टम

10 दिनों तक चला धरना प्रदर्शन, 11.50 लाख मुआवजा और बेटे को संविदा नौकरी की बात पर सहमति

बिलासपुर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में चौकीदार नरेंद्र खांडे की हत्या के 11 दिन बाद बुधवार को उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव रिश्तेदारों को सौंप दिया गया, जिसके बाद गांव में अंतिम संस्कार किया गया।

चौकीदार के रिश्तेदार मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे थे। मंगलवार रात प्रशासन के साथ हुई बातचीत के बाद धरना समाप्त हुआ। प्रशासन ने अलग-अलग मदों से कुल 11.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और बेटे को संविदा या कलेक्टर दर पर नौकरी देने का आश्वासन दिया।

सरकंडा के नूतन चौक स्थित बाल संप्रेक्षण विशेष गृह में 12

जुलाई की रात चार अपचारी बालक चौकीदार नरेंद्र खांडे की हत्या कर फरार हो गए थे। घटना के बाद परिजन और समाज के लोग धरने पर बैठ गए।

उनकी मांग थी कि परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, पत्नी को 15 हजार रुपए मासिक पेंशन, बेटे को नौकरी और बेटी की पढ़ाई, शादी का खर्च प्रशासन उठाए।

धरने के आठवें दिन नरेंद्र खांडे की पत्नी सीमा खांडे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद समाज के लोगों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया।

इस बीच पुलिस ने चार फरार अपचारी बालकों में से तीन को पकड़ लिया, जबकि प्रशासन लगातार परिजनों को समझाने में जुटा रहा।

शुरुआत में समाज के लोग 35 लाख रुपए मुआवजे की मांग पर अड़े रहे।

ज्यादा देर दिखे तो मुकदमे हो जाएंगे, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी

छात्र प्रदर्शन के दौरान सीओ सिटी का बयान

आजमगढ़, 23 जुलाई (एजेंसियां)। दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के नेतृत्व में नीट-यूजी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जारी छात्र आंदोलन की गूंज अब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक पहुंच गई है। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और युवा प्रदर्शन के लिए जुटे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। इसी बीच सीओ सिटी शुभम तोड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह छात्रों से कहते सुनाई दे रहे हैं, ज्यादा देर तक यहां दिखे तो मुकदमे हो जाएंगे, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। मंगलवार दोपहर प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राएं और महिलाएं कुंवर सिंह उद्यान के पास एकत्र हुए। आरोप है कि जैसे ही उन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश की, पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली भेजा गया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिरासत में लिए गए साथियों को छुड़ाने के बाद वे दोबारा कलेक्ट्रेट और कुंवर सिंह उद्यान के आसपास एकत्र हुए। इसके बाद पुलिस ने फिर मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सीओ सिटी शुभम तोड़ी छात्रों से बातचीत करते हुए कहते सुनाई दे रहे हैं कि यदि वे अधिक देर तक मौके पर मौजूद रहे तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं।

भूपेश बघेल ने पुलिस अफसरों को दी चेतावनी

बोले- पुलिस के संरक्षण में भाजपा सरकार ने हमला किया, कुछ ही महीनों की मेहमान, फिर मिलेंगे

रायपुर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए प्रदर्शन के बाद सियासत और तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सुनियोजित हमला किया गया।

उसके बाद एफआईआर भी उन्हीं के खिलाफ दर्ज कर दी गई। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि, भाजपा सरकार कुछ ही महीनों की मेहमान है।

भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि, भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय के घेराव के नाम पर हमला किया। उन्होंने

आरोप लगाया कि इस दौरान भाजपा के मंत्री भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं को दरकिनार कर प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय और पार्टी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके, जबकि पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें छोड़ीं। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि, इस घटना में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुए और कई पत्रकारों को भी चोटें आईं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हमला कांग्रेस पर हुआ, लेकिन एफआईआर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कर ली गई। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि, पूरी घटना पुलिस के संरक्षण में भाजपा सरकार द्वारा कराया गया सुनियोजित हमला था। उन्होंने इसकी तुलना दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से भी की। अपने बयान के अंत में भूपेश बघेल ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा से राजनीतिक स्तर पर निपट लिया जाएगा, लेकिन पुलिस अधिकारी अपने आचरण का ध्यान रखें क्योंकि सत्ता बदलती रहती है।

मछली कारोबारी से 2.07 लाख की लूट

पांच बदमाश नकदी से भरा बैग छीनकर फरार, पुलिस जांच में जुटी

गिरिडीह, 23 जुलाई (एजेंसियां)। मोहनपुर में गुरुवार को दिनदहाड़े एक मछली कारोबारी से 2.07 लाख रुपये की लूट हो गई। पांच अज्ञात बदमाशों ने नकदी से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, जगपतारी निवासी मछली कारोबारी आफताब रैन बस स्टैंड स्थित मछली मंडी से कारोबार समाप्त कर अपने घर लौट रहे थे। मोहनपुर फॉरेस्ट ऑफिस के समीप दो बाइक पर सवार पांच अज्ञात बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया।

पीड़ित आफताब रैन ने आरोप लगाया कि अपराधियों ने उनकी कनपटी पर पिस्टलनुमा हथियार सटाकर नकदी से भरा बैग छीन लिया। बैग में कारोबार की 2,07,000 रुपये की नकद राशि थी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश पचंबा की ओर फरार हो गए।

आफताब रैन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पचंबा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके। संभावित ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है।

जेपीएससी पूर्व अध्यक्ष के आवास पर सीआईडी की छापेमारी

14वीं सिविल सेवा परीक्षा के दस्तावेज खंगाले गए, अब तक पांच लोग हो चुके हैं गिरफ्तार

रांची, 23 जुलाई (एजेंसियां)। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी क्रम में गुरुवार को सीआईडी की टीम ने जेपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एल. ख्यांग्ते के कांके रोड स्थित आवास पर छापेमारी की।

सीआईडी टीम पुलिस बल के साथ एल. ख्यांग्ते के आवास पर पहुंची और जेपीएससी से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की। जांच दल ने महत्वपूर्ण कागजात और अन्य रिकॉर्ड खंगाला। हालांकि, छापेमारी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। यह कार्रवाई

जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में धांधली और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद की जा रही है। इस मामले में सीआईडी ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। सीआईडी ने इस पूरे प्रकरण में कांड संख्या 16/2026 दर्ज किया है। सीआईडी की कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है और जांच एजेंसी परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी और रांची पुलिस की छापेमारी के बाद चेयरमैन एल ख्यांगते ने मंगलवार देर शाम इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके बाद जेपीएससी ने नौ परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। आयोग ने नौ जुलाई को ही इन परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था, जो सितंबर तक होनी थी। इन परीक्षाओं के माध्यम से 500 अधिकारियों की नियुक्ति होनी थी। इनमें प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, अभियोजन, उद्योग श्रम एवं तकनीकी विभाग के पद थे। वहीं 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 25 से 27 जुलाई तक होनी थी, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में चल रही थी। आयोग ने परीक्षा स्थगित करने का कारण अपरिहार्य बताया है। जेपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने केस दर्ज कर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता, परीक्षा आयोजित कराने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रामवीर सिंह और दो कर्मचारी मो. उस्मान व मो. एबाद शामिल हैं।

सेप्टिक टैंक में दो मजदूरों की मौत

जहरीली गैस की चपेट में आने से दम घुटा सेंटरिंग हटाने के लिए अंदर गए थे दोनों

धनबाद, 23 जुलाई (एजेंसियां)। धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के सदरियाडीह गांव में गुरुवार को एक सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई। राजमिस्त्री और एक मजदूर सेंटरिंग खोलने के लिए टैंक के अंदर उतरे थे।

जानकारी के अनुसार, लगभग 12 फीट गहरे इस सेप्टिक टैंक की ढलाई करीब एक महीने पहले की गई थी। गुरुवार को सेंटरिंग हटाने के लिए दोनों मजदूर टैंक के भीतर गए। कुछ ही देर बाद, अंदर मौजूद जहरीली गैस के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े।

स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों को तत्काल बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान अंधारी बस्ती निवासी दिलीप महतो (45) और सदरियाडीह निवासी राजेश महतो (25) के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बाघमारा अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू और बाघमारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। यह घटना निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन और बंद स्थानों में काम करने से पहले गैस जांच जैसी आवश्यक सावधानियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

थम जाएगा इंडस्ट्री का इंजन

ईरान युद्ध के बीच घुटनों पर आ जाएगा अमेरिका! बड़ा गेम खेल रहा चीन

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। ग्लोबल रेयर अर्थ इंडस्ट्री में चीन का एकाधिकार है। माइनिंग में उसकी हिस्सेदारी दो-तिहाई है जबकि रिफाइनिंग में वह 90% से ज्यादा हिस्से को कंट्रोल करता है। अपनी इस बादशाहत को चीन स्ट्रैटजिक हथियार की तरह यूज कर रहा है। हाल में उसने कई देशों को इनके एक्सपोर्ट में कटौती की है। अमेरिका को भी चीन का रेयर अर्थ एक्सपोर्ट काफी कम हो गया है।

2026 की पहली छमाही में अमेरिका को चीन से रेयर-अर्थ मैग्नेट का मासिक एक्सपोर्ट औसतन 479 टन रहा। यह 2021 के बाद सबसे कम सालाना मासिक औसत है। इसकी तुलना में, 2022 और 2024 के बीच एक्सपोर्ट औसतन 586 टन था, जो मौजूदा दर से लगभग 22% ज्यादा है। इन कंपोनेंट्स का यूज इलेक्ट्रिक वाहनों, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और डिफेंस जैसे उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। यही वजह है कि अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स के लिए इनकी सुरक्षित सप्लाई एक अहम प्राथमिकता है। इससे ईरान युद्ध में फंसे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

चीन की वादाखिलाफी

अक्टूबर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें चीन ने ट्रेड वॉर को रोकने के हिस्से के तौर पर रेयर-अर्थ मैग्नेट की सप्लाई जारी रखने का वादा किया था। लेकिन वह अपना वादा नहीं निभा रहा है। चीन इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है और ग्लोबल रेयर-अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन के 90% से ज्यादा हिस्से पर उसका कंट्रोल है। साल 2024 में चीन ने 270,000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ का उत्पादन किया जो ग्लोबल प्रॉडक्शन का 69% है। इसकी तुलना में अमेरिका का उत्पादन 45,000 टन और म्यांमार को 31,000 टन है। ग्लोबल प्रोडक्शन में अमेरिका की हिस्सेदारी 11 फीसदी और म्यांमार की हिस्सेदारी 8 फीसदी है। नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में भी रेयर अर्थ प्रोडक्शन होता है।

जापान पर निर्भरता होगी कम!

बुलेट ट्रेन के लिए भारत बना रहा अपना सुपरफास्ट सिस्टम

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। भारत अब बुलेट ट्रेन तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारतीय रेलवे देश के लिए अपना स्वदेशी हाई-स्पीड रेल सिग्नलिंग और कंट्रोल सिस्टम विकसित कर रहा है।

इसका नाम भारत ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होगा। यह सिस्टम भारतीय जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में बनने वाले करीब 7,000 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन नेटवर्क के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, बीटीसीएस को ओपन-सोर्स तकनीक पर विकसित किया जाएगा। इससे इसकी लागत कम रहेगी और इसे देशभर में अलग-अलग हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं की जरूरत के मुताबिक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस तकनीक को दूसरे देशों को भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

मुंबई-अहमदाबाद परियोजना से मिलेगा अनुभव

भारतीय रेलवे इस नए सिस्टम को विकसित करने में मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना से मिले अनुभव का इस्तेमाल करेगा। इस परियोजना में फिलहाल यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल-2 लगाया जा रहा है। यह सिग्नलिंग सिस्टम 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से ट्रेनों का सुरक्षित संचालन करने में सक्षम है। पिछले साल जून में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए करीब 4,100 करोड़ रुपये का सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्ट भारत की दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन और जर्मनी की सीमेंस के कंसोर्टियम को दिया था।

2027 तक नए कॉरिडोर की योजना होगी तैयार

अधिकारियों के अनुसार, देश में प्रस्तावित नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के डिजाइन और रूट प्लान को 2027 के मध्य तक अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। रेलवे का मानना है कि अपना कंट्रोल सिस्टम विकसित होने से भारत की कंपनियों को भी हाई-स्पीड रेल उपकरण और तकनीक विकसित करने का बड़ा अवसर मिलेगा। इससे रेलवे सेक्टर में घरेलू विनिर्माण और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

जापानी तकनीक को लेकर हुई थी चर्चा

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जापान के सहयोग से बनाई जा रही है। हालांकि, इसमें जापान के डिजिटल ऑटोमैटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के बजाय यूरोपियन ईटीसीएस लेवल-2 सिग्नलिंग को अपनाया गया है। इसी मुद्दे पर हाल ही में जापान के पूर्व मंत्री हिदेकी माकिहारा ने सवाल उठाए थे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जापान की कंपनी हिताची की ट्रेनें ईटीसीएस सिस्टम के साथ पूरी तरह अनुकूल हैं।

1.75 लाख करोड़ का खाने के तेल का आयात होगा!

सिर्फ 8 महीने में बढ़ गए 20% दाम, वजह क्या है?

नई दिल्ली। भारत कच्चे तेल के साथ ही खाद्य तेलों का भी बड़ा आयातक देश है। एक तरफ सरकार दलहन-तिलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर देश में खाद्य तेलों के आयात का बिल भी बढ़ता जा रहा है। भारत के खाने के तेल आयात बिल चालू तेल वर्ष 2025-26 (नवंबर-अक्टूबर) के पहले आठ महीनों में ही 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। सीजन के अंत तक इसके आंकड़ा और बड़ा हो जाएगा।

1.75 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है बिल

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्यों के लिखे अपने मासिक पत्र में, एसईए के अध्यक्ष संजीव अस्थाना ने कहा कि भारत खाद्य तेल के क्षेत्र में अपने सफर के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, और चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है।

चालू तेल वर्ष 2025-26 के शुरुआती 8 महीने में ही पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। का अनुमान है कि तेल वर्ष के अंत तक यह 1.75 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा।

कितने बढ़े तेल के दाम?

देश का खाद्य तेल आयात बिल, जो पिछले साल 1.61 लाख करोड़ था, अब ये रिकॉर्ड 1.75 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

चालू तेल वर्ष के नवंबर से जून के दौरान ही आयात 104 लाख टन से अधिक हो चुका है, जिससे आयात बिल 99,000 करोड़ से बढ़कर 1.19 लाख करोड़ हो गया है, यानी मात्र आठ महीनों में लगभग 20,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जो 20.20 फीसदी के आसपास है।

रुपये को बचाने के लिए आरबीआई का बड़ा दांव

मई में बेचे 6.1 अरब डॉलर, वायदा बाजार में बना नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी तनाव का असर भारतीय मुद्रा 'रुपये' पर पड़ रहा है। रुपये की कीमत में गिरावट रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मई महीने में डॉलर बाजार में बड़ा कदम उठाया।

केंद्रीय बैंक आरबीआई की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ने मई में 6.104 अरब डॉलर बेचे। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी आरबीआई ने रुपये को मजबूत रखने के लिए 8.944 अरब डॉलर बेचे थे।

मई के दौरान रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की खरीद-बिक्री इस प्रकार की: कुल डॉलर खरीदे: 22.2 अरब डॉलर कुल डॉलर बेचे: 28.3 अरब डॉलर नतीजा (शुद्ध बिक्री): 6.104 अरब डॉलर मई के अंत तक आरबीआई का वायदा बाजार में बकाया डॉलर बिक्री का आंकड़ा 106.66 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक भविष्य के लिए भी रुपये को स्थिर रखने की पूरी तैयारी कर रहा है।वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक तस्वीर पेश की है: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और इसकी रफ्तार बरकरार है। भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है कि उससे 10 महीने से अधिक का सामान विदेशों से आयात किया जा सकता है। इस साल की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत के आयात और निर्यात दोनों में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। देश में मानसून कुछ जगहों पर असमान रहा है, जिससे खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने का खतरा रहता है, लेकिन भारत के पास अनाज का पर्याप्त स्टॉक है जो महंगाई को रोकने में मदद करेगा।

मुकेश अंबानी की इस कंपनी ने डुबो दिया लोगों का पैसा, एक साल में करीब आधी रकम हुई स्वाहा

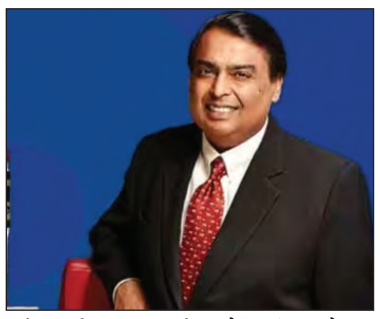

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। मुकेश अंबानी की शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनी सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ही नहीं है। उन्होंने ऐसी कई कंपनियों में बड़ी रकम निवेश की है जो शेयर मार्केट में कारोबार करती हैं। ऐसी ही एक कंपनी लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड भी है। एक समय इस कंपनी के शेयर रॉकेट बने हुए थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट है।

गुरुवार को इस कंपनी के शेयर में मामूली तेजी आई। इस तेजी के साथ यह शेयर 662.70 रुपये पर बंद हुआ। पिछले 6 महीने में यह शेयर 17 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गया है। वहीं एक साल में इस शेयर में करीब 47 फीसदी की गिरावट आई है। यानी एक साल में निवेशकों की करीब आधी रकम स्वाहा हो गई है।

साल 2024 में रॉकेट बना था यह शेयर

साल 2024 में इस शेयर में गजब की तेजी आई थी। जनवरी 2024 की शुरुआत में शेयर की कीमत 307 रुपये थी। अगस्त 2024 के अंत में यह शेयर करीब 2485 पर पहुंच गया था, जो इसका अभी तक का ऑल टाइम हाई है। यानी 7 महीने में ही इसमें 700 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ गई थी।

लगातार आती रही गिरावट

अगस्त 2024 के बाद इस शेयर में गिरावट शुरू हुई। बीच-बीच में कुछ मौके ऐसे जरूर आए जब यह शेयर संभला, लेकिन इसमें बड़ी तेजी नहीं आई। स्थिति ऐसी है कि यह शेयर अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 70 फीसदी से ज्यादा नीचे गिर गया है।

कितनी है अंबानी की हिस्सेदारी?

लोटस चॉकलेट कंपनी का मालिकाना हक मुकेश अंबानी के पास है। यह रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की सब्सीडियरी कंपनी है। कंपनी की स्थापना 1988 में हुई थी। आरसीपीएल ने इस कंपनी में 51% हिस्सेदारी खरीदी थी। आरसीपीएल देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल की सहयोगी कंपनी है। रिलायंस रिटेल की कमान मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के पास है।

चांदी 5,000 से ज्यादा फिसली, सोना भी 1600सस्ता हुआ

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। सोने और चांदी की कीमत में आज गिरावट आई है। एमसीएक्स पर कारोबार के दौरान सोने की कीमत में 5,000 रुपये से ज्यादा गिरावट आई है जबकि सोने की कीमत 1,600 रुपये से अधिक गिरी है। पश्चिम एशिया में संकट बढ़ने से कच्चे तेल की कीमत में तेजी आई है। इससे एक बार फिर महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। इसका असर आज सोने और चांदी की कीमत पर देखने को मिला है। हालांकि सर्राफा बाजार में भी सोने की कीमत में तेजी आई है। एमसीएक्स पर 5 अगस्त की डिलीवरी वाला सोना 145680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज यह 145470.00 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 1,623 रुपये नीचे 1,44,057 तक फिसला। 2.45 बजे यह 1,350 रुपये यानी 0.93 फीसदी नीचे 1,44,330 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी भी 5,178 रुपये की गिरावट के साथ 2,21,820 रुपये तक फिसली।

सर्राफा कीमत

गुड रिटर्न्स के मुताबिक सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना 770 रुपये की तेजी के साथ 1,47,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड रहा है। 22 कैरेट सोना 700 रुपये ऊपर 1,35,000 रुपये पर है जबकि 18 कैरेट वाला सोना 580 रुपये की तेजी के साथ 1,10,460 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। चांदी फ्लैट 2,40,000 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय कीमत

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पॉट गोल्ड की कीमत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ और यह $4,133.39 प्रति औंस पर रही। पिछले सेशन में इसकी कीमत $4,165.87 तक पहुंच गई थी, जो 7 जुलाई के बाद का इसका सबसे ऊंचा स्तर था। अगस्त डिलीवरी के लिए यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 0.4% गिरकर $4,136.8 पर आ गया। स्पॉट सिल्वर 0.1% बढ़कर $59.78 प्रति औंस हो गई।

शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट

सेंसेक्स 364 अंक टूटा, अडानी पोर्ट्स सबसे ज्यादा फिसला

मुंबई, 23 जुलाई (एजेंसियां)। पश्चिम एशिया में जारी संकट और कच्चे तेल की कीमत में तेजी का असर आज घरेलू शेयर बाजार पर देखने को मिला। लगातार चौथे दिन शेयर बाजार में गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स में 400 अंक से अधिक की गिरावट आई है जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 23,900 से नीचे फिसल गया। अंत में सेंसेक्स 363.66 अंक यानी 0.47% गिरावट के साथ 76,391.39 अंक पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी भी 126.65 अंक यानी 0.53% फिसलकर 23,869.60 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। अडानी पोर्ट्स में सबसे ज्यादा 2.01 फीसदी गिरावट रही। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, इंडिगो, एक्सिस बैंक, रिलायंस, टाटा स्टील, एसबीआई, एशियन पेंट्स, मारुति में भी 1 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई। दूसरी ओर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, इटरनल, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व और कोटक बैंक में तेजी रही।

क्यों गिरा बाजार?

निफ्टी50 इंडेक्स में अडानी एंटरप्राइजेज, नेस्ले इंडिया और श्रीराम फाइनेंस सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर रहे। सेक्टर के हिसाब से देखें तो निफ्टी रियल्टी, निफ्टी केमिकल और निफ्टी ऑयल एंड गैस में सबसे अधिक गिरावट आई। वहीं, निफ्टी मीडिया और निफ्टी ऑटो ने बेहतर प्रदर्शन किया। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमत में आज काफी तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड 4.35 फीसदी तेजी के साथ 98.16 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है।

कच्चे तेल में तेजी से 382 करोड़ का घाटा

रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद 2 .38 अरब का घाटा

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने एफवाई27 की पहली तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इंडिगो एयरलाइन की पैरेंट कंपनी, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने 23 जुलाई को 30 जून, 2026 को खत्म हुई तिमाही के लिए 382 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन नेट लॉस (शुद्ध घाटा) बताया।

इससे पहले इसी अवधि में कंपनी को 2,161 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफ़िट (शुद्ध लाभ) हुआ था।

कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद इंडिगो के राजस्व में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है, हालांकि बढ़ती लागत के कारण कंपनी को इस तिमाही में शुद्ध घाटा उठाना पड़ा है।

कैसे रहे क्यू1 रिजल्ट?

क्यू1एफवाई26 में 20,496 करोड़ के मुकाबले, क्यू1एफवाई27 में एयरलाइन का ऑपरेशन से रेवेन्यू 20% बढ़कर 24,584 करोड़ हो गया। हालांकि, इस शानदार रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद कंपनी को 2.38 अरब रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है। जबकि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 21.76 अरब रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था। कंपनी के खर्च 35.1% की तेज़ी से बढ़े। इसमें सबसे बड़ी वजह एयरक्राफ्ट फ्यूल के खर्च में लगभग 86% की बढ़ोतरी थी, जिससे यह खर्च 10,830 करोड़ हो गया।

घाटे के मुख्य कारण

इंटरग्लोब एविएशन के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया ने बताया कि इस तिमाही में मुनाफे पर तीन बड़े कारणों से असर पड़ा। ईंधन की बढ़ती कीमतें: विमान ईंधन की लागत में पिछले साल के मुकाबले 85.7% की भारी बढ़ोतरी हुई है। विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव: रुपये की कमजोरी और डॉलर की मजबूती ने खर्चों को बढ़ा दिया। मिडिल ईस्ट संकट: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण नेटवर्क संबंधी बाधाएं आईं, जिससे परिचालन प्रभावित हुआ।

मुनाफा बढ़ा, नया सीईओ मिला, लेकिन कंपनी ने दिया ऐसा संकेत कि निवेशक हो गए अलर्ट

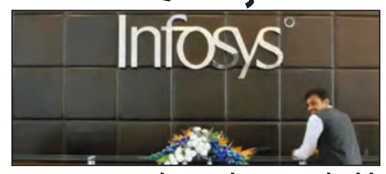

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2026-27 (एफवाई27) की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. अप्रैल-जून 2026 तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 12% बढ़कर 7,769 करोड़ रुपये हो गया. पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,921 करोड़ रुपये था. वहीं, कंपनी की ऑपरेशनल आय भी 14% बढ़कर 48,211 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 42,279 करोड़ रुपये थी.

हालांकि, मजबूत तिमाही नतीजों के बावजूद कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष एफवाई27 के लिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस की ऊपरी सीमा को घटा दिया है. इससे साफ है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और आईटी सेवाओं की मांग को लेकर कंपनी अभी भी सतर्क बनी हुई है.

आशीष कुमार दास होंगे नए सीईओ

तिमाही नतीजों के साथ कंपनी ने नेतृत्व में बड़े बदलाव का भी ऐलान किया. इंफोसिस ने आशीष कुमार दास को सीईओ-निर्दिष्ट नियुक्त किया है. वह 1 अप्रैल 2027 से मौजूदा सीईओ और प्रबंध निदेशक सलिल पारेख की जगह कंपनी की कमान संभालेंगे. तब तक सलिल पारेख अपने पद पर बने रहेंगे और नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा करेंगे.कंपनी का कहना है कि यह बदलाव लंबे समय की रणनीति के तहत किया गया है, ताकि नेतृत्व में सहज परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके.

एफवाई27 के लिए घटाया ग्रोथ अनुमान

इंफोसिस ने पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने राजस्व वृद्धि अनुमान की ऊपरी सीमा को 3.5% से घटाकर 3% कर दिया है. हालांकि, निचली सीमा को बरकरार रखा गया है. कंपनी का मानना है कि दुनिया के कई प्रमुख बाजारों में आर्थिक सुस्ती और ग्राहकों द्वारा आईटी खर्च में सावधानी बरतने का असर आने वाली तिमाहियों में भी देखने को मिल सकता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि गाइडेंस में कटौती यह संकेत देती है कि आईटी सेक्टर में रिकवरी अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई है. ऐसे में कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स और बड़े तकनीकी निवेश को लेकर सतर्क रुख अपना रही हैं.

दैनिक पंचांग

गृह गोचर

श्री रौद्र /श्री दुर्मती नामके संवत्सरे-विक्रम संवत्- 2083
शक संवत् -1948, सूर्य दक्षिणायने /उत्तर , ऋतु- वर्षा
महावीर निर्वाण संवत् -2551 , राजा गुरु, मन्त्री भौम
कलियुग अवधि - 432000
भोग्य कलि वर्ष. - 426873
कलियुग संवत् - 5127 वर्ष,
कल्पारंभ संवत् - 1972949127
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् - 1955885127
सूर्योदय 05-56
सूर्यास्त. 18 -48
दिशाशूल - पश्चिम - दही खाकर घर से निकले
मास - आषाढ़ शुक्ल पक्ष शुक्रवार 24 July 2026
तिथि - दशमीं 09-12 तक उपरान्त एकादशी
नक्षत्र - अनुराधा 04-36 तक उप ज्येष्ठा
योग - शुक्ल 20-11 तक उप ब्रह्म
करण - गर 09-12 तक उप वणिज

गृह स्थिति			लग्नारंभ समय	
सूर्य	कर्क	मे	कर्क---	05-26 बजे
चंद्र	वृश्चिक	मे	सिंह---	07-38 बजे
मंगल	वृष	मे	कन्या--	09-44 बजे
बुध	मिथुन	मे	तुला----	11-50 बजे
गुरु	कर्क	मे	वृश्चिक--	14-00 बजे
शुक्र	सिंह	मे	धनु----	16-14 बजे
शनि	मीन	मे	मकर--	18-19 बजे
राहु	कुंभ	मे	कुंभ---	20-10 बजे
केतु	सिंह	मे	मीन---	21-48 बजे
			मेष----	23-24 बजे
			वृष-----	01-09 बजे
			मिथुन--	03-10 बजे

विशेषः- राशिफल ग्रहों के गोचर के आधार पर लिखा गया है।सूक्ष्म फलादेश के लिए जन्म पत्रिका हमें दिखावे व पत्रिका की सूक्ष्म स्थिति व दशान्तर्दशा को विशेष प्रभावित समझना चाहिए ।

राहुकाल 10-46 से 12-23 तक

श्री पंचागुल्लि ज्योतिष केन्द्र अतापुर Ph. 9247132654

दिन का चौघड़िया		रात का चौघड़िया	
चंचल	05 -56 - 07-31 शुभ	रोग	18-48 - 20-14 अशुभ
लाभ	07-31 - 09-08 शुभ	काल	20-14 - 21-37 अशुभ
अमृत	09-08 - 10-46 शुभ	लाभ	21-37 - 22-59 शुभ
काल	19-46 - 12-23 अशुभ	उत्पात	22-59 - 00-23 अशुभ
शुभ	12-23 - 13-59 शुभ	शुभ	00-23 - 01-46 शुभ
रोग	13-59 - 15-37 अशुभ	अमृत	01-46 - 03-09 शुभ
उत्पात	15-37 - 17-14 अशुभ	चंचल	03-09 - 04-32 शुभ
चंचल	17-14 - 18-48 शुभ	रोग	05-32 - 05-53 अशुभ

आपका राशिफल

मेष (चू,चे, चो,ला, ली, लू, ले, लो, अ,)
आज आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी । आप आज तर्क के स्थान पर अपने दिल की आवाज और प्रवृति के आधार पर फैसले कर सकते हैं,लेकिन वे भी वित्त के मामले में लाभकारी ही साबित होंगे । आप इन दिनों फैसले लेने में सबसे अधिक महत्ता अपने मन की आवाज को देते हैं।

वृष (ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो)
आप बहुत अच्छे निर्णायक हैं और सब चीजों का आसानी से विश्लेषण कर लेते हैं । आज आपको अपनी इस विशेषता के लिए खूब तारीफ मिलेगी । लोग अच्छी तरह काम करने के लिए आपकी और देखेंगे और आपसे सीखेंगे । आपको किसी खतरनाक जगह पर यात्रा करने की जरूरत सम्बन्धी सूचना मिलेगी । घबराएं नही,यह यात्रा छोटी सी होगी ।

मिथुन (का, की, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह,)
आपके पास पिछले कामों की भरमार रहेगी,आप पिछले कुछ समय से अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रहें हैं,आज का दिन आपके उन सब कामों के लिए बहुत अच्छा है । आपको अपने कामो को पूरा करने के लिए इच्छाशक्ति,अनुशासन और एकाग्रता से काम लेना होगा । जिस काम की आप अच्छी खासी योजना बनाये हुए हैं,उसे सफलता में बदलने के लिए अपनी पूरी उर्जा को उसमें लगा दें ।

कर्क (ही, हू ,हे , हो, डा , डी, डू, डे, डो,)
आज आप बहुत जल्दी में हैं । आपको अपने सब कामों को निपटाने की गति जरा धीमी करनी होगी क्योकि जल्दी मे काम निपटाने के चक्कर में आपसे गलतियाँ हो सकती हैं । इसीलिए धीमे चलें । इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप क्या कह और कर रहें हैं ।आपको अपने कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए सभी बारीकियों पर ध्यान देने की जरुरत है ।

सिंह (मा, मी ,मू ,मे, मो, टा, टी ,टू ,टे,)
यह समय अपने लक्ष्य के लिए गंभीरता से कोशिश करने का है ,आपको बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा । आप अभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे,उनको कार्यान्वित करने का समय आ गया है ।आपको अपना सारा ध्यान अब इसी पर लगाना होगा । हालाँकि आप इसके कारण बहुत व्यस्त रहेंगे ,लेकिन आपको इसका अच्छा फल भी जल्दी मिलेगा और आपकी सफलता की इच्छा बढ़ेगी ।

कन्या (टो पा पी पू ष ण ठ पे पो)
दिन आपके लिए अच्छा रहेगा ,लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप छोटी सी बात के बारे में सोच-सोचकर परेशान हों । ऐसा सोचना प्राक्रतिक है ,लेकिन इससे आपकी घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति प्रभावित होगी । यह समय बड़े लक्ष्यों को सोचकर छोटी-मोटी बातों को नजरंदाज कर देने का है ।

तुला (रा, री, रू ,रे ,रो , ता, ती, तू ,ते,)
आज आपके लिए अच्छा दिन है । आपका सुंदर व्यक्तित्व दूसरों को आकर्षित करेगा । आज आप कुछ भी करें,सफलता मिलेगी । आप काफी लोकप्रिय हैं । आप सृजनात्मक भी हैं और नम्र भी ,आपके इन्ही गुणों ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है । चालाकी और अभिमान को आने दिये बिना इसी रास्ते पर चलते रहें ।

वृश्चिक (तो,ना,नी, ने,नू, नो, या, यी ,यू,)
आप अपने गुस्से के कारण तुरंत प्रतिक्रिया देने के मूड में हैं ।लेकिन आपके लिए सुझाव यह है कि अपने दिमाग को शांत रखकर गंभीरता से सोचें । आपके पास अच्छी संचार-कुशलता है और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें । तनाव घटाने के लिए,किसी साहसिक यात्रा पर जा सकते हैं लेकिन शारीरिक आनंद के चक्कर में न पड़ें।

धनु (ये, यो,भा, भी, भू धा ,फा, ढा, भे)
दिन शुरुआत में बहुत अच्छा,बाद में थोडा व्यस्त रह सकता है । घर पर कोई बीमार पड़ सकता है और आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनकी देखभाल के लिए समय निकालना होगा । आपको सहकर्मियों या दोस्तों से खुशी मिलेगी और आप आने वाले समय में उनके साथ समय बिताने की योजनायें बना सकते हैं ।

मकर (भो, ज, जी, खो, खू, खे, खो, गा, गी)
आपका दिमाग आज बहुत सक्रिय है ,आप उर्जा और प्रेरणा से भरे हैं । आपके दिमाग में नयी योजनायें आती रहेंगी जिन्हें आप आसानी से कार्यान्वित भी कर पायेंगे । आपकी समस्या आज यही रहेगी की आपके दिमाग में आज लगातार नए विचारों की बाढ़ सी आती रहेगी । आप अपने आसपास के सभी लोगों को भी अधिक प्रेरित कर पायेंगे ।

कुंभ (गू, गे ,गो, सा, सी, सू, से, सो, दा)
आपको दोस्तों का प्यार पाने के लिए थोडा नम्र बनना पड़ेगा । आप यह नही जानते लेकिन आपको घमंडी समझा जाता है इसीलिए यह सबसे अच्छा समय है कि आप दूसरों की आलोचना करने के स्थान पर अपनी भूतकाल की गतिविधियों का विश्लेषण करें । यह आपके लिए अपने अंतर्मन में झाँकने का बहुत अच्छा समय है।

मीन (दी, दू,थ, झ, ञ, दे, दो, चा,ची)
आप आज अनजाने तथ्यों के साथ सहज महसूस नही करेंगे । इसलिए आप प्रयोग ना करते हुए जानी –पहचानी राहों पर ही आगे बढने की कोशिश करेंगे । आपके सामने नए अवसर आयेंगे ,लेकिन आप उनमे से भी उसी को चुनेंगे जिससे आप भली-भांति परिचित हैं । इस समय का उपयोग अपना पिछला बचा हुआ काम निपटाने के लिए करें ।

पं महेशचन्द्र शर्मा फोन : 9167555710

आनासागर झील की दुर्दशा पर फूटा गुस्सा

कांग्रेस के आह्वान पर स्कूल-कॉलेज और बैंक बंद

अजमेर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। ऐतिहासिक आनासागर झील की बदहाली, बढ़ती गंदगी, बदबू और बड़ी संख्या में मछलियों की मौत के विरोध में गुरुवार को शहर कांग्रेस के आह्वान पर 'अजमेर बंद' का व्यापक असर देखने को मिला। बंद को देखते हुए शहर के कई निजी स्कूलों और कॉलेजों ने एहतियातन छुट्टी घोषित कर दी। वहीं, बाजारों में सामान्य जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ।

बता दें कि गुरुवार सुबह से ही बंद का असर अजमेर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में नजर आने लगा। शहर के ऐतिहासिक दरगाह बाजार में सुबह से ही कई होटल और अधिकांश दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। हालांकि, अकीदतमंदों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दरगाह के आसपास की फूलों की दुकानें खुली नजर आईं। कंट्रोल रूम और विशेष टीमों के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही शहर के अलग-अलग चौराहों और बाजारों में व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील करते देखे गए।

कांग्रेस के आह्वान पर अजमेर बंद

बंद का आह्वान कराने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रामक रुख भी शहर के कई हिस्सों में देखने को मिला। रेलवे स्टेशन के बाहर सवारी ले जा रहे ई-रिक्शा और टेम्पो को कांग्रेसियों ने जबरन रुकवाया। कई वाहनों में बैठे पर्यटकों और यात्रियों को नीचे उतार दिया गया। इस दौरान एक ई-रिक्शा चालक मौका देखकर अपना वाहन लेकर वहां से भाग निकला।

कचहरी रोड पर स्थित कई प्राइवेट बैंकों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और जबरन बैंक बंद करवा दिए। शटर गिराने के बाद अंदर काम कर रहे बैंक कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और शांतिपूर्वक सहयोग की अपील की गई। कचहरी रोड स्थित एक बंद पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल और वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली निकाली और पूरे शहर में भ्रमण कर बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। डॉ. जयपाल ने स्पष्ट किया कि आमजन की सहूलियत को देखते हुए अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस और अग्निशमन जैसी आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को इस बंद से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। इसके अलावा बंद के सुचारू संचालन और समन्वय के लिए जिला कांग्रेस कार्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।

बंद के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अजमेर जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आई। अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशों पर शहर को अलग-अलग सुरक्षा जोन में बांटा गया। शहर के प्रमुख चौराहों, रेलवे स्टेशन, कचहरी रोड और संवेदनशील इलाकों में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर स्थिति की निगरानी और मॉनिटरिंग करते रहे, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।

जोजरी नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, एसआईटी जांच पर भी उठाए सवाल

जोधपुर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। जोजरी नदी में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मंगलवार को स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य अपने नागरिकों को जहर देना चाहता है तो यह शर्मनाक है। हम राज्य के हाथों लोगों को जहर नहीं देने देंगे। चाहे इसके कारण कितनी भी नौकरियां क्यों न चली जाएं, हम 20 लाख लोगों की जान की रक्षा करेंगे। सप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि नदी में अभी भी बहुत ज्यादा जहरीला पानी बह रहा है। एसआईटी ने अब तक कुछ नहीं किया है। रिपोर्ट के रिव्यू से पता चलता है कि जांच सही दिशा में नहीं चल रही है, बल्कि यह सिर्फ़ एक दिखावा है। कोर्ट में अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। बता दें कि जोजरी नदी में प्रदूषण का मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है। जोधपुर सहित कई जिलों के लोग लगातार नदी में प्रदूषण को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। माना जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए वकील एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि एसआईटी पिछले महीने बनाई गई थी और उसने अपनी शुरुआती रिपोर्ट एक्सपर्ट कमिटी को सौंप दी है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया है और सीईटीपी से पानी के सैंपल के कलेक्शन के लिए ज़िम्मेदार रीजनल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि, कोर्ट इन जवाबों से खुश नहीं दिखा। बेंच ने कहा कि गलत रिपोर्ट दी जा रही हैं। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि कमेटी के निर्देशों को न मानने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जोजरी नदी किनारे बनी सभी फैक्ट्रियां अभी बंद हैं, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी उन इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेशन पर विचार कर सकती है जो पॉल्यूशन कंट्रोल के तरीके अपनाने को तैयार हैं।

बता दें कि जोजरी नदी में प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने औद्योगिक कचरे और सीवरेज के कारण जोधपुर, पाली और बालोतरा की नदियों के जहरीले होने पर गहरी चिंता जताई थी। इसमें स्टील और टैक्सटाइल सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों की बड़ी भूमिका सामने आई थी।

हाल ही में जोधपुर की जोजरी नदी पर जेएनवीयू के शोध में बड़ा खुलासा हुआ था। अध्ययन में सामने आया था कि जोजरी नदी का पानी न केवल पीने योग्य रहा, बल्कि सिंचाई के लिए भी असुरक्षित श्रेणी में पहुंच चुका है। शोधकर्ताओं की मानें तो स्टील और टैक्सटाइल उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट इस स्थिति के प्रमुख कारण है।

पेपर लीक विवाद; पीएम मोदी के ट्वीट पर भड़के टीकाराम जूली, पूछे तीखे सवाल

अलवर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। देश में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और युवाओं के भविष्य को लेकर सियासत पूरी तरह गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली ने गुरुवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों की चिंता जाहिर करने और इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात पर जूली ने जोरदार हमला बोला।

टीकाराम जूली ने तीखे लहजे में सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आज सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वे बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं और इस

मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई होनी चाहिए। मैं उनसे बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 12 सालों से देश में आपकी सरकार चल रही है। इस दौरान देशभर में दर्जनों पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका, तब आपकी सरकार ने दोषियों पर क्या सख्त कार्रवाई की? इतने सालों तक आपको देश के इन होनहार बच्चों और उनके परेशान मां-बाप का दर्द क्यों नजर नहीं आया?

नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं और अभ्यर्थियों पर हुए पुलिसिया एक्शन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं।

छात्रों पर अत्याचारः जब जंतर-मंतर पर मासूम बच्चों और अभ्यर्थियों की बेरहमी से पिटाई की जा रही थी, तब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की संवेदनशीलता कहां चली गई थी?

सवालों से भागती सरकारः जब भी सदन में या सड़कों पर विपक्ष युवाओं और रोजगार से जुड़े सवाल पूछता है, तो सरकार कोई जवाब देने के बजाय बातें घुमाने लगती है।

टीकाराम जूली ने राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर भी गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के बड़े नेता अपने हक की आवाज उठाने वाले छात्रों को 'पत्थरबाज' कहकर संबोधित कर रहे हैं। सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह की गलत बयानबाजी करना बेहद निंदनीय है।

एसडीएम थप्पड़ कांडः अब मांगा नरेश मीणा की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, कोर्ट ने 10 दिन पहले जारी किया था गिरफ्तारी वारंट

टोंक, 23 जुलाई (एजेंसियां)। टोंक के देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के 10 दिन बाद अब नगरफोर्ट थाना पुलिस ने नरेश मीणा से चल-अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मांगा है, जिसे एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत टोंक में पेश किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की फिर से गिरफ्तारी हो सकती है। नगरफोर्ट थानाधिकारी राजेंद्र ताड़ा की ओर से नरेश मीणा की चल अचल संपत्ति के रिकॉर्ड के लिए ग्राम पंचायत नयागांव उर्फ नानवता के सरपंच (प्रशासक) को पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि टोंक कोर्ट की ओर से अभियुक्त नरेश पुत्र कल्याण सिंह मीणा निवासी नयागांव उर्फ नानवता थाना मोठपुर जिला बांरा का चल-अचल सम्पत्ति का रिकॉर्ड मांगा गया

है। ऐसे में नरेश मीणा की चल-अचल सम्पत्ति रिकॉर्ड उपलब्ध कराए, ताकि कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड पेश किया जा सके।

बता दें कि समरावता थप्पड़ कांड के आरोपी तथा पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की 13 जुलाई को एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत टोंक ने जमानत अर्जी निरस्त करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। नरेश मीणा को इस प्रकरण में 13 जुलाई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। आरोप है कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। इसे आधार बनाते हुए नगरफोर्ट थाना पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक रामावतार सोनी के माध्यम से एससी, एसटी कोर्ट में जमानत निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पुलिस की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए नरेश मीणा की जमानत रद्द की थी और उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए थे।

पुलिस की ओर से अदालत में प्रस्तुत आवेदन में बताया कि पीपलोदी स्थित सरकारी विद्यालय की छत गिरने से छात्रों की मौत के बाद हुए धरना-प्रदर्शन के दौरान नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। वहीं, नरेश मीणा के सहयोगी राकेश बैंसला का कहना है कि सरकार उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर गई है और पंचायत चुनाव से पहले उन्हें जेल में रखकर किसानों और छात्रों की आवाज दबाना चाहती है। राकेश बैंसला ने आरोप लगाया कि पहले स्पेशल लोक अभियोजक नियुक्त कर जमानत रद्द कराई गई और अब उनकी संपत्ति का रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे न्यायपालिका के आदेश का सम्मान करते हैं और उन्हें भरोसा है कि अदालत नरेश मीणा को न्याय देगी।

बता दें कि यह मामला 13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान शुरू हुआ था। समरावता गांव में वोटिंग के दिन नरेश मीणा ने उपखंड अधिकारी (एसडीएम) अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसके बाद उनके समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया, वाहनों में आग लगा, और नरेश को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। अगले दिन 14 नवंबर को भारी पुलिस बल ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 59 लोगों को नामजद किया गया था।

स्मैक के साथ पकड़ा गया तस्कर जयपुर पुलिस कस्टडी से फरार

जयपुर23 जुलाई (एजेंसियां)। जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी से एक बदमाश के फरार होने का मामला सामने आया है। हालांकि उसका भागना सफल नहीं हो सका और उसकी आजादी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। पुलिस ने 80 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है और पहले भी पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश कर चुका है। शिवदासपुरा थाना प्रभारी राजेश गौतम ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत टोंक के रहने वाले 39 साल के सतसिंह उर्फ सदौल को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसटी के हेड कॉन्स्टेबल अभय कुमार को सूचना मिली थी कि आरोपी टोंक रोड पर बड़खेड़ा टोल प्लाजा के पास घूम रहा है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो पुलिस को देख आरोपी ट्रक के पीछे छिप गया था। लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया था।

फर्जी ई-मेल से 104 टेंडर पास कराने वाला अफसर बेनकाब

जयपुर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। जल जीवन मिशन में करोड़ों के घोटाले की कहानी एक शिकायत से शुरू होती है। इरकॉन इंटरनेशनल के नाम पर लगाए गए अनुभव और कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्रों की सत्यता पर सवाल उठाते हुए एक शिकायत आई और मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा। इसके बाद विभाग ने दस्तावेजों की वास्तविकता जांचने के लिए अधिकारी को केरल भेजा। यही वह पड़ाव था, जहां फर्जीवाड़ा रुक सकता था। लेकिन इसके बाद घटनाक्रम ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। विभाग ने शाहपुरा के तत्कालीन एक्सईएन विशाल सक्सेना को केरल के कट्टप्पना और इडुक्की भेजा। कट्टप्पना के होटल वूडलार्क के रिकॉर्ड के अनुसार, उसी अवधि में महेश मित्तल, उसके सहयोगी संजीव गुप्ता और मुकेश पाठक भी वहीं ठहरे हुए थे। जांच में शामिल रिकॉर्ड, लोकेशन इनकी एक ही अवधि में मौजूदगी दर्ज करते हैं।

रिकॉर्ड पर यह भी है कि महेश मित्तल ने अलग कमरा नहीं लिया, संजीव गुप्ता के साथ ही ठहरे। सत्यापन के दौरान जिन परियोजनाओं का हवाला दस्तावेजों में दिया गया था, उनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला, लेकिन झूठी रिपोर्ट भेजी गई।

हाईकोर्ट का सरकार को आदेशः ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आए या नहीं, 15 अगस्त तक पूरी करें आरक्षण की लॉटरी

जयपुर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी राजनीतिक आरक्षण आयोग को स्पष्ट समय-सीमा तय करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि अब चुनाव कराने में किसी भी तरह की और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि आगे भी विलंब हुआ तो जवाबदेही तय की जाएगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने 20 जुलाई को सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग (राजनीतिक आरक्षण) के सचिव को वर्चुअली उपस्थित किया। सरकार ने अदालत को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 19 जुलाई को हुई बैठक का निर्णय और प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम सौंपा।

हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक आरक्षण पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट देने में पहले ही पर्याप्त देरी हो चुकी है। इसलिए आयोग हर हाल में 5 अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपे। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस समय-सीमा में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।

खंडपीठ ने कहा कि आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक सप्ताह या अधिकतम आठ दिन पर्याप्त हैं। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग को 15 अगस्त 2026 तक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर देना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि आरक्षण की पूरी प्रक्रिया इसी अवधि में पूरी करने का प्रयास किया जाए।

हाईकोर्ट ने सबसे अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी कारणवश 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है, तब भी आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि चुनाव में और देरी न हो। अदालत ने साफ किया कि चुनाव टालने का आधार अब रिपोर्ट का इंतजार नहीं हो सकता।

बाइक को गाय से बचाने का प्रयास, ट्रक की चपेट में आए 3 भाइयों की मौत

करौली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। जिले के मैग्जीन क्षेत्र के समीप दर्दनाक सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों की मौत हो गई। इस दौरान मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे के बाद तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो युवकों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

पुलिस के अनुसार एक मोटरसाकिल पर सवार तीन युवक जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर सामने आई गाय से बचने के प्रयास में मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई और ट्रक की चपेट में आ गई। इससे हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां भीमनगर निवासी आशीष और धौलपुर के पुरानी छावनी स्थित डगरिया मोहल्ला निवासी पवन पुत्र चंद्रप्रकाश कश्यप (21) को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं भीमनगर पांडे का कुआं करौली निवासी हर्ष पुत्र राजू कश्यप को गंभीर हालत में भर्ती किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

तीनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उधर घटना की सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक पवन के भाई पारस ने बताया कि पवन फूड डिलीवरी का कार्य करता था। जबकि हर्ष एक होटल में कार्य करता था और आशीष एक दुकान पर कार्य करता था। मरने वाले युवक रिश्ते में भाई थे और तीनों अच्छे दोस्त थे।

एएनटीएफ ने राजस्थान, एमपी व गुजरात में फैले नशे के साम्राज्य का मुख्य सूत्रधार चित्तौड़गढ़ से दबोचा

जयपुर, 23 जुलाई (एजेंसियां)। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन मदार्कभ के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक वर्ष से फरार चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर सुखलाल आंजना को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात में सक्रिय अंतरराज्यीय अफीम तस्करी नेटवर्क का प्रमुख कड़ी माना जाता है।

महानिरीक्षक पुलिस, एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. के निर्देशन में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। आरोपी पर दौसा पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था और वह करीब एक वर्ष से फरार चल रहा था।

आईजी विकास कुमार के अनुसार आरोपी सुखलाल ने 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद खेती-बाड़ी शुरू की थी। उसमें मुनाफा न होने पर उसने शराब के ठेके लिए, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान और कर्जा हो जाने के कारण उसने जल्द अमीर बनने की चाहत में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का रास्ता चुना।

ऑनलाइन बैंक एफडी तोड़कर की 18.93 लाख की ठगी, आरोपी रिमांड पर भेजा गया

बारां, 23 जुलाई (एजेंसियां)। बारां में ऑनलाइन बैंक एफडी तोड़कर 18.93 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। साइबर थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि ऑनलाइन बैंक एफडी तोड़कर 18.93 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने मध्यप्रदेश के मैहर निवासी आरोपी विनोद सिंह को गिरफ्तार किया था। जिसे न्यायालय में पेश किया गया। रिमांड के दौरान आरोपी से गिरोह के अन्य सदस्यों, ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों, मोबाइल सिम, साइबर नेटवर्क और ठगी की राशि के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। जांच का फोकस बिहार और रीवा मध्यप्रदेश से जुड़े उन आरोपियों तक पहुंचने पर है, जो इस साइबर ठगी गिरोह का संचालन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी भोले-भाले लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते और मोबाइल सिम हासिल कर साइबर ठगों को उपलब्ध कराता था।

बांध उड़ाने के लिए चुराई थी शिवपुरी के किले से तोप!

इनपुट मिले तो करौली में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी

शिवपुरी, 23 जुलाई (एजेंसियां)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित प्रसिद्ध और प्राचीन नरवर किले से चोरी हुई ऐतिहासिक तोप के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले की पड़ताल कर रही शिवपुरी पुलिस को पड़ोसी राज्य राजस्थान के करौली से बेहद अहम इनपुट मिले हैं, जिसके आधार पर चोरों की धरपकड़ के लिए राजस्थान सीमा में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बता दें कि 15 जुलाई 2026 को नरवर किले से यह बेशकीमती तोप चोरी हुई थी, जिसके बाद से ही स्थानीय इतिहास प्रेमियों में भारी आक्रोश था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। इस हाई-प्रोफाइल चोरी में सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आया है। सूत्रों और स्थानीय चर्चाओं के मुताबिक, इस प्राचीन तोप को किसी सामान्य चोरी के इरादे से नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और विशेष मकसद से चुराया गया था।

दावा किया जा रहा है कि चोर इस तोप के जरिए एक बड़े मिट्टी के बांध को उड़ाने की साजिश रच रहे थे। हालांकि, प्रशासनिक या पुलिस अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर इस बांध उड़ाने की थ्योरी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस इनपुट के बाद एमपी और राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। जांच में यह साफ हुआ है कि आरोपी तोप चुराने के तुरंत बाद उसे राजस्थान सीमा में ले गए। इसके बाद शिवपुरी पुलिस ने करौली पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर संयुक्त रणनीति तैयार की और संदेहास्पद ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों के बेहद करीब पहुंचा जा चुका है।

बीआरएस की मांग : मुफ़्त इंदिराम्मा घर और खाली पड़े 39,000 2बीएचके घरों का तुरंत आवंटन हो

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। बीआरएस ने गुरुवार को मांग की कि कांग्रेस सरकार गरीबों को 6 लाख रुपये प्रति यूनिट की दर से इंदिराम्मा घर देने का अपना प्रस्ताव वापस ले और इसके बजाय अपने चुनावी वादे के अनुसार मुफ़्त आवास उपलब्ध कराए।

पार्टी ने हैदराबाद में खाली पड़े और 39,000 डबल-बेडरूम घरों के तुरंत आवंटन की भी मांग की।

विधानसभा मीडिया पॉइंट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, बीआरएस विधायक दल के उप-नेता तलसानी श्रीनिवास यादव ने पार्टी विधायकों और एमएलसी के साथ कहा कि पिछली बीआरएस सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद में एक लाख डबल-बेडरूम घर बनाए थे। हालाँकि, उन्होंने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपने 30 महीने के कार्यकाल में शहर में एक भी घर नहीं बना पाई है। पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इंदिराम्मा आवास योजना के तहत केवल 7,000 से 8,000 घर बनाने की योजना बना रही है और लाभार्थियों से लगभग 6 लाख रुपये का योगदान करने के लिए कह रही है, जबकि चुनाव से पहले मुफ़्त घर देने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा, "अगर सरकार घर बनाती है और उन्हें गरीबों को मुफ़्त में देती है, तो हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन हम लाभार्थियों से पैसे लेकर सिंगल-बेडरूम घर देने की बात स्वीकार नहीं करेंगे।" उन्होंने कांग्रेस सरकार पर गरीबों को मुफ़्त आवास देने के अपने वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस सरकार ने लॉटरी सिस्टम के ज़रिए मुफ़्त डबल-बेडरूम घर उपलब्ध कराए थे, जिसमें सचिवालय के आस-पास की प्रमुख जगहें भी शामिल थीं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर सड़क किनारे सामान बेचने वालों के खिलाफ़ केस दर्ज करने का आरोप लगाया और हैदराबाद की मौजूदा नागरिक समस्याओं को नज़रअंदाज़ करते हुए 'फोर्थसिटी' बनाने के प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित करने की आलोचना की। श्रीनिवास यादव ने मांग की कि सरकार तुरंत 39,000 तैयार डबल-बेडरूम वाले घर पात्र लाभार्थियों को बांटे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बीआरएस की मांग मान लेती है और घर मुफ़्त में देती है, तो पार्टी मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी का सार्वजनिक रूप से सम्मान करेगी।

शिवाजी की मूर्ति लगाने को लेकर तनाव

वारंगल, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। गुरुवार को जिले के वारंगल मंडल के बोल्लिकुंटा गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने को लेकर तनावपूर्ण माहौल बन गया। हिंदू समूहों और बीजेपी की ओर से स्थानीय चौराहे पर मूर्ति लगाने की योजना के बाद, मूर्ति लगाने का समर्थन करने वाले लोग बड़ी संख्या में गांव में इकट्ठा हुए। इसी तरह, दलित समूह और वे लोग भी गांव में इकट्ठा हुए जो डॉ. बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति के बगल में शिवाजी की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे थे। चूंकि गांव दो गुटों में बंटा हुआ है और तनाव बढ़ गया है, इसलिए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

भद्राचलम के एक व्यक्ति ने एपीके साइबर फ्रॉड में 55,894 गंवाए

कोठागुडेम, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। जिले के भद्राचलम शहर में एक व्यक्ति साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया और उसने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस के अनुसार, शहर की अशोक नगर कोठा कॉलोनी के निवासी और इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले यर्रमसेट्टी रामू को 29 जून को एक अज्ञात व्यक्ति से वाट्सअप पर "आरटीए चालान के विवरण वाली एक एपीके फ़ाइल मिली। इसे असली समझकर, उसने फ़ाइल खोली और इंस्टॉल कर ली। कुछ समय बाद, उसे एसएमएस अलर्ट मिलने लगे जिनसे पता चला कि उसके बैंक खाते से पैसे कट गए हैं। अपना खाता चेक करने पर, उसने पाया कि कई ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए 55,894 की राशि निकाल ली गई थी। इसके बाद उसने साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसे एक एक्नॉलेजमेंट (पावती) जारी की गई। बाद में, आगे के ट्रांज़ैक्शन को रोकने के लिए उसके बैंक खाते में मौजूद पैसे को होल्ड पर डाल दिया गया। इलेक्ट्रीशियन की शिकायत के आधार पर, पुलिस सब-इंस्पेक्टर वुडुम सतीश ने आरोपी के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की।

हाल ही में, भद्राचलम में कई साइबर अपराधों की सूचना मिली है। शहर की मेडिकल कॉलोनी के एक रिटायर्ड कर्मचारी वेमुला जनार्दन रेड्डी ने जनवरी में साइबर अपराध में 2.28 लाख गंवा दिए थे। रेड्डीपालेम गांव के एक युवक आकाश ने मई में ओएलएक्स फ्रॉड में 50,000 कीमत का अपना स्मार्टफोन गंवा दिया था।

रघु वंशी एयरोस्पेस तेलंगाना में सुपरअलॉय प्लांट में 600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। रघु वंशी एयरोस्पेस ग्रुप ने तेलंगाना में 600 करोड़ रुपये से अधिक के नियोजित निवेश के साथ 50 एकड़ में फैली इंटीग्रेटेड सुपरअलॉय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की। यह घोषणा दुनिया की प्रमुख एयरोस्पेस और डिफेंस प्रदर्शनियों में से एक, फार्नबोरो इंटरनेशनल एयरशो 2026 के उद्घाटन के दिन की गई।

यह फैसिलिटी उच्च गुणवत्ता वाले निकेल-बेस्ड सुपरअलॉय के लिए भारत के कुछ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से एक होगी, जिसमें अत्याधुनिक वैक्यूम मेल्टिंग प्रक्रिया, फोर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट, वैक्यूम कास्टिंग, पाउडर मेटलर्जी और अन्य फॉर्मिंग क्षमताएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। लगभग 5,000 टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ डिज़ाइन की गई इस इकाई में राउंड बार, तार, फोर्जिंग, कास्टिंग, टंगस्टन कार्बाइड पाउडर और अन्य विशेष उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। निकेल-बेस्ड सुपरअलॉय एयरो इंजन, स्पेस सिस्टम, डिफेंस प्लेटफॉर्म, गैस टर्बाइन, तेल और गैस, परमाणु ऊर्जा, मेडिकल इम्प्लांट और उभरती हुई हाइड्रोजन तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत वर्तमान में अपनी निकेल अलॉय की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है।

इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व डॉ. एस.के. झा करेंगे, जो भारत की प्रमुख स्पेशल मेटल्स निर्माता कंपनी, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं।

हैदराबाद में स्थापित, रघु वंशी एयरोस्पेस ग्रुप एक ग्लोबल प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग और डीप-टेक कंपनी के रूप में विकसित हुआ है जो एयरोस्पेस, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर को सेवाएं प्रदान करती है।

उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने आज की परीक्षाएं टाली

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को 24 जुलाई को होने वाली सभी परीक्षाएं टाल दीं। यूनिवर्सिटी ने यह फैसला वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आह्वान को देखते हुए लिया। ये संगठन दिल्ली में नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मुद्दे पर हाल ही में हुए 'चलो संसद मार्च' के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे। ओयू ने कहा कि स्थगित परीक्षाओं के लिए संशोधित शेड्यूल/समय-सारणी की जानकारी उचित समय पर दी जाएगी।

गांजे बेचने के आरोप में दुकानदार गिरफ्तार

> 500 ग्राम गांजा ज़ब्त

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। बुधवार को प्रोहिबिशन और एक्साइज़ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हैदराबाद में अपनी दुकान से गांजे के पैकेट बेचने के आरोप में एक पान की दुकान के मालिक को गिरफ़्तार किया। उसके पास से कुल 500 ग्राम गांजा ज़ब्त किया गया। एक गुप्त सूचना के आधार पर, एक टीम ने माधापुर रोड पर चंदा नायक नगर स्थित सोहेल पान शॉप पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान, अधिकारियों को छोटी पुड़ियाओं में पैक किया गया 500 ग्राम गांजा मिला, जिसे कथित तौर पर खुदरा बिक्री के लिए रखा गया था।

इंस्पेक्टर नागराजू के अनुसार, दुकान का मालिक कथित तौर पर बड़ी मात्रा में गांजा खरीदता था या 10 ग्राम के पैकेट लगभग 300 रुपये में खरीदकर उन्हें 500 रुपये में बेचता था, और इस तरह नशीले पदार्थों की बिक्री से अवैध मुनाफ़ा कमाता था। इस ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध मलिक असलम उर्फ टॉम बोली को गिरफ़्तार किया गया। ज़ब्त किए गए गांजे और आरोपी को आगे की जांच और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए माधापुर एक्साइज़ स्टेशन को सौंप दिया गया।

बिना मंज़ूरी के इलाज करने वाले डॉक्टर चिन्हित

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ने रविवार को अलवाल में जांच के दौरान ऐसे क्लीनिक और नर्सिंग होम का पता लगाया, जिन्हें ऐसे लोग चला रहे थे जिनके पास ज़रूरी योग्यता, रजिस्ट्रेशन या कानूनी मंज़ूरी नहीं थी।

जांच के दौरान, डॉ. गुंडागानी श्रीनिवास और डॉ. इमरान सहित टीजीएमसी की टीम को अलवाल में गोपु श्रीनिवास द्वारा चलाया जा रहा 'शंकर शशांका क्लीनिक' मिला। वह बिना वैध लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के एलोपैथी का अभ्यास कर रहे थे और उन्होंने एफएमजी परीक्षा पास नहीं की थी। 'श्री साई पॉली क्लीनिक' में, फिजियोथेरेपिस्ट जी. जानकी रामुलु कथित तौर पर अपनी मंज़ूर सीमा से बाहर जाकर एलोपैथिक दवाएं लिख रहे थे।

'कोमल क्लीनिक' में, टीम को सुदर्शन नाम का व्यक्ति मिला जो ज़रूरी योग्यता और मंज़री के बिना एलोपैथिक इलाज कर रहा था। इसी तरह, 'शेभा क्लीनिक' में, क्रिस्टोफर नाम का व्यक्ति कथित तौर पर ज़रूरी मेडिकल योग्यता के बिना आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास कर रहा था।

टीम ने देखा कि ऐसे बिना मंज़ूरी वाले डॉक्टर कथित तौर पर स्टेरॉयड, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक इंजेक्शन और डॉक्टर की सलाह से दी जाने वाली अन्य दवाएं बिना सोचे-समझे दे रहे थे, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और कानूनों के तहत मामले दर्ज करेगी। आम जनता को सलाह दी गई कि वे केवल योग्य डॉक्टरों से ही इलाज कराएं जो तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के साथ विधिवत रजिस्टर्ड हों। नकली या बिना मंज़ूरी वाले डॉक्टरों के बारे में जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से दी जा सकती है।

ग्रुप-1 पेपर लीक मामले में दासोजू श्रवण ने सीएम से इस्तीफ़े की मांग की

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, बीआरएस एमएलसी दासोजू श्रवण ने टीजीपीएससी ग्रुप-I पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से इस्तीफ़े की मांग की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी भी इस विवाद के लिए उतने ही ज़िम्मेदार हैं, जितना कि कांग्रेस कथित नीट पेपर लीक के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज़िम्मेदार ठहरा रही है।

गुरुवार को बीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, श्रवण ने सवाल किया कि कांग्रेस नेता प्रधान के इस्तीफ़े की मांग क्यों कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप-I मुद्दे पर रेवंत रेड्डी के इस्तीफ़े की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास इस मुद्दे पर विरोध करने का नैतिक अधिकार नहीं है।

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया; गांधी ने नई दिल्ली में छात्रों के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई की निंदा की, लेकिन हैदराबाद में अपनी ही कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोज़गार युवाओं पर कथित लाठीचार्ज पर चुप रहे।

श्रवण ने मुख्यमंत्री के उन आरोपों का मज़ाक उड़ाया जिनमें बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव को तेलंगाना में 2019 की इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी से जोड़ा गया था, जबकि NEET पेपर लीक विवाद पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। उन्होंने कहा कि रामा राव ने पिछले दो वर्षों में जीओ 29, 46 और ग्रुप-I परीक्षा से जुड़े मुद्दों का विरोध करके बेरोज़गार युवाओं का लगातार समर्थन किया है।

इस बीच, बीआरएस के मेडचल-मलकजगिरी ज़िला अध्यक्ष और एमएलसी शंभीपुर राजू ने घोषणा की कि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष शुक्रवार को अपने जन्मदिन के जश्न से दूर रहेंगे। इसके बजाय, रामा राव इंदिरा पार्क में बीआरएसवी के उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे जो नीट के मुद्दे और दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ छात्रों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने छात्रों और युवाओं से बड़ी संख्या में बीआरएसवी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।

केटीआर के जन्मदिन पर देशव्यापी फ़ूड डोनेशन ड्राइव

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। बिज़नेसमैन नयिनी अनुराग रेड्डी ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव के 50वें जन्मदिन के मौके पर गिफ़्ट ए स्माइल के बैनर तले देशव्यापी फ़ूड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया। यह पहल रामा राव की दयालु जनसेवा की सोच से प्रेरित थी।

गिफ़्ट ए स्माइल बियॉन्ड बाउंड्रीज़, स्प्रेडिंग स्माइल्स अक्रॉस इंडिया (सीमाओं से परे मुस्कान का उपहार, पूरे भारत में मुस्कान फैलाना) थीम के तहत आयोजित इस कैंपेन में 28 राज्य शामिल थे। वॉलंटियर्स और पार्टनर एनजीओ की मदद से ज़रूरतमंद समुदायों को लगभग 3,500 ताज़ा बने भोजन परोसे गए।

हैदराबाद की सड़कों से लेकर वाराणसी के घाटों तक और बड़े शहरों से लेकर दूर-दराज़ के इलाकों तक, वॉलंटियर्स ने ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हाथ मिलाया। इस कैंपेन का सबसे यादगार आयोजन वाराणसी के घाटों पर हुआ, जहाँ सैकड़ों लोगों को भोजन कराया गया।

रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या की कोशिश कर रहे युवक की जान बचाई

महाबूबाबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। अपनी जान जोखिम में डालकर महाबूबाबाद पुलिस ने एक युवक को बचाया, जिसने महाबूबाबाद रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या की कोशिश की थी। सूत्रों के अनुसार, महाबूबाबाद रूरल सीआई अंजलि को बुधवार तड़के करीब 2:44 बजे डीजी कंट्रोल रूम से एक ज़रूरी संदेश मिला कि महाबूबाबाद में एक युवक आत्महत्या के इरादे से रेलवे ट्रैक पर लेटा हुआ है।

तेज़ी से कार्रवाई करते हुए, सीआई अंजलि ने वायरलेस कम्युनिकेशन के ज़रिए अपनी टीम को अलर्ट किया। तुरंत हरकत में आते हुए, वह SI सुदर्शन, ब्लू कोल्ट्स के जवानों और पुलिस स्टाफ के साथ बिना एक मिनट बर्बाद किए रेलवे ट्रैक की ओर दौड़ीं। वे अंधेरे में ट्रैक के किनारे-किनारे दौड़ते हुए युवक को ढूंढ रहे थे।

हालाँकि, उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा था; क्योंकि वह ट्रैक पर सीधा लेटा हुआ था और अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। तभी, मनुगुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस उनकी ओर तेज़ी से आ रही थी और बिल्कुल आखिरी पल में, युवक ट्रैक पर दिखाई दिया।

अगर एक मिनट की भी देरी होती, तो एक कीमती जान ट्रेन के पहियों के नीचे कुचल जाती। फिर भी, सीआई अंजलि और उनकी टीम ने अपनी जान के खतरे की परवाह नहीं की - जबकि ट्रेन के पास जाना बहुत जोखिम भरा था - और उन्होंने युवक को बचा लिया।

बाद में युवक की पहचान कोठागुडेम ज़िले के येल्लांडु निवासी शेख वसीम (26) के तौर पर हुई। इसके बाद उसे महाबूबाबाद टाउन पुलिस स्टेशन लाया गया और काउंसलिंग की गई। उसके माता-पिता को सूचित किया गया और उसे उन्हें सौंप दिया गया। महाबूबाबाद के एसपी डॉ. सबरीश पी ने सीआई अंजलि, एसआई सुदर्शन, ब्लू कोल्ट्स के जवानों और अन्य पुलिस कर्मचारियों की तारीफ़ की। उन्होंने एक कीमती जान बचाने में उनकी सूझ-बूझ, हिम्मत और सेवा के प्रति समर्पण की सराहना की।

क्रेडाई प्रॉपर्टी शो 2026, 28 से 30 अगस्त तक हाइटेक में होगा

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। क्रेडाई हैदराबाद के सीनियर लीडर्स, जिनमें प्रेसिडेंट एन जयदीप रेड्डी और प्रेसिडेंट-इलेक्ट बी जगन्नाथ राव शामिल हैं, ने घोषणा की कि क्रेडाई हैदराबाद प्रॉपर्टी शो 2026, 28 से 30 अगस्त तक हाइटेक एग्ज़िबिशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा।

जयदीप रेड्डी ने कहा कि खरीदार अक्सर इस उम्मीद में इंतज़ार करते रहते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन हैदराबाद की सच्चाई यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है और अच्छी जगहों की मांग लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा, इस अगस्त में सबसे अच्छे रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स को एक ही जगह पर लाकर, हम परिवारों को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वे इंतज़ार करना छोड़ें, आगे बढ़ें और आज ही एक सुरक्षित भविष्य के लिए इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी शो में, घर खरीदने वाले 100 से ज़्यादा रेरा-अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स को देख-परख सकते हैं, डेवलपर्स से सीधे बात कर सकते हैं, बड़े बैंकों से तुरंत फाइनेंशियल जानकारी पा सकते हैं और पूरी तसल्ली के साथ घर लौट सकते हैं। जगन्नाथ राव ने कहा, अच्छी जगहों पर प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती रहेंगी और मांग भी बढ़ेगी। घर खरीदने में आप जितना ज़्यादा इंतज़ार करेंगे, वह उतना ही महंगा होता जाएगा।

इसलिए, हम आपसे अभी खरीदने का आग्रह करते हैं।इस एग्ज़िबिशन में पूरे हैदराबाद में अपार्टमेंट, विला, प्लॉटेड डेवलपमेंट और ऑफिस स्पेस समेत कई तरह के रेजिडेंशियल और कमर्शियल ऑप्शन दिखाए जाएंगे।

राजपूत समाज का वार्षिक कार्यक्रम संपन्न

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। राजपूत समाज का वार्षिक कार्यक्रम 'आषाढ़ के बगीचे', 19 जुलाई को महाराणा प्रताप फंक्शन पैलेस, अंबरपेट में संपन्न हुआ। सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राजपूत समाज के अध्यक्ष गोपाल सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की। मुंबई से आए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ महासचिव हरगोविंद सिंह तोमर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि राजपूत समुदाय ने अपने अनूठे उत्सव को हैदराबाद में पुनर्जीवित कर दिया है। नरेंदर सिंह ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस समारोह में मुंबई से वीरेंद्र सिंह और विनोद सिंह; क्षत्रिय राजपूत ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष कुंदन सिंह और सचिव रघुनंदन सिंह; क्षत्रिय राजपूत सभा के अध्यक्ष जयवीर सिंह; अनूप कुमार सिंह आदि बडी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे।

मिनी ट्रक में लगी आग

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। गुरुवार को बाचुपल्ली-मियापुर रोड पर अर्बनराइज के सामने एक मिनी ट्रक में आग लग गई, जिससे आने-जाने वालों में घबराहट फैल गई। हालांकि, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आने-जाने वालों से सूचना मिलने पर बाचुपल्ली पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और गश्ती वाहन में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया। उनकी त्वरित कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को रोक दिया और यह सुनिश्चित किया कि आग पूरे वाहन या उसमें लदे सामान को अपनी चपेट में न ले।

नाबालिग से शादी करने पर पाक्सो केस दर्ज

कोठागुडेम, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। जिले के बुरगमपाड पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ पाक्सो मामला दर्ज किया गया है। बुरगमपाड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इंटरमीडिएट के दूसरे वर्ष की छात्रा बताई जा रही यह लड़की बुधवार को लापता हो गई थी। आरोपी युवक, जो असवापुरम मंडल के कल्याणपुरम का रहने वाला है, नाबालिग लड़की को ले गया और उससे शादी कर ली।

रात का खाना खाने के बाद 30 छात्राएं बीमार

मंचेरियल, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। बुधवार रात बेल्लमपल्ली में सरकारी महात्मा ज्योतिबा फुले रेजिडेंशियल स्कूल (गर्ल्स) में बासी खाना खाने के बाद लगभग 30 छात्राएं बीमार पड़ गईं।

अभिभावकों ने बताया कि रात 9 बजे खाना खाने के बाद छात्राओं को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बाद में आधी रात तक उन्हें छुट्टी दे दी गई। हालांकि, गुरुवार सुबह उन्हें फिर से उल्टी और पेट दर्द की समस्या हुई।

अभिभावकों ने इस घटना पर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि छात्राओं को साफ़-सुथरा खाना मिले। उन्होंने अधिकारियों से भविष्य में फ़ूड पॉइज़निंग की ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय करने का भी अनुरोध किया। अधिकारियों ने कहा कि खाने के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे।

प्रथम पृष्ठ का शेष भाग

अभिषेक बनर्जी को ...

अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनके खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भवानीपुर, सिलीगुड़ी, नकाशीपाड़ा और विष्णुपुर समेत राज्य के विभिन्न थानों में अभिषेक के खिलाफ आठ एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने इन सभी मामलों में अभिषेक को कानूनी संरक्षण देने का अनुरोध किया। सिब्बल ने दलील दी कि पहले भी कई एफआईआर के मामले में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी को अदालत से संरक्षण मिला था।

राहुल बोले-पीएम ...

एक छात्र के शरीर पर बंदूक के छर्रे दिखाई दिए। हालांकि, पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल के दावे को खारिज किया है।

घायल छात्रों की चीख-पुखार : छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस अचानक उन पर लाठीचार्ज कर देती है। वीडियो में दिखाया गया कि किसी छात्रों के सिर से खून बह रहा तो किसी छात्र को पुलिस घसीट रही है।

पेपर लीक में अभी तक कोई सजा नहीं :

राहुल की दूसरी स्लाइड पेपर लीक के आंकड़ों से जुड़ी थी। राहुल ने कहा- अब तक 152 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। जिससे 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए लेकिन पेपर लीक करने वालों को कोई सजा नहीं मिली।

नीट का खर्च देश के शिक्षा बजट से ज्यादा :राहुल ने कहा- 10 साल में 152 पेपर देश में लीक हुए हैं। इनमें किसी भी मामले में किसी को भी सजा नहीं मिली। 1.4 लाख करोड़ भारत सरकार का एजुकेशन बजट है। 1.32 लाख करोड़ भारतीय परिवार नीट एग्जाम पर खर्च करते हैं। नीट का खर्च देश के शिक्षा बजट से ज्यादा है।

समय और तारीख तय ...

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं विपक्ष जितने भी समय इस विषय पर चर्चा चाहता है, हम बिल्कुल तैयार हैं। रिजिजू ने लोकसभा में कहा, आज सभी एनडीए सदस्यों ने भी प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि नीट पेपर लीक पर तुरंत और पूरे देश में चर्चा हो।

उन्होंने कहा कि यह किसी सरकार या दल का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, सभी पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। हमको इस विषय पर बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी दलों को एकजुट होकर छात्रों के हित को लेकर चर्चा करनी चाहिए। रिजिजू ने लोकसभा में मांग की कि बिना देरी के नीट पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए।

मेट्रो स्टेशन बंद ...

अगर मेरे हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा। दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सीजेपी के 'चलो संसद' प्रदर्शन और सुरक्षा कारणों के चलते राजीव चौक और केन्द्रीय सचिवालय सहित 16 मेट्रो स्टेशन सुबह साढ़े सात बजे से अगले निर्देश तकबंद रखने का एलान किया।

सीजेआई ने यह भी बताया कि उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वकीलों की अनुपस्थिति के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाए। दिल्ली मेट्रो ने गुरुवार सुबह अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की थी। इनमें सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भी शामिल है।

गड़बड़ गोला-बारूद ...

इससे आर्मी में भारी कमी आई और पुरानी तोपों का इस्तेमाल जारी रहा जिनकी फायरपावर सीमित है। समिति ने कहा कि एमओडी को स्टॉक की नियमित समीक्षा, कैपेबिलिट गैप्स की पहचान और उभरते खतरों के अनुसार समय पर खरीद का मजबूत तंत्र बनाना चाहिए।

धनुष तोप पर इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन की खामियां :

स्वदेशी 155एमएम/45 कैलिबर धनुष तोप प्रोजेक्ट को पीएसी ने सराहा लेकिन उत्पादन में आई देरी पर नाराजगी जताई। समिति ने कहा कि प्रोडक्शन मेथडोलॉजी धीरे-धीरे विकसित हुई क्योंकि भारत में पहले कभी ऐसी एडवांस तोप नहीं बनाई गई थी। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जरूरत के अनुरूप नहीं था।

डीपीएसी एमओडी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उसने सिफारिश की कि ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले घरेलू क्षमताओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि देरी और लागत बढ़ोतरी रोकी जा सके। घरेलू निर्माताओं को ज्यादा आर&डी सपोर्ट देने पर जोर दिया गया।

स्किल और क्षमता की कमी : विशेषज्ञता की दरकार :

रिपोर्ट में बैलिस्टिक एक्सपर्टीज, गन इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस्ड साइटिंग सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने वाली तकनीकी कमी को देरी का बड़ा कारण बताया गया। हालांकि बाद में स्वदेशी प्रयासों से इन गैप्स को पूरा किया गया लेकिन पीएसी ने कहा कि इन्हें प्रोजेक्ट मंजूरी के समय ही पहचान लिया जाना चाहिए था। समिति ने आईआईटी और टेक संस्थानों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स शुरू करने और डीपीएसयू कर्मियों के नियमित अपस्किलिंग का सुझाव दिया। इससे भारत वैश्विक स्तर के स्टैंडर्ड को मैच कर सकेगा। पीएसी ने स्वीकार किया कि धनुष तोप ने बोफोर्स के पार्ट्स की कॉमनलिटी के कारण रखरखाव में मदद की। लेकिन उत्पादन में देरी से आर्टिलरी डिवीजन की ऑपरेशनल तैयारी प्रभावित हुई। समिति ने एमओडी की निर्णय प्रक्रिया में ढांचागत बदलाव, बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और वेंडर्स के लिए सख्त टाइमलाइंस की मांग की।

फीफा ने चुनी टूर्नामेंट की बेस्ट-11 : छह गोल करने वाला दिग्गज हैरी केन बाहर, स्पेन के सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ी

न्यूयॉर्क, 23 जुलाई (एजेंसियां)। फीफा ने विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट (बेस्ट 11) का एलान कर दिया है। इस टीम में कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन कुछ फैसलों ने फुटबॉल प्रशंसकों को चौंका दिया। सबसे बड़ा सरप्राइज इंग्लैंड के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन का टीम में जगह नहीं बना पाना रहा, जबकि केप वर्डे के अनुभवी गोलकीपर वोजिन्हा को शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला। विश्व कप विजेता स्पेन और तीसरे स्थान पर रही फ्रांस के तीन-तीन खिलाड़ियों को इस टीम में जगह मिली है, जबकि उपविजेता अर्जेंटीना के दो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं।

विश्व कप 2026 में केप वर्डे ने अपने बेखौफ खेल से सभी को प्रभावित किया। टीम पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही और राउंड ऑफ-32 में केवल अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना से हारकर बाहर हुई।

40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा ने पूरे टूर्नामेंट में कई यादगार बचाव किए। उनके प्रदर्शन की तारीफ खुद लियोनल मेसी ने भी की थी।

सोशल मीडिया पर भी उन्हें काफी लोकप्रियता मिली और अब फीफा ने उन्हें टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल कर उनके प्रदर्शन को सम्मान दिया है।

वोजिन्हा को स्पेन के उनाई सिमोन और इंग्लैंड के जॉर्डन पिकफोर्ड जैसे दिग्गज गोलकीपरों पर तरजीह दी गई।

रक्षा पंक्ति में स्पेन के मार्क कुकुरेला और पेड्रो पोरो को फुल-बैक के रूप में चुना गया है। सेंटर-बैक की बात करें तो स्पेन के युवा स्टार पाउ कुबार्सी को जगह नहीं मिली। उनकी जगह फ्रांस के दायोत उपामेकानो और अर्जेंटीना के लिसांद्रो मार्टिनेज को टीम में शामिल किया गया।

विश्व कप 2026 के गोल्डन बॉल विजेता रोड्री का चयन लगभग तय माना जा रहा था। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में स्पेन की मिडफील्ड को शानदार तरीके से संभाला और टीम को विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।उनके साथ इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम और फ्रांस के युवा स्टार माइकल ओलिसे को भी टीम में जगह मिली है। दोनों खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

फॉरवर्ड लाइन में सबसे ज्यादा चर्चा हैरी केन के बाहर होने को लेकर रही। इंग्लैंड के कप्तान होने के बावजूद वह फीफा की सर्वश्रेष्ठ टीम में जगह नहीं बना सके।

उनकी जगह नॉर्वे के एर्लिंग हालंद को सेंटर-फॉरवर्ड चुना गया है। दोनों विंग पर फ्रांस के किलियन एमबाप्पे और अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनल मेसी को शामिल किया गया।

स्पेन ने विश्व कप जीतने के साथ टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा। वहीं, केप वर्डे के वोजिन्हा का चयन इस विश्व कप की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक माना जा रहा है, जबकि हैरी केन का बाहर रहना चयनकर्ताओं के सबसे चर्चित फैसलों में शामिल हो गया।

विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट (बेस्ट 11)

पोजिशन	खिलाड़ी	देश
गोलकीपर	वोजिन्हा	केप वर्डे
डिफेंडर	मार्क कुकुरेला	स्पेन
डिफेंडर	लिसांद्रो मार्टिनेज	अर्जेंटीना
डिफेंडर	दायोत उपामेकानो	फ्रांस
डिफेंडर	पेड्रो पोरो	स्पेन
मिडफील्डर	रोड्री	स्पेन
मिडफील्डर	जूड बेलिंगहम	इंग्लैंड
मिडफील्डर	माइकल ओलिसे	फ्रांस
फॉरवर्ड	किलियन एमबाप्पे	फ्रांस
फॉरवर्ड	एर्लिंग हालंद	नॉर्वे
फॉरवर्ड	लियोनल मेसी	अर्जेंटीना

भारत ने ज़िम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया

वैभव सूर्यवंशी बने टी-20 इंटरनेशनल के सबसे युवा हाफ सेंचुरियन

हरारे, 23 जुलाई (एजेंसियां)। भारत ने पहले टी-20 में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। हरारे में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए।

जवाब में भारत ने 13.2वें ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे ने पहले टी-20 में भारत को 126 रन का टारगेट दिया है। हरारे में टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी 50, ईशान किशन 35 और अभिषेक शर्मा 1 रन बनाकर आउट हुए।

यह श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की पहली जीत भी रही। इससे पहले उन्हें आयरलैंड सीरीज में 2-0 और इंग्लैंड सीरीज में 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था।

सूर्यवंशी ने 15 साल 118 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया। वे टी-20 इंटरनेशनल में फिफ्टी लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 16 साल 56 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाने वाले जिब्राल्टर के लुई ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा।

वेस्ली मधेवेरे ने सबसे ज्यादा 39 रन की पारी खेली। आखिर में तदिवानाशे मरुमानी ने नाबाद 27 रन जोड़कर टीम को 100 के पार पहुंचाया। भारत की ओर से मयंक यादव और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए। मयंक ने पारी की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को आउट किया और फिर डियोन मायर्स का विकेट भी झटका। शिवम दुबे और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट मिला। वेस्ली मधेवेरे रन आउट हुए।

भारत की प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, मयंक यादव और अशोक शर्मा।

पीवी सिंधु को चेन युफेई ने 16-21, 22-20, 21-18 से हराया

बीजिंग, 23 जुलाई (एजेंसियां)। पिछले हफ्ते जापान ओपन सुपर-750 जीतने वाली पीवी सिंधु का चीन ओपन सुपर-1000 का प्री-क्वार्टर फाइनल हार गई हैं। उन्हें गुरुवार को वर्ल्ड नंबर-4 और घरेलू खिलाड़ी चेन युफेई ने 16-21, 22-20, 21-18 से हराया। यह मैच 1 घंटे 29 मिनट तक चला।

चांगझोउ में सिंधु ने पहला गेम जीतकर शानदार शुरुआत की और दूसरे गेम में भी जीत के बेहद करीब पहुंच गई थीं।

उनके पास मुकाबला समाप्त करने के चार मैच प्वाइंट थे, लेकिन वह उन्हें भुना नहीं सकीं। इसका फायदा उठाते हुए युफेई ने लगातार अंक जुटाए और दूसरा गेम 22-20 से जीतकर मैच बराबरी पर ला दिया।

निर्णायक गेम में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन अहम मौकों पर युफेई ने बेहतर संयम दिखाया और 21-18 से जीत दर्ज कर ली।

भारत का जूडो खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल

कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड का दावेदार था

नई दिल्ली, , 23 जुलाई (एजेंसियां)। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से ठीक पहले भारतीय जूडोका अरुण कुमार डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। वे 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल के दावेदार थे। उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया है। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि अरुण से पदक की उम्मीद थी, लेकिन इतने कम समय में उनका विकल्प नहीं चुना जा सकता। मुकेश ने कहा- 'हमें नोटिस मिला है, जिसमें 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। उन्हें जवाब देने का मौका मिलेगा, लेकिन नियमों के तहत वह प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। इतने कम समय में किसी दूसरे खिलाड़ी को शामिल करना भी संभव नहीं है।'

शाहिदी के इस्तीफे के बाद रहमत शाह टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान बने

काबुल, 23 जुलाई (एजेंसियां)। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हश्मतुल्लाह शाहिदी के इस्तीफे के बाद अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह को टेस्ट और वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। रहमानुल्लाह गुरबाज दोनों फॉर्मेट में उपकप्तान होंगे। दोनों आयरलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज से नई जिम्मेदारी संभालेंगे।

रहमत शाह 2021 से अफगानिस्तान की टेस्ट और वनडे टीम के उपकप्तान रहे हैं। एसीबी ने कहा कि रहमत का अनुभव, नेतृत्व क्षमता और टीम की गहरी समझ अफगानिस्तान क्रिकेट को आगे नई सफलताएं दिलाएगी।

हश्मतुल्लाह शाहिदी को मई 2021 में कप्तान बनाया गया था। उनके नेतृत्व में अफगानिस्तान ने 55 वनडे में 27 जीत दर्ज की। 2023 वनडे विश्व कप में टीम ने इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और नीदरलैंड को हराकर छठा स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन के दम पर अफगानिस्तान ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया, जहां पहले ही अभियान में इंग्लैंड को हराकर पांचवें स्थान पर जगह बनाई।

शाहिदी की कप्तानी में अफगानिस्तान पहली बार आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में सातवें स्थान तक पहुंचा। टीम ने 2024-25 में लगातार पांच वनडे सीरीज जीतीं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत भी शामिल रही। बांग्लादेश के खिलाफ लगातार तीन वनडे सीरीज जीतना भी उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों में रहा।

क्या नीरज चोपड़ा नहीं जीतेंगे कॉमनवेल्थ गोल्ड

ओलिंपिक और खेल संघों की इंटरनल रिपोर्ट- भारत 28 साल में सबसे कमजोर प्रदर्शन कर सकता है

खेल डेस्क, 23 जुलाई (एजेंसियां)। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के सामने 28 साल में अपने सबसे कमजोर प्रदर्शन का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय ओलिंपिक संघ और अलग-अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को पैरा स्पोर्ट्स सहित 13 खेलों में 31 पदक मिलने का अनुमान है, जिसमें सिर्फ 6 गोल्ड शामिल हैं।

रिपोर्ट में नीरज चोपड़ा को भी गोल्ड का दावेदार नहीं माना गया है। नीरज ने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। वे ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। जिन सात खिलाड़ियों को गोल्ड का दावेदार माना जा रहा था, उनमें से एक अरुण कुमार गुरुवार को डोप टेस्ट में फेल हो गया है। नीचे दी गई तस्वीर में बचे दावेदार देख सकते हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सफलता का आधार शूटिंग, कुश्ती और बैडमिंटन जैसे खेल रहे हैं। इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार पदक जीते हैं। ग्लासगो 2026 के कार्यक्रम में इन तीनों खेलों को शामिल नहीं किया गया है। यही भारत के लिए सबसे बड़ा झटका है।

ग्लासगो 2026 में बर्मिंघम 2022 के 19 की तुलना में सिर्फ 10 खेल होंगे। भारत के कई मेडल स्पोर्ट्स शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, स्क्वैश और क्रिकेट इस बार शामिल नहीं हैं। बर्मिंघम में भारत के 61 में से 30 मेडल इन्हीं खेलों से आए थे।

यही वजह है कि इस बार भारत का प्रदर्शन केवल खिलाड़ियों के फॉर्म पर नहीं, बल्कि गेम्स के स्पोर्ट्स प्रोग्राम पर भी निर्भर करेगा।

भारत के कुछ बड़े मेडल दावेदारों की मौजूदा फॉर्म भी चिंता बढ़ा रही है। जेवलिन थ्रो में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा हैं। लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती पहले से ज्यादा कठिन होगी।

उनकी मौजूदा फॉर्म भी पहले जैसी नहीं है और पाकिस्तान के अरशद नदीम के अलावा ऑस्ट्रेलिया के कैमरन मैकिन्टायर जैसे खिलाड़ी भी नीरज को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसलिए रिपोर्ट में नीरज को गोल्ड का दावेदार नहीं माना गया है।

बॉक्सिंग में भारत की उम्मीदें लवलीना बोरगोहेन जैसे बड़े नामों पर होंगी। हालांकि, पिछले कुछ समय में उनका प्रदर्शन उस लेवल का नहीं रहा है, जिसके लिए वे जानी जाती हैं।

भारत के कई अन्य बड़े खिलाड़ियों के साथ भी यही स्थिति है। वे पदक जीतने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हालिया प्रदर्शन के आधार पर उनके गोल्ड मेडल जीतने की गारंटी नहीं दी जा सकती। इस बार शामिल 10 में से 5 खेल स्वीमिंग, साइक्लिंग, जूडो, नेटबॉल और जिम्नास्टिक्स में भारत हमेशा से कमजोर रहा है। इसलिए इस बार भारत के मेडल काउंट में बड़ी गिरावट की आशंका है।

ग्लासगो गेम्स के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत करेगा। अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2030 गेम्स में 15 से 17 खेल शामिल किए जा सकते हैं। इससे भारत को शूटिंग, कुश्ती और बैडमिंटन जैसे अपने मजबूत खेलों को वापस कार्यक्रम में शामिल कराने का फायदा मिल सकता है।

खेलों की संख्या बढ़ने के साथ मेडल इवेंट्स भी बढ़ेंगे, जिससे भारत के पदक जीतने के मौके बढ़ सकते हैं। ऐसे में ग्लासगो 2026 भारत के लिए चुनौतीपूर्ण एडिशन हो सकता है, लेकिन अहमदाबाद 2030 में तस्वीर पूरी तरह बदलने की उम्मीद है।

डूरंड कप की ट्रॉफियां कोलकाता पहुंचीं

कल से शुरू होगा 135वां संस्करण, उद्घाटन मैच किन टीमों के बीच?

कोलकाता, 23 जुलाई (एजेंसियां)। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 135वें संस्करण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। टूर्नामेंट की तीन प्रतिष्ठित ट्रॉफियां ट्रॉफी टूर के तहत कोलकाता पहुंचीं। इसके साथ ही पांचों मेजबान राज्यों की यात्रा पूरी हो गई। कोलकाता में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल सरकार के युवा सेवा एवं खेल तथा उपभोक्ता मामलों के विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. इंद्रनील खान ने ट्रॉफियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ और डूरंड कप आयोजन समिति के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह समेत सेना और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

डूरंड कप का 135वां संस्करण 25 जुलाई से शुरू होगा। उद्घाटन मुकाबला कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा, जिसमें चिर प्रतिद्वंद्वी मोहन बागान सुपर जायंट और ईस्ट बंगाल एफसी आमने-सामने होंगे। कोलकाता में उद्घाटन मुकाबले के अलावा ग्रुप ए और बी के मैच, एक क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत कुल 16 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल 23 अगस्त को होगा।

मंत्री डॉ. इंद्रनील खान ने कहा कि कोलकाता के लिए 16 मुकाबलों की मेजबानी गर्व की बात है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के फुटबॉल प्रेमियों से उद्घाटन मुकाबले से लेकर फाइनल तक स्टेडियम पहुंचकर भारतीय खिलाड़ियों और टीमों का उत्साह बढ़ाने की अपील की।

आयोजन समिति के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह ने कहा कि डूरंड कप भारतीय सेना के सबसे महत्वपूर्ण खेल आयोजनों में से एक है और यह सैन्य-नागरिक साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है। वहीं, बंगाल सब एरिया के जीओसी और आयोजन समिति के उपाध्यक्ष मेजर जनरल दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि पूर्वी कमान के अधीन डूरंड कप का विस्तार 2032 तक होना टूर्नामेंट की बढ़ती लोकप्रियता और सफलता को दर्शाता है। इस बार टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें श्रीलंकाई सशस्त्र बलों की एक विदेशी टीम भी शामिल है। कुल 43 मुकाबले पांच मेजबान शहरों-कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, शिलांग और इम्फाल में छह मैदानों पर खेले जाएंगे। 1888 में शुरू हुआ डूरंड कप दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी सक्रिय फुटबॉल प्रतियोगिता है।

अभिनव मुकुंद ने 2027 वर्ल्डकप टीम में रोहित-कोहली को चुना, संजू-तिलक बाहर

नई दिल्ली, 23 जुलाई (एजेंसियां)। पूर्व भारतीय ओपनर अभिनव मुकुंद ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए 15 मेंबर्स की भारतीय टीम चुनी है। उन्होंने ESPN क्रिकइन्फो के यूट्यूब चैनल पर अपनी टीम का ऐलान किया। अभिनव ने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भरोसा जताया है। जबकि, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम से बाहर किया है। शुभमन गिल को कप्तान बनाया है।

अभिनव मुकुंद की वर्ल्डकप टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, गुरनूर बराड़।

बांग्लादेशी पेसर इबादत हुसैन ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर

ढाका, 23 जुलाई (एजेंसियां)। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज इबादत हुसैन अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। वे पिता बनने वाले हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत बांग्लादेश 13 अगस्त से डार्विन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा। इससे पहले टीम 3 अगस्त से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी।

बांग्लादेश की चिंता सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं है। तेज गेंदबाज नाहिद राणा की साइड इंजरी का स्कैन कराया गया है। पहले टेस्ट में उनकी उपलब्धता पर फैसला होना बाकी है। टीम को उम्मीद है कि अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास पिंडली की चोट से उबरकर समय पर फिट हो जाएंगे।

बैटिंग कोच मोहम्मद अशरफुल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन जल्दी पहुंचने और अभ्यास मैच खेलने का फायदा मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी खिलाड़ी फिट रहे तो बांग्लादेश अच्छा प्रदर्शन करेगा।

हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे टेस्ट में बल्लेबाजी विफल रहने के बावजूद अशरफुल ने कहा कि पिछले सात महीनों में बल्लेबाजों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत का जिक्र करते हुए कहा कि एक-दो खराब मैचों से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए।

जिदान फ्रांस फुटबॉल टीम के मैनेजर बन सकते हैं

पेरिस, 23 जुलाई (एजेंसियां)। पूर्व फुटबॉलर जिनेदिन जिदान के मंगलवार को आधिकारिक तौर पर फ्रांस के मुख्य कोच नियुक्त किए जाने की उम्मीद है। वह 2012 से टीम की कमान संभाल रहे दिदिएर देशां की जगह लेंगे।

54 वर्षीय जिदान 2030 फीफा वर्ल्ड कप तक चार साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। देशां के लंबे और सफल कार्यकाल के बाद अब फ्रांस टीम नई दिशा में आगे बढ़ेगी।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए स्पेन के मिडफील्डर रोड्री पर रियल मैड्रिड की नजर है। मैनचेस्टर सिटी के साथ उनका अनुबंध अब केवल एक साल का बचा है, जिससे इस गर्मी में उनके ट्रांसफर की अटकलें तेज हो गई हैं।

सीएम ने बीआरएस की चुप्पी पर सवाल उठाया

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया कि हालिया विवादों को लेकर बीआरएस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की। मुख्यमंत्री ने पिछली बीआरएस सरकार के दौरान इंटरमीडिएट के 27 छात्रों की मौत का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि ये मौतें परीक्षा पत्रों के मूल्यांकन में हुई त्रुटियों के कारण हुईं। उन्होंने मांग की कि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ग्लोबरेना मुद्दे के संबंध में अपनी सत्यनिष्ठा साबित करें और छात्रों की मौत के लिए माफी मांगें।

गुरुवार को विधानसभा में मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान बोलते हुए, रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की संभावना है और कहा कि ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं। उन्होंने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) द्वारा लगाए गए उन आरोपों का भी जवाब दिया कि उनके नाम पर दो जगहों पर वोट दर्ज हैं। बीआरएस नेता आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पास दो वोट हैं। उन्हें शिकायत दर्ज करने दीजिए। अगर शिकायत झूठी पाई जाती है, तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। मैंने आधिकारिक तौर पर कलेक्टर को अपना मतदाता पंजीकरण स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। मतदाता सूची में पहले हुए संशोधन का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जीएचएमसी की सीमा के भीतर रहने वाले आंध्र प्रदेश मूल के सभी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर अदालत का रुख किया था, जिसके बाद अदालत ने तत्कालीन जीएचएमसी आयुक्त के प्रति असंतोष व्यक्त किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (हाइड्रा) प्रभावी ढंग से काम कर रही है और उसने कई अतिक्रमित संपत्तियों को वापस हासिल कर लिया है। पूर्व बीआरएस सरकार पर नया हमला बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण में गुणवत्ता मानकों से पूरी तरह समझौता किया गया था। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस नेता टी. हरीश राव को पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कुछ समय के लिए दरकिनार कर दिया था और परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया था। रेवंत रेड्डी ने आगे आरोप लगाया कि तेलंगाना भाजपा नेताओं के बीच आंतरिक कलह उभर रही है। उन्होंने बीआरएस नेताओं पर गरीबों के लिए बने दो शयनकक्षों को बिचौलियों के माध्यम से बेचने का आरोप लगाया और केटी रामाराव को जनवाड़ा फार्महाउस भूमि विवाद की जांच कराने की चुनौती दी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने इंदिरा पार्क स्थित धरना चौक को फिर से खोल दिया था, जबकि पिछली बीआरएस सरकार के दौरान इसे बंद कर दिया गया था। उन्होंने टिप्पणी की, विडंबना यह है कि केटीआर अब उसी धरना चौक पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं जिसे उनकी अपनी सरकार ने बंद कर दिया था।

रेवंत रेड्डी ने विधानसभा के नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण किया

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को ऐतिहासिक तेलंगाना विधानसभा परिसर में चल रहे मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्यों का व्यापक निरीक्षण किया। प्रमुख विधायी नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परिसर का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान, रेवंत रेड्डी ने विभाग के इंजीनियरों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और परिचालन सुविधाओं को उन्नत करते हुए संरचना के ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रमुख नेताओं में विधान सभा अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार, मंत्री अदलुरी लक्ष्मण, सरकारी सचेतक आदी श्रीनिवास, अदांकी दयाकर और बालमुरी वेंकट के साथ-साथ विधायक कव्वमपल्ली सत्यनारायण और जयवीर रेड्डी शामिल थे।

राज्य सरकार आगामी विधायी सत्रों की परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक विधानसभा परिसर में संरचनात्मक जीर्णोद्धार और आधुनिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन को प्राथमिकता दे रही है।

भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू कीं

> केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने हैदराबाद में 47वें सामूहिक गणेश उत्सव की तैयारियों की औपचारिक शुरूआत करते हुए बाहेती भवन, सिद्दिअंबर बाजार में अपने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष जी राघव रेड्डी ने कहा कि कार्यालय हजारों गणेश पंडालों, सरकारी एजेंसियों और नगर निकायों के साथ समन्वय स्थापित करेगा ताकि उत्सव सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उत्सव की शुरूआत 14 सितंबर को प्रतिमा स्थापना के साथ होगी और 25 सितंबर (अनंत चतुर्दशी) को विसर्जन जुलूस के साथ समाप्त होगी। इस वर्ष का उत्सव वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, संत रामदास की 650वीं जयंती और अशोक सिंघल की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाएगा। समिति के सचिव डॉ. रविनुथला शशिधर ने बताया कि जुड़वां शहरों में गणेश उत्सव इस वर्ष भाग्यनगर में अपना 47वां सामूहिक गणेश उत्सव आयोजित करने जा रहा है। इसकी शुरूआत सोमवार, 14 सितंबर को गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ होगी और इसका समापन शुक्रवार, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर विशाल सामूहिक गणेश विसर्जन के साथ होगा।

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया संवाद के बजाय टकराव की : उत्तम कुमार रेड्डी

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में हाल के घटनाक्रमों ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और पूरे भारत के युवाओं की आशाओं और सपनों के बीच बढ़ती खाई को उजागर किया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों और युवा नागरिकों की चिंताओं को दूर करने का एकमात्र तरीका दमन नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सहभागिता है। उत्तम कुमार रेड्डी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ऐसे समय में जब लाखों छात्र सार्वजनिक परीक्षाओं और शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया संवाद के बजाय टकराव की रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से न्याय की मांग करने वाले छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों के साथ लगातार खड़ी रही है। मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के साथ खड़े होने के फैसले की सराहना करते हुए उनके कार्यों को साहसी, दयालु और सिद्धांतवादी नेतृत्व का उदाहरण बताया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, दूर से राजनीतिक तमाशा देखने के बजाय, राहुल गांधी ने उन छात्रों और युवा नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का विकल्प चुना, जिनकी आवाज अनसुनी कर दी जाती है। उनकी चिंताओं को उठाने और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने की उनकी तत्परता उस तरह की राजनीति को दर्शाती है जिसकी आज भारत को जरूरत है सहानुभूति, जवाबदेही और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित राजनीति। उन्होंने पाया कि पूरे देश में, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच, एक नई राजनीतिक संस्कृति की बढ़ती इच्छा है जो प्रचार के बजाय ईमानदारी, धमकी के बजाय संवाद और विभाजनकारी राजनीति के बजाय सार्वजनिक सेवा को महत्व देती है। उन्होंने कहा, दिल्ली में हुए घटनाक्रम महज एक विरोध प्रदर्शन या एक राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर एक व्यापक राष्ट्रीय बहस को दर्शाते हैं। भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं हमेशा से तब मजबूत हुई हैं जब सरकारों ने लोगों को चुप कराने की कोशिश करने के बजाय उनकी बात सुनी है।

उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अधिक से अधिक नागरिक राहुल गांधी को एक प्रमुख लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं जो भारत के लिए एक दयालु, समावेशी और दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करने में सक्षम है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी 2029 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को जीत दिलाएंगे और प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे।

मंत्री ने जर्मनी में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। सड़क, भवन और सिनेमा मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि की मेधावी छात्रा परिमाला को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे जर्मनी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का उनका मार्ग प्रशस्त हुआ है। देवराकोंडा की मूल निवासी और दिहाड़ी मजदूर की बेटी परिमाला ने आईआईटी मद्रास से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मास्टर डिग्री के लिए एक प्रतिष्ठित जर्मन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। आर्थिक तंगी का सामना करते हुए, उनके परिवार ने उनकी विदेश में पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए काफी संघर्ष किया। उनकी स्थिति का पता चलने पर, देवराकोंडा के विधायक बालू नाइक ने परिवार की दुर्दशा को मंत्री वेंकट रेड्डी के ध्यान में लाया।

परिमाला की शैक्षणिक उपलब्धियों से प्रभावित होकर, मंत्री ने तुरंत कोमटिरेड्डी प्रतीक फाउंडेशन के माध्यम से 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी। उन्होंने कहा, गरीबी कभी भी प्रतिभा के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। सही अवसर मिलने पर, वंचित पृष्ठभूमि के छात्र वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं हमेशा योग्य छात्रों के साथ खड़ा रहूंगा और उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करूंगा। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि परिमाला जर्मनी में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगी और तेलंगाना तथा राष्ट्र दोनों का नाम रोशन करेंगी।

अल नीनो प्रभाव को कम करने के लिए कार्य योजना तैयार होगी : मंत्री तुम्मला

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना के कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार इस महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करेगी। तेलंगाना के कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि राज्य सरकार एल नीनो की संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला स्तर से प्राप्त सुझावों और विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर एक व्यापक राज्यव्यापी कार्ययोजना तैयार करेगी। इस कार्ययोजना को अंतिम रूप देकर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को प्रस्तुत किया जाएगा।

गुरुवार को सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सितंबर तक एल नीनो का प्रभाव बढ़ सकता है और दिसंबर तक इसकी स्थिति गंभीर होने की आशंका है। इससे खरीफ और रबी दोनों मौसम की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य के 23 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। हाल में हुई छिटपुट बारिश को देखते हुए किसानों को धान की खेती शुरू नहीं करने की सलाह दी गई है, क्योंकि आगे वर्षा की कमी की संभावना बनी हुई है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती अपनाने के लिए प्रेरित करें, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां भूजल स्तर लगातार घट रहा है और सिंचाई संसाधन सीमित हैं। उन्होंने मंडल स्तर पर उपलब्ध जल की स्थिति की नियमित जानकारी किसानों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। तुम्मला नागेश्वर राव ने बैंकों से फसल ऋण वितरण में तेजी लाने, सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए नाबार्ड से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने तथा वैकल्पिक फसलों के बीजों की शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने को कहा। आवश्यकता पड़ने पर रैतु वेदिका केंद्रों का उपयोग बीज वितरण केंद्रों के रूप में करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित विभागों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने तथा सभी विभागों के समन्वय से मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

केंद्र सरकार ने खेल बजट को बढ़ाकर 4,480 करोड़ रुपये कर दिया : बंडी संजय

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने गुरुवार को गच्चीबावली स्थित जीएमसी बालायोगी इंडोर स्टेडियम में 11वें अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2026 का उद्घाटन किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के साधन के रूप में खेलों को बढ़ावा दे रही है और खेल बजट को बढ़ाकर 4,480 करोड़ रुपये कर दिया है। उन्होंने 2047 तक विश्व के शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में से एक बनने के भारत के लक्ष्य को दोहराया। बंडी संजय ने आगे कहा कि पुलिस खेल राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और अनुशासन को मजबूत करते हैं, साथ ही महिला कर्मियों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता, पोषण सहायता और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं सहित कल्याणकारी उपायों के विस्तार की सराहना की। 23 से 30 जुलाई तक सीआईएसएफ द्वारा आयोजित की जा रही इस चैंपियनशिप में 36 राज्य पुलिस और सीएपीएफ संगठनों के 1,600 से अधिक एथलीट जूडो, वुशु, ताइक्वांडो, कराटे और पेंचक सिलाट में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कार्यक्रम में सीआईएसएफ एडीजी (दक्षिण) पद्माकर एस. रणसिपे, एनआईएसए निदेशक और आईजी हरप्रीत कौर सोही, एसआर सरवनन, एडीजी, और पीआईबी एडीजी, श्रुति पाटिल और अन्य उपस्थित थे।

बीआरएसवी आज इंदिरा पार्क में विरोध प्रदर्शन करेगी

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। भारत राष्ट्र समिति विद्यार्थी संगठन 24 जुलाई शुक्रवार को सुबह 10 बजे हैदराबाद के इंदिरा पार्क स्थित धरना चौक पर एक बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है।

यह प्रदर्शन नई दिल्ली में छात्रों और युवाओं के विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की कार्रवाई और कथित दमन के विरोध में किया जा रहा है। युवा आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता को दोहराने के लिए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (केटीआर) विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।

व्यक्तिगत समर्थन के तौर पर, केटीआर ने अपने 50वें जन्मदिन के सभी पारंपरिक समारोहों में शामिल न होने का फैसला किया है और इसके बजाय छात्र कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने का विकल्प चुना है। केटीआर ने असहमति व्यक्त करने और शांतिपूर्ण सभा करने के संवैधानिक अधिकार पर जोर देते हुए कहा, भारत के युवाओं की आवाज को बलपूर्वक कुचला नहीं जा सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ जवाबदेही की मांग करने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए छात्रों, युवा संगठनों और बीआरएसवी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सभा के भाग लेने की उम्मीद है। इस बीच, गेलू श्रीनिवास यादव, मुथा जयसिम्हा और अन्य सहित बीआरएस नेताओं ने मुलाकात की। गांधी नगर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) से विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी।

काजीपेट-बल्हारशाह तिहरी रेललाइन परियोजना पूरी

> उत्तर-दक्षिण रेल संपर्क को मिलेगी नई गति

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। दक्षिण मध्य रेलवे ने देश के सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों में शामिल काजीपेट-बल्हारशाह रेलखंड पर तिहरी रेललाइन तथा विद्युतीकरण परियोजना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। 22 जुलाई को आसिफाबाद-सिरपुर कागजनगर के बीच 11 किलोमीटर लंबे अंतिम खंड तथा बिबरा नदी पर महत्वपूर्ण रेल पुल का निर्माण एवं विद्युतीकरण पूरा होने के साथ ही यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्ण हो गई। करीब 203 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत आई है। इसके पूरा होने से देश के उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले प्रमुख रेल गलियारे पर यात्री और मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुगम एवं तेज़ होगा। दक्षिण मध्य रेलवे के अनुसार, काज़ीपेट-बल्हारशाह रेलखंड उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी है। इसी मार्ग से कोयला और सीमेंट उद्योगों से जुड़े अनेक साइडिंग भी जुड़े हुए हैं। लगातार बढ़ते यात्री और माल परिवहन के कारण यह रेलखंड अत्यधिक व्यस्त हो गया था। इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2016 में राघवपुरम-मंदामर्री के बीच 33 किलोमीटर लंबी तिहरी रेललाइन का कार्य पूरा किया गया था। इसके बाद वर्ष 2015-16 में काज़ीपेट-बल्हारशाह के शेष 203 किलोमीटर रेलखंड (तेलंगाना में 159 किलोमीटर तथा महाराष्ट्र में 44 किलोमीटर) पर तिहरी रेललाइन और विद्युतीकरण कार्य को स्वीकृति दी गई। अब बल्हारशाह स्टेशन के समीप मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक छोटे हिस्से को छोड़कर पूरी परियोजना का निर्माण और परिचालन शुरू कर दिया गया है। बल्हारशाह यार्ड को नई तीसरी रेललाइन से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2020 से विभिन्न चरणों में इस परियोजना के अलग-अलग हिस्सों को पूरा किया गया और अब संपूर्ण परियोजना पूर्ण हो चुकी है। परियोजना से तेलंगाना और महाराष्ट्र में रेल अवसंरचना को महत्वपूर्ण मजबूती मिलेगी। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच यात्री तथा मालगाड़ियों का निर्बाध संचालन संभव होगा। इसी क्रम में तीसरी रेललाइन से रेल यातायात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कोयला, सीमेंट तथा अन्य औद्योगिक माल की ढुलाई अधिक तेज़ और सुगम होगी। ताप विद्युत संयंत्रों और उद्योगों तक कच्चे माल की आपूर्ति बेहतर होगी। यात्री रेल सेवाओं के विस्तार और समयपालन में सुधार होगा। विद्युतीकरण से ऊर्जा की बचत, ईंधन व्यय में कमी तथा कार्बन उत्सर्जन घटेगा। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव ने निर्माण, अभियांत्रिकी, सिग्नल एवं दूरसंचार, विद्युत, परिचालन तथा अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को परियोजना के सफल समापन पर बधाई दी।

बिहार के प्रवासी मज़दूर ने आत्महत्या की

संगारेड्डी, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। मंगलवार को पा टनचेरु पुलिस स्टेशन इलाके के इस्नापुर में एक व्यक्ति ने कोर्ट केस में सज़ा के डर से आत्महत्या कर ली। मृतक अंकित कुमार (22), जो बिहार का प्रवासी मज़दूर था, इंद्राकरण पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के एक मामले में आरोपी था। इस मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होनी थी। हालाँकि, वह कोर्ट में पेश नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि उसे डर था कि सुनवाई में शामिल न होने के कारण उसे सज़ा हो सकती है। इन्हीं हालात के बीच, कुमार ने इस्नापुर में अपने किराए के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है।

केटीआर ने झूठे आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत को कानूनी नोटिस भेजा

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा उन पर लगाए गए झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोपों की कड़ी निंदा की है, जिनमें उन्हें ग्लोब एरेना टेक्नोलॉजीज से जोड़ा गया है। गुरुवार को यहां एक बयान में, केटी रामाराव ने खुलासा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पहले ही एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे ग्लोब एरेना को उनकी बेनामी कंपनी बताकर झूठा दावा करने और कई अन्य निराधार आरोप लगाने के लिए 48 घंटों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की गई है। बीआरएस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मीडिया के सामने बिना किसी सबूत के कई गैरजिम्मेदाराना बयान देने के बाद कानूनी नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने दावा किया कि ग्लोब एरेना टेक्नोलॉजीज के साथ उनका कोई स्वामित्व, वित्तीय संबंध, मालिकाना हक या किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और उन्होंने मुख्यमंत्री को विश्वसनीय सबूतों के साथ अपने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी। केटीआर ने कहा, मुख्यमंत्री को 48 घंटों के भीतर अपने आरोपों को साबित करने के लिए कहा गया है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। अन्यथा, उन्हें उचित दीवानी और आपराधिक कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, जिसमें मेरी प्रतिष्ठा को हुए अपूरणीय नुकसान के लिए मानहानि का मुकदमा भी शामिल है। आरोपों का खंडन करते हुए, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि ग्लोब एरेना उनकी बेनामी कंपनी है, उन्होंने कंपनी के लिए सीबीएसई परीक्षा अनुबंध दिलवाए थे, या कंपनी में उनका कोई वित्तीय हित था, ये सभी दावे पूरी तरह से झूठे, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन मुख्यमंत्री के लिए बिना किसी तथ्यात्मक आधार के ऐसे गंभीर आरोप लगाना अत्यंत गैरजिम्मेदाराना है। मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए केटीआर ने पूछा, अगर ग्लोब एरेना वाकई मेरी बेनामी कंपनी है, तो कांग्रेस सरकार ने खुद उस कंपनी के साथ समझौते क्यों किए? आपकी अपनी सरकार ने उस फर्म के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, और आज आप दावा कर रहे हैं कि यह मेरी बेनामी कंपनी है। क्या मुख्यमंत्री को ऐसे आरोप लगाने से पहले कोई जिम्मेदारी का एहसास है? केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर राष्ट्रीय परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से संबंधित वास्तविक मुद्दे से जनता का ध्यान जानबूझकर भटकाने का आरोप भी लगाया।

वेरिफिकेशन ड्राइव के बाद एएसडी वोटर्स की संख्या घटकर 2.60 लाख हुई

हैदराबाद, 23 जुलाई (स्वतंत्र वार्ता)। वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न-2026' पर आई ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट में हैदराबाद में 2.60 लाख वोटर्स को एएसडी (अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए या मृत) के तौर पर पहचाना गया है।

15 जुलाई को, ज़िला चुनाव अधिकारी आर.वी. कर्णन ने कहा था कि 11.50 लाख AŞ वोटर्स की पहचान की गई थी। 21 जुलाई तक, एएसडी वोटर्स की संख्या घटकर 2.60 लाख हो गई। याकूतपुरा विधानसभा क्षेत्र 37,197 एएसडी वोटर्स के साथ सबसे ऊपर रहा, जबकि अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम, यानी 6,427 एएसडी वोटर्स दर्ज किए गए।

इस बीच, हैदराबाद ज़िले में एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक एन्यूमरेशन फ़ॉर्म के डिजिटाइज़ेशन का 42.96% काम पूरा हो चुका है। कुल 47,36,669 वोटर्स में से, बीएलओ ने सभी 15 विधानसभा क्षेत्रों में 20,34,849 वोटर्स से एन्यूमरेशन फ़ॉर्म इकट्ठा किए। डिजिटाइज़ेशन में चंद्रयानगुट्टा विधानसभा क्षेत्र 49.36% के साथ सबसे आगे रहा।

Printed and published by Dr. Gireesh Sanghi on behalf of AGA Publications Ltd., at 396, Lower Tankbund, Hyderabad-500080 Editor: *Dhirendra Pratap Singh *responsible for selection of news under the PRB Act. Postal Licence H/SD/380/21-22, Phone:27644999. Fax:27642512, RNI No.69340/98, Regd.:No.AP/HIN/00196/01/1/97/TC.